विशेषांक

इंडिया टुडे

25 जनवरी, 2023 50 रुपए

भारत@2023: आगे की राह

राजनीति | यूक्रेन | जलवायु परिवर्तन | मनोरंजन

करीब 15 परिणाम (0.49 सेकंड में)

MAGAZINE KING

जहांगीर अजीज, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में :
ऊंची वृद्धि दर हासिल करना आसान न होगा पेज. **22**
वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वृद्धि धीमी रहेगी, जिसकी वजह से बार-बार इस ...

शिवशंकर मेनन, विदेश नीति के बारे में :
तीन चुनौतियां और अवसर एक पेज. **26**
परिवर्तनकाल से गुजर रही दुनिया में भारत के पास मौका है कि वह पिछले साल ...

रोहन मूर्ति, टेक्नोलॉजी के बारे में :
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अनदेखी न करें पेज. **38**
क्रिप्टोकरेंसियों की चमक 2022 में भले ही फीकी पड़ गई हो लेकिन उन्हें चलाने ...

सौम्या स्वामीनाथन, कोविड के बाद की स्थिति के बारे में :
तीन साल की महामारी ने पढ़ाया हमें जो पाठ पेज. **50**
दुनिया भर की वैज्ञानिक और जन स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी बिरादरी को सेहत का ...

देखें और परिणाम

RNI NO. 45823/86 REGISTRATION NO. DL(DS)-02/MP/2022-23-24, DL(ND)-11/6042/2021-22-2023; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2021-23; FARIDABAD/46/2023-25 www.indiatodayhindi.in

अंक सप्ताह के लिए प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित; एलपीसी दिल्ली-आरएमएस-दिल्ली-110006 से प्रत्येक शनिवार और सोमवार को प्रेषित; कुल पन्नों की संख्या 60 (आवरण सहित) वर्ष 37; अंक: 08

VISIT…

प्रधान संपादक की कलम से

समय कभी नहीं रुकता, नदी की तरह बहता रहता है. हमारे कैलेंडर इस पर बांध बना देते हैं ताकि आकलन कर सकें कि क्या हुआ और भविष्य में क्या हो सकता है. आगे देखने पर पहले से तय कुछ निश्चित घटनाएं दिखती हैं—जैसे चुनाव. 2023 के आने वाले महीनों में एक के बाद एक अहम विधानसभा चुनाव होने हैं—फरवरी में त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड; गर्मियों में कर्नाटक; सर्दियों की शुरुआत में मध्य प्रदेश-राजस्थान-छत्तीसगढ़ की महातिकड़ी; फिर तेलंगाना के साथ समापन. हम अनुभव से जानते हैं कि अगले साल के आम चुनाव के लिए इनकी अहमियत शायद सीमित हो. फिर भी, ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चेंगप्पा अपने आलेख में कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को मिले राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के साथ विपक्ष का आकाश अब स्थाई नहीं रहा. दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत अब भी पुश्त भर ऊंची दिखती है, पर ''उनका दबदबा कुछ हद तक अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर निर्भर करता है''.

इसके बीज बहुत पहले ही बो दिए गए. भारत ने महामारी को पश्चिम के मुकाबले बेहतर ढंग से संभाला, पर उसकी आर्थिक बहाली प्रतिकूल झंझावातों से जूझ रही है. जे.पी. मॉर्गन से जुड़े अर्थशास्त्री जहांगीर अजीज लिखते हैं, ''आर्थिक बहाली की रफ्तार प्रभावशाली तो है, मगर 7 फीसद से नीचे बनी हुई है जिसकी ओर महामारी से पहले के वृद्धि के रुझानों ने इशारा किया था. यह महामारी से हुए आर्थिक नुक्सान को भरने में नाकाफी है. सरकार और आरबीआइ इस साल औसतन 6.5-7 फीसद की वृद्धि होती देख रहे हैं.'' खुद वे दुनिया को 3 फीसद वृद्धि की तरफ बढ़ते और ''अगले साल 1.7 फीसद'' तक आधा घटते देख रहे हैं. वृद्धि को टेका लगाना और मुद्रास्फीति को नीचे लाना विपरीत दिशाओं में एक साथ दौड़ने जैसा है. देखना है कि बजट 2023 में समझदारी से संसाधन आवंटित करके इस दौर से कैसे पार पाया जाता है.

21 जनवरी, 2022

एक और ऐतिहासिक घटना यह होगी कि भारत 2023 में दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा. बाकी सदी वह इसी स्थिति में रहेगा और चीन पर हमारी जबरदस्त बढ़त होगी. जनसंख्या विशेषज्ञ चिन्मय तुम्बे लिखते हैं, ''अगर भारत की प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी-खासी बढ़ती है, तो वह 2050 तक चीन के मुकाबले ज्यादा बड़ा बाजार और अर्थव्यवस्था बन सकता है.'' वे यह भी कहते हैं, ''इससे जबरदस्त भू-राजनैतिक अहमियत हासिल होगी... भारत को महाशक्ति के रूप में अंततः अमेरिका और चीन के साथ जोड़कर देखा जाने लगेगा.'' फिर जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, जिसमें दुनिया धरती के पर्यावरण को बचाने के लिए दशकों से जूझ रही है और बहुत कामयाब नहीं है. पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन लिखते हैं, ''भारत की 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की दीर्घकालिक रणनीति निराशाजनक है.'' वे ''पूरी तरह नई परिवहन रणनीति'' की मांग करते हैं, जिसमें ''छह लेन के राजमार्गों और फ्लाइओवरों के निर्माण'' पर भारी-भरकम खर्च के बदले उस रकम को पर्याप्त रेल और नदी परिवहन के विकास पर खर्च किया जाए. वे यह भी बताते हैं कि देश 1960 के दशक की पुरातन हरित क्रांति और सघन फसलें उगाने के खब्त पर पुनर्विचार करे.

पिछले साल ज्यादातर दुनिया को कोविड-19 से उबरते देखा गया, पर यह फिक्र अब भी बनी हुई है कि कहीं नया वैरिएंट फिर न आ धमके. इस अंक में लिख रहे दोनों स्वास्थ्य विशेषज्ञ, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के के. श्रीनाथ रेड्डी और डब्ल्यूएचओ की पूर्व चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन जरूरी सतर्कता के साथ दूसरे ढंग से सोचते हैं. रेड्डी लिखते हैं कि कोविड अब ''भारी बर्बादी करके विदा हो जाने वाले हमलावर के बजाए यहां रहने आए नए किरायेदार की तरह'' है. उनकी सिफारिश है कि हम अपनी ऊर्जा अब दवा-प्रतिरोधी टीबी और मलेरिया जैसी उन जानलेवा बीमारियों पर केंद्रित करें जिनकी हमने अनदेखी की है. जीवनशैली से जुड़ी गैर-संक्रामक बीमारियों को ''समय पूर्व मृत्य की बड़ी वजह'' बताते हुए स्वामीनाथन स्वास्थ्य के ''व्यावसायिक पहलुओं'' पर नीतिगत कार्रवाई की मांग करती हैं. इसके लिए वे ''ट्रांस फैट पर पाबंदी, तंबाकू विनियमन, पीडीएस के जरिए सुलभ करवाकर मोटे अनाजों की खपत को बढ़ावा और स्कूलों में बहुत ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी वाले खाद्य व पेय पदार्थों को नियम-कायदों के दायरे में लाना'' जरूरी बताती हैं.

मगर इस बीमारी के लक्षण आर्थिक और भू-राजनैतिक भी हैं. खासकर चीन में मानो 2020 का साल लौट आया है क्योंकि कोविड उसे फिर सता रहा है, जिसके नतीजे घरेलू राजनीति और उससे इतर भी दिखते हैं. क्या वह अपनी वुल्फ वारियर यानी आक्रामक कूटनीति पर टिका रहेगा? क्या वह ताइवान और हमारे अस्थाई सीमांतों पर युद्ध को दावत देगा? क्या बाइडन का अमेरिका चीन और रूस के सवालों पर उतने ही लड़ाकूपन से जवाब देगा?

ये जटिल और जरूरी सवाल हैं. प्रतिष्ठित विशेषज्ञों का समूह भारत की चुनौतियों और अवसरों को तौल रहा है. कार्नेगी एंडाउमेंट के एश्ले जे. टेलिस यूक्रेन पर तटस्थता के बावजूद भारत के लिए चिंता की तीन वजहें गिनाते हैं: ''प्रतिबंधों के कारण रूसी सैन्य कलपुर्जे मिलने में रुकावट; चीन पर रूस की बढ़ती रणनीतिक निर्भरता; और महाशक्ति के रूप में रूस का लगातार दुर्बल होना, जो भारत की बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था की ख्वाहिश को कमजोर करता है.'' एशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनयूएस, के प्रतिष्ठित फेलो किशोर महबूबानी इस निरंतर बदलाव में भारत के लिए ''सुखद भू-राजनैतिक जगह'' पाते हैं, जहां वह ''दुनिया की एकमात्र सच्ची स्वतंत्र ताकत'' के रूप में अपनी संभावनाओं को साकार कर सकता है. लेकिन तभी जब वह अपने डिब्बे को अमेरिका की रेलगाड़ी के साथ जोड़ने के प्रलोभन पर काबू पाए—क्योंकि ''विश्व इतिहास पर पश्चिम के प्रभुत्व के पिछले 200 पथभ्रष्ट साल अंततः खत्म हो रहे हैं''. पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन कहते हैं कि भारत अपने मौके झपट सकता है बशर्ते वह एलएसी पर शांति के लिए चीन से रिश्ते फिर से तय करे; आरसीईपी और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के साथ एशियाई बहुपक्षीय व्यापार की मुख्यधारा से जुड़े; और अपनी घरेलू राजनीति में कुछ हद तक सुसंगति लाए. यह सवाल हवा में झूल रहा है कि यूक्रेन में युद्ध कब खत्म होगा. स्ट्रैटजिक फोरसाइट ग्रुप के प्रेसिडेंट संदीप वास्लेकर लिखते हैं, ''युद्ध महज भूगोल, अर्थव्यवस्था या नियति के कारण नहीं होता. युद्ध नेताओं के चुने गए विकल्पों से निकलता है. अगर युद्ध विकल्प का मामला है, तो शांति भी क्यों नहीं हो सकती.''

हमारी जिंदगी पूरी तरह इन बड़ी घटनाओं की ही बंधक नहीं है. सोरोको के संस्थापक रोहन मूर्ति और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ प्रशांतो के. रॉय डिजिटल भविष्य में गौर से झांकते हुए अच्छे और बुरे बदलावों की भविष्यवाणी कर रहे हैं. क्रिप्टोकरेंसी के गर्त में जाने के बावजूद मूर्ति को लगता है कि इसका अंदरूनी ढांचा—ब्लॉकचेन—''यथास्थिति'' को बदल देगा. ह्युंडई मोटर्स इंडिया के पूर्व प्रेसिडेंट बी.वी.आर. सुब्बु कहते हैं, ''क्या 2023 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की कामयाबी का साल होगा? बेशक.'' प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर बता रहे हैं कि एआर/वीआर मल्टीवर्स से लेकर ओटीटी, सोशल मीडिया, सिनेमाघरों और टेलीविजन के साथ भारत मनोरंजन का समृद्ध मैदान होगा. 15 लेखकों की ऐसी ही कई सूझ-बूझ से भरी बातों ने इस अंक को जीवंत बना दिया है.

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

इंडिया टुडे

www.indiatodayhindi.in

चेयरमैन और प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सन: कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर: राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: मनोज शर्मा
एडिटर: सौरभ द्विवेदी
डिप्टी एडिटर: मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटर: शिवकेश मिश्र, आशीष मिश्र (लखनऊ)
सीनियर असिस्टेंट एडिटर: पवन वर्मा
असिस्टेंट एडिटर: मनीष दीक्षित, प्रदीपिका सारस्वत
वरिष्ठ विशेष संवाददाता: हिमांशु शेखर
विशेष संवाददाता: विनय सुल्तान
राज्य ब्यूरो: पुण्यमित्र (पटना), आनंद चौधरी (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर: नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर: चंद्रमोहन ज्योति
असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर: असित सॉय
ग्रुप फोटो एडिटर: वंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंट: राजवंत रावत, चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चर: प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चर: सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफ: अभिनव पुगला
एसोसिएट पब्लिशर (इंपैक्ट): विद्या मेनन, सुपर्णा कुमार
इंपैक्ट टीम
सीनियर जनरल मैनेजर: मयूर रस्तोगी (बॉर्ब), जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजर: सैयद नवीद (चेन्नै)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर: विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजर: दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजर: विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजर: राजीव गांधी (बॉर्ब)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: योगेश गोधनलाल गौतम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजर: पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

वर्ष: 37; अंक: 09; 19-25, जनवरी 2023; इसके सप्ताह में प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोन: 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवा:** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोन: दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्स: (0120) 4078080. ई-मेल: wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालय:** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोन: 022-66063355 फैक्स: 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** ए1-ए2, एनके सेंटर, विद्युज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोन: 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरु-560 025 फोन: 2212448, 226233, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN. फैक्स: 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालय: एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.
- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित. संपादक: राज चेंगप्पा**

सुर्खियां

जोशीमठ: खतरे की जद में हैं और कई मठ
पेज 5

धर्म: जैन समाज गुस्से में क्यों
पेज 7

सवाल+जवाब/जावेद अख्तर: क्या दिन थे और क्या दिन आ गए!
पेज 58

भीतर

इलस्ट्रेशन: नीलांजन दास

22 अर्थव्यवस्था
जहांगीर अजीज

24 यूक्रेन की जंग
संदीप वासलेकर

26 विदेश नीति
शिवशंकर मेनन

28 सुरक्षा
जयदेव रानाडे

30 भू-राजनीति
किशोर महबूबानी

32 अमेरिका फैक्टर
एशले जे. टेलिस

34 राजनीति
राज चेंगप्पा

38 टेक्नोलॉजी
रोहन मूर्ति

40 साइबर जगत
प्रशांतो के. रॉय

42 मनोरंजन
सिद्धार्थ रॉय कपूर

44 समाज
चिन्मय तुम्बे

46 जलवायु परिवर्तन
श्याम सरन

48 परिवहन
बी.वी.आर. सुब्बू

50 कोविड के बाद की स्थिति
सौम्या स्वामीनाथन

52 स्वास्थ्य
के. श्रीनाथ रेड्डी

उत्तर प्रदेश इंवेस्टमेंट समिट

12 निवेश कैसे बने जमीनी हकीकत ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले योगी सरकार ने हासिल किए 12 लाख करोड़ रु. के निवेश प्रस्ताव

खास रपट

54 कहां है हमारा रैनावारी? निर्वासित पीढ़ियों की अपना कश्मीर न खोने की जद्दोजहद

आवरण: नीलांजन दास

पाठकों के लिए सूचना: कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में 'इम्पैक्ट फीचर' या 'एडवरटोरियल' या 'फोकस' के पन्ने नजर आते होंगे. ये विज्ञापन हैं और इन्हें बनाने में पत्रिका का संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होता.

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

धर्म: जैन समाज
गुस्से में क्यों
पेज 7

सुर्खियां

छत्तीसगढ़: आपस में
ही भिड़े आदिवासी
पेज 8

फटाफट लगिए
उत्तराखंड के सीएम धामी 7 जनवरी को जोशीमठ का दौरा करते हुए

एएनआइ

जोशीमठ

खतरे की जद में हैं और कई मठ

एस.एम.ए. काज़मी

अपने ही वजन तले धंसता जोशीमठ किसी नक्शे पर दिखता 'एक और' बिंदु भर नहीं है. उत्तराखंड के चमोली जिले में 6,000 फुट की ऊंचाई पर बसा सुंदर-सा पहाड़ी शहर यह पवित्र बद्रीनाथ मंदिर, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, अनमोल विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी, स्नो स्पोर्ट्स रिजॉर्ट औली और आसपास के पहाड़ों में काफी ऊंचाई वाले ट्रेकिंग मार्गों का प्रवेश द्वार है. इस मध्य हिमालयी क्षेत्र में भारत-चीन सीमा की रक्षा करने वाली भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) के ब्रिगेड मुख्यालय होने के कारण इसका सामरिक महत्व भी है.

वैसे जोशीमठ में कुछ भी अचानक नहीं हुआ है. गढ़वाल की पहाड़ियों में बड़ी संख्या में कस्बे और गांव लगातार भूस्खलन और कृषि भूमि के साथ-साथ आवासीय भवनों के धंसाव का सामना करते रहे हैं. क्यों? मानव जाति की मूर्खता उजागर करने वाले इस सवाल को यहीं छोड़ दें. जोशीमठ में उभरते संकट पर 2021 में दो सहयोगी भूवैज्ञानिकों के साथ एक अध्ययन करने वाले, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में कार्यरत भूविज्ञानी डॉ. एस.पी. सती बताते हैं, "हिमालय दुनिया की सबसे नई पर्वत शृंखला है. इसके निर्माण की प्रक्रिया अभी भी जारी है. और भूगर्भीय रूप से उत्तराखंड अत्यधिक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है. ढेरों पनबिजली परियोजनाओं, बारहमासी चार धाम राजमार्ग जैसी बेलगाम निर्माण गतिविधियों और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए सुरंग बनाने में विस्फोटकों

के बड़े पैमाने पर उपयोग ने क्षेत्र की पहले से ही नाजुक हालत को और बिगाड़ दिया है.''
पिछले दो साल से इलाके के बाशिंदे जमीन धंसने और मकानों में दरारें आने की बढ़ती घटनाओं की जानकारी प्रशासन को दे रहे थे. करीब 14 महीने पहले 'जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति' बनाई गई. आवाजें उठने पर राज्य सरकार ने भूगर्भीय और भू-तकनीकी जांच के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया, लेकिन उसकी चेतावनी भी अनसुनी रह गई.

दिसंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में यह बुरा सपना सच हो गया. घरों, होटलों और यहां तक कि सड़कों में बड़ी दरारें आ गईं. कुछ दरारों से पानी रिसना शुरू हो गया. हिमालय का यह शहर जैसे *टाइटैनिक* में बदल गया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने गया स्थानीय निवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल मायूस लौट आया. एक मिनट से भी कम समय में मुलाकात खत्म हो गई. लेकिन जोशीमठ की नाजुक हालत की जानकारी हर बीतते घंटे के

तबाही के खतरे का सामना सिर्फ जोशीमठ ही कर रहा हो, ऐसा नहीं है. नैनीताल, मसूरी और दूसरे कई हिल स्टेशन भी इसी तरह दरकने और धंसने के अंदेशों के बीच जी रहे हैं. हालात से निबटने को विशेषज्ञों के सुझाए उपायों पर कान न दिए जाने का यही है नतीजा

साथ सार्वजनिक होती गई और जल्द ही राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच गई. फिर तो 7 जनवरी को धामी भागे-भागे आए और प्रभावित परिवारों के बचाव तथा पुनर्वास का उपक्रम शुरू करने का आदेश दिया. 20,000 से थोड़ी अधिक आबादी वाले इस कस्बे में 678 घरों को असुरक्षित घोषित किया जा चुका है. एक चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत रुड़की के केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआइ) के वैज्ञानिकों की देखरेख में 75 सर्वाधिक संवेदनशील भवनों को गिराने का काम शुरू हो गया है.

हर रंग के राजनेता अब जोशीमठ की दौड़ लगा रहे हैं. पर जिस बात से यहां के निवासी क्षुब्ध हैं, वह है इन नेताओं की लागू की हुई अतिमहत्वाकांक्षी 'विकास' नीति. लोग खास तौर पर शहर के नजदीक चल रही दो मेगा परियोजनाओं को बंद करने की मांग कर रहे हैं: 520 मेगावाट तपोवन-विष्णुगढ़ पनबिजली परियोजना के लिए पहाड़ियों में विस्फोट करके बनाई जा रही एक सुरंग; और बद्रीनाथ तक जाने वाले चार धाम राजमार्ग के हिस्से के रूप में बन रहा दो-लेन का हेलंग-मारवाड़ी बाइपास. समिति के संयोजक अतुल सती कहते हैं, ''इन परियोजनाओं के अवैज्ञानिक नजरिए ने हमें इस हाल में पहुंचाया है. इस पर फौरन कार्रवाई और दीर्घकालिक योजना की जरूरत है.''

चेतावनी तो वैसे इतिहास ने भी कम नहीं दी थी. 1970 की विनाशकारी बाढ़ के बाद 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गढ़वाल के तत्कालीन आयुक्त एम.सी. मिश्र के नेतृत्व में 18 सदस्यीय समिति गठित की थी. वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जोशीमठ एक भूस्खलन के बैठ गए मलबे पर बसा है और यहां भूगर्भीय चट्टानी सतह बहुत गहराई में स्थित है जिसके कारण यहां भूस्खलन का खतरा है. भूकंपीय खतरा तो यहां है ही क्योंकि यहां की भूगर्भीय चट्टानें मुख्य केंद्रीय दबाव क्षेत्र (मेन सेंट्रल थ्रस्ट) का हिस्सा हैं. यही वह बिंदु है जहां भारतीय भूभार यूरेशियन प्लेट पर दबाव डालता रहता है. समिति की सिफारिश थी कि पहाड़ी ढलानों के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए, पेड़ न काटे जाएं और इस कस्बे के लिए एक उचित जल निकास प्रणाली बनाई जाए. तीनों सिफारिशें कहां गईं, पता ही न चला.

वर्षों से इस क्षेत्र में बढ़ते पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की जरूरतें पूरी करने को बेलगाम निर्माण होता रहा है. अकेले 2022 में 15 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ के दर्शन किए. पिछले साल उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए), सीबीआरआइ रुड़की, आइआइटी रुड़की, वाडिया संस्थान (देहरादून) और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के विशेषज्ञों को लेकर बने विशेषज्ञ दल ने भी दोहराया था कि यह छोटा शहर अस्थिर आधार पर बसा है और भारी बारिश, भूकंप के झटकों, अनियमित निर्माण या शहर की वहन क्षमता से ज्यादा लोगों की भीड़ होने पर ढह सकता है. इस दल ने जोशीमठ-औली मार्ग पर उग आई इमारतों को यहां के भूधंसाव के लिए जिम्मेदार ठहराया है. खराब जल निकासी और नदी किनारे कटाव के कारण यह समस्या और गंभीर हुई है.

वैज्ञानिकों की एक केंद्रीय टीम अब सर्वे के लिए जोशीमठ में है. निर्माण गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है और प्रभावित स्थानीय निवासियों को सुरक्षित भवनों में भेजा जा रहा है. कड़कड़ाती ठंड में 4,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ कर अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है. अस्थायी राहत के रूप में राज्य सरकार ने पीड़ितों को 4,000 रुपए महीने के अनुदान के अलावा भोजन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री को सलाह के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की टीम देहरादून पहुंची है. एनडीआरएफ की चार कंपनियां जोशीमठ पहुंच चुकी हैं.

हालांकि, आपदा प्रबंधन की इस फौरी आपाधापी से बड़े संकट का समाधान न होगा. संभावित विनाश का सामना केवल जोशीमठ ही नहीं कर रहा. मसूरी और नैनीताल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटन स्थलों के कई क्षेत्रों में भू-धंसाव हो रहा है. कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग के कई गांवों और एक दशक पहले वरुणावत पर्वत से भूस्खलन का शिकार हो चुके उत्तरकाशी जिले के कई हिस्सों में भी ऐसी ही स्थितियां हैं. पारिस्थितिकीय और भूगर्भीय रूप से बेहद नाजुक इन क्षेत्रों में बेलगाम अनियोजित विकास ही असल दोषी है. धामी ने अब सभी पहाड़ी कस्बों की भारवहन क्षमता का आकलन करने के लिए उनके तकनीकी सर्वेक्षण का आदेश दिया है. इन स्थानों पर निर्धारित सीमा पार होने पर निर्माणों पर रोक लगेगी.

भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने और अचानक बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का लगातार सामना करने वाले इस क्षेत्र ने 2013 में भयानक केदारनाथ जलप्रलय देखा जिसमें 5,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की जान गई थी और पूरे राज्य में बुनियादी ढांचा भारी विनाश का शिकार हुआ था. 2021 में आई प्राकृतिक आपदाओं में भी 300 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई. पिथौरागढ़ जिले के धारचूला कस्बे के पास ऐलधारा पहाड़ियों से भारी भूस्खलन हुआ. भारत और नेपाल के बीच की सीमा बनाने वाली काली नदी पर मॉनसून से पहले सुरक्षा दीवार का निर्माण न होने पर वहां के निवासियों को अचानक आने वाली बाढ़ के डर में जीना पड़ता है. राज्य ने 2021 तक आपदाओं की चपेट में आने वाले 465 गांवों की पहचान की थी जिन्हें पुनर्वासित करने की जरूरत थी. अब तक 44 गांवों में 1,100 परिवारों का ही पुनर्वासन हुआ है. ■

धर्म

जैन समाज गुस्से में क्यों

पवित्र पर्वत
झारखंड में पारसनाथ पर्वत पर सम्मेद शिखरजी तीर्थस्थल

सोमनाथ सेन

जुमाना शाह

आमतौर पर शांत रहने वाले जैन समुदाय ने 2022 के आखिरी कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई शहरों में विरोध-प्रदर्शन किया. उनके गुस्से की दो फौरी वजहें थीं—एक तो ये कि उन्हें लगता है, केंद्र सरकार झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पर्वत पर उनके पवित्र तीर्थस्थल सम्मेद शिखरजी की धार्मिक पवित्रता की रक्षा करने की उनकी मांग पर टाल-मटोल कर रही है; दूसरी यह कि नवंबर 2022 में गुजरात के भावनगर जिले के पालीताना में शत्रुंजय पहाड़ियों पर स्थित भगवान आदिनाथ की चरण पादुका के अपमान पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. मध्य दिसंबर में कुछ अराजक तत्वों ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया.

विरोध तेज होने पर केंद्र और गुजरात की भाजपा सरकार ने इस समृद्ध और रसूखदार अल्पसंख्यक समुदाय को आश्वस्त करने के कदम उठाए. पालीताना मामले में गुजरात सरकार ने वहां एक स्थायी पुलिस चौकी बनाने के साथ ही 'जैन तीर्थस्थल' से संबंधित दूसरे मामलों पर नजर रखने के लिए आठ-सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया. वहीं, सम्मेद शिखरजी के बारे में केंद्र ने पारसनाथ पहाड़ियों के साथ ही करीब 49.3 वर्ग किमी के वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में सभी पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगाने का मेमोरंडम जारी कर दिया. लेकिन जैन समुदाय इससे संतुष्ट नहीं है और उसका विरोध प्रदर्शन जारी है. इन मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे दो जैन संतों की अब तक जान जा चुकी है.

अपने पवित्र स्थलों को कथित रूप से अपमानित किए जाने को लेकर सरकार की 'निष्क्रियता' पर जैन समुदाय आक्रोशित है

आबादी में कम होने के बावजूद यह समुदाय वोट बैंक के रूप में अहम माना जाता है. इसलिए भी कि यह सत्तारूढ़ भाजपा के समर्थकों में माना जाता है. गुजरात में यह राज्य की कुल आबादी का केवल 0.5 फीसद है लेकिन 15वीं विधानसभा में उनके चार विधायक हैं. पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी जैन थे.

पालीताना मामले में जैन समुदाय का दावा है कि वह क्षेत्र में सक्रिय खनन माफिया का शिकार हुआ है. गुजरात में जैन समुदाय की धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करने वाले सेठ आनंदजी कल्याणजी ट्रस्ट के सदस्य प्रणव शाह कहते हैं, "865 जैन मंदिरों वाली शत्रुंजय पहाड़ियों में तीर्थ धाम गिरिराज के चारों ओर बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा है. पिछले पांच वर्षों में हमने मुख्यमंत्रियों (रूपाणी और भूपेंद्र पटेल) से मुलाकात की पर कोई फायदा

नहीं हुआ.'' ट्रस्ट शत्रुंजय पहाड़ियों में 8,600 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर ऐतिहासिक स्वामित्व का दावा करता है. ट्रस्ट का कहना है कि इन पहाड़ियों की कानूनी स्थिति में अंग्रेजों ने 1877 में 'बदलाव' किया था. ट्रस्ट के इस दावे के संबंध में एक मामला गुजरात हाइ कोर्ट में चल रहा है. वहीं, इन पहाड़ियों पर स्थानीय भरवाड़ और अहीर समुदायों का भी दावा है. यह दावा खास तौर पर पहाड़ी पर स्थित एक शिव मंदिर में महाशिवरात्रि मनाने और वहां रातभर रहने के अधिकारों को लेकर है, जो जैन पूजा पद्धति के विरुद्ध है.

जैन समुदाय में धीरे-धीरे यह भावना बलवती होती जा रही है कि भाजपा जैन धर्म को सनातन धर्म में समाहित करने की साजिश में लगी है. गुजरात विधानसभा से पारित धर्म की स्वतंत्रता विधेयक, 2006 में जैनियों और बौद्धों को हिंदू श्रेणी के अंतर्गत रखने वाले संशोधन का उल्लेख करते हुए अहमदाबाद के एक जैन आंदोलनकारी कहते हैं, ''सियासी रूप से हम भाजपा के साथ जा सकते हैं, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अतीत में मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने जैन धर्म का हिंदू धर्म में विलय करने की कोशिश की थी. कुछ साधु अभी भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार उन पर कोई लगाम नहीं लगा रही.'' व्यापक विरोध के बाद उस विधेयक को 2007 में विधानसभा को वापस भेज दिया गया था. तब से यह दबा हुआ है.

इस बीच, विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष संजय जैन पारसनाथ पहाड़ी पर समुदाय की मांगों को ईकोटुरिज्म यानी पारिस्थितिकीय पर्यटन क्षेत्र के मुद्दे के रूप में रखते हैं. यहां भी भाजपा को दोषी कहा जा रहा. 2019 में जब क्षेत्र को ईकोटुरिज्म क्षेत्र के रूप में विकसित करने की अधिसूचना जारी हुई तब झारखंड में भाजपा ही सत्ता में थी. संजय मांग करते हैं कि सरकार को संशोधित राजपत्र अधिसूचना जारी करनी चाहिए और ईकोटूरिज्म शब्द की जगह 'जैन धार्मिक तीर्थ स्थल' लिखकर क्षेत्र का संरक्षण किया जाना चाहिए. केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ आठ महीने तक चली बातचीत के बेनतीजा रहने और बीते साल के अंत में हुए प्रदर्शनों की ओर इशारा करते हुए वे कहते हैं, ''मांगे पूरी होने तक हम चैन से न बैठेंगे.''

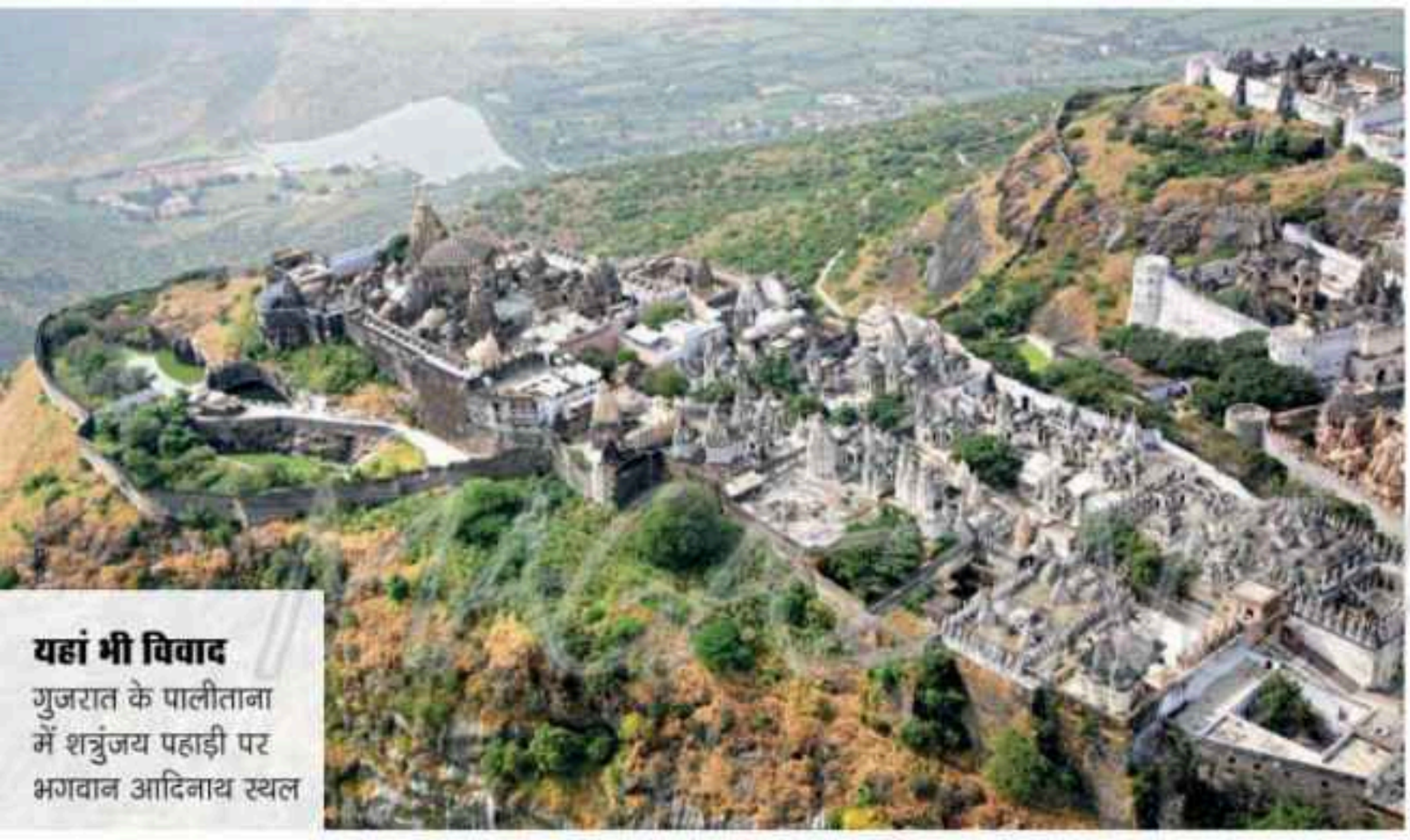

यहां भी विवाद
गुजरात के पालीताना में शत्रुंजय पहाड़ी पर भगवान आदिनाथ स्थल

शैलेष रावल

लेकिन पारसनाथ पहाड़ मामले में भी कुछ और दावेदार हैं. गिरिडीह पहाड़ियों के आदिवासी इसे अपने पवित्र पूजा स्थल के रूप में देखते हैं. आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता सिकंदर हेम्ब्रम कहते हैं, ''हम पीढ़ियों से इस क्षेत्र की रखवाली कर रहे हैं. यह पवित्र पहाड़ी मरांग बुरु है, और हम अपने रीति-रिवाजों के अनुसार वहां पूजा करते हैं. हम किसी को वहां हमपर रोक नहीं लगाने देंगे.'' वैसे, संजय जैन का दावा है कि मरांग बुरु भगवान पार्श्वनाथ का ही आदिवासी नाम है जिनके नाम पर पारसनाथ पहाड़ी और वन्यजीव अभयारण्य का नाम रखा गया है. वे कहते हैं, ''स्थानीय लोगों के साथ हमारा कोई संघर्ष नहीं क्योंकि आदिवासी प्रकृति पूजक हैं. यह विरोध विशुद्ध सियासत है. सरकार की ओर से अधिसूचना वापस लेने पर यह सब सुलझ सकता है.''■

राहुल नरोन्हा

अक्सर वामपंथी उग्रवाद की वजह से सुर्खियों में रहने वाला दक्षिण छत्तीसगढ़ इस बार सांप्रदायिक घटनाओं से हिल गया है. पिछले तीन हफ्तों में नारायणपुर और कोंडागांव जिलों में कथित हिंदू आदिवासियों ने धर्मांतरित आदिवासी ईसाइयों पर हमले किए हैं. इसकी वजह से सैकड़ों ईसाई आदिवासी अपने घरों को छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं.

सत्तारूढ़ कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि उसने आदिवासियों के बीच कलह के बीज बोने का प्रयास किया है. वहीं भाजपा ने इन हमलों को 'स्वाभाविक' करार दिया है. हालिया घटना 2 जनवरी की है जब आदिवासी हिंदुओं की ओर से नारायणपुर जिले के भाजपा अध्यक्ष रूप सिंह सलाम की अगुआई में किया गया प्रदर्शन हिंसक हो उठा. प्रदर्शनकारियों ने एक चर्च और पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार पर हमला कर दिया. अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए. सलाम समेत दोनों पक्षों के 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

वैसे, राज्य भाजपा के कार्यकारी सदस्य प्रबल प्रताप जूदेव कहते हैं, ''भाजपा का इन हमलों से कोई वास्ता नहीं है. पर यह सच है कि पिछले कुछ समय से बस्तर में जबरन धर्मांतरण एक मुद्दा रहा है. अगर आपको याद हो तो सुकमा के एसपी ने जुलाई 2021 में आगाह किया था कि धर्मांतरित, गैर-धर्मांतरित आदिवासियों के बीच तनाव से बलवे का अंदेशा है.'' उनके पिता और भाजपा के दिवंगत नेता दिलीप सिंह जूदेव ने ही आदिवासी ईसाइयों के लिए 'घर वापसी' अभियान शुरू किया था.

दो जनवरी की घटना को लेकर पांच एफआइआर दर्ज हुई हैं. फसाद में शामिल आदिवासी ईसाइयों और आदिवासी हिंदुओं पर दंगों से जुड़ी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है. वहीं सलाम और 11 अन्य पर चर्च और एसपी पर हमला करने का भी आरोप है. इनमें से छह पर हत्या की कोशिश का मामला भी दर्ज किया गया है. ज्यादातर मामलों में आदिवासी समुदाय के कुछ सदस्यों की ओर से ईसाई रीति-रिवाजों

^ अपने ही खिलाफ
नारायणपुर जिले में बंगला पाड़ा इलाके में एक क्षतिग्रस्त चर्च

छत्तीसगढ़

आपस में ही भिड़े आदिवासी

के पालन को लेकर विवाद के साथ हमलों की शुरुआत हुई. धर्मांतरित ईसाई आदिवासियों पर हमले हुए, उनके घरों में तोड़फोड़ की गई और उनके सामानों को बाहर फेंक दिया गया. छह गांवों के करीब 400 विस्थापित लोगों को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में शरण लेनी पड़ी.

देश के अन्य भागों में रहने वाले ईसाई लोगों का भी इन पर ध्यान गया है. यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम (यूसीएफ) की एक फैक्ट-फाइंडिंग टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है. फेडरेशन ऑफ कैथलिक एसोसिएशन्स ऑफ आर्कडायोसीज ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष ए.सी. माइकल ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय से कार्रवाई की मांग करते हुए एक बयान में कहा, ''महिलाओं और बच्चों समेत करीब 1,000 आदिवासी ईसाइयों को उनके घरों से भगा दिया गया है. असल में उन्हें हिंदू धर्म में धर्मांतरित करने की धमकी दी जा रही है.''

इन घटनाओं पर कांग्रेस सरकार का रुख रक्षात्मक ही है. वहीं, आदिवासी क्षेत्रों में कुछ नेताओं को पार्टी से मिल रही अहमियत से स्पष्ट है कि भाजपा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रही है. सलाम और नारायणपुर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नारायण मरकाम, दोनों को केंद्र में लाया गया है. दोनों ऐसी संस्था से जुड़े थे जो वर्षों से धर्मांतरण सरीखे मुद्दों पर काम कर रही है. 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने बस्तर इलाके में 12 में से 11 सीटें जीत ली थी. भाजपा को मिली एकमात्र सीट को भी बाद में उपचुनाव में कांग्रेस ने छीन लिया था.

पुलिस जबरन धर्मांतरण या लालच या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन की कोई शिकायत मिलने से इनकार करती है. पिछले चार साल में रीति-रिवाजों को मानने या न मानने को लेकर गांववालों के बीच हुए विवाद में 14 एफआइआर दर्ज हो चुकी हैं. इनमें कुल 158 लोगों पर मुकदमा चल रहा है. ऐसे में अब हाल में ईसाई धर्म में धर्मांतरित हुए लोग अपने धर्म के बदलाव की सूचना या आवेदन नहीं दे रहे हैं. पर जन्म, मृत्यु या विवाह के वक्त विवाद होते हैं क्योंकि किसी एक परिवार में धर्मांतरित और गैर-धर्मांतरित सदस्य अपनी अलग-अलग धार्मिक पहचान के आधार पर रीति-रिवाजों का पालन करते हैं.

इसको लेकर बड़ी बहस यह है कि ईसाई धर्म में जाने से पहले वे लोग आदिवासी थे या हिंदू. जूदेव का कहना है, ''आदिवासी निश्चित रूप से हिंदू हैं. वे हिंदू धर्म के रखवाले हैं.'' पर ईसाई नेता और खुद आदिवासियों का एक वर्ग इसका खंडन करता है. आदिवासियों के बीच सरना धर्म आंदोलन भी इसमें शामिल है.

राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इन हमलों के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन भाजपा ने इससे इनकार किया है

आदिवासियों का एक वर्ग मांग कर रहा है कि अगली जनगणना में वे खुद को हिंदू के रूप में सूचीबद्ध न करें. इसने भाजपा के माथे पर बल डाल दिया है क्योंकि इससे मतदान में उनकी पसंद-नापसंद का पैमाना बदल सकता है.

क्या आदिवासी ईसाइयों की संख्या बढ़ी है? या आदिवासी हिंदू हैं या नहीं—इन मोर्चों पर 2011 की जनगणना के नतीजे रोशनी डालते हैं. उसमें नारायणपुर जिले की आबादी 1.39 लाख थी, जिसमें 92.38 फीसद यानी 1.29 लाख लोगों ने खुद को हिंदू बताया, जबकि 0.43 फीसद यानी केवल 600 लोगों ने खुद को ईसाई के रूप में पंजीकृत किया.

ईसाई नेताओं ने दावा किया है कि हमलों से विस्थापित होने वाले ईसाइयों की संख्या 1,000 से ज्यादा है. इसका मतलब यह कि पिछले दशक में कई ईसाइयों ने खुद को ईसाई नहीं बताया है या यह नहीं बताया कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है. नारायणपुर जिले की कुल आबादी के करीब 77 फीसद आदिवासी बताए जाते हैं और 92 फीसद हिंदू आबादी का मतलब है कि आदिवासियों के बड़े वर्ग ने खुद को हिंदू बताया है. वहीं, नारायणपुर में 6.11 फीसद आबादी ने खुद को 'अन्य' बताया है. अनुमान है कि यह आबादी उन आदिवासियों की है जो खुद को न तो हिंदू, न ही ईसाई बताते हैं, बल्कि वे खुद को केवल आदिवासी के रूप में सूचित करते हैं.

लेकिन अब नारायणपुर में आदिवासी बनाम आदिवासी की ही जंग छिड़ गई है.■

दोनों फोटोः एएनआइ

^ गठबंधन का मौसम

(बाएं से) प्रकाश आंबेडकर, उद्धव ठाकरे, और जोगेंद्र कावडे और एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र

दलितों पर डाल रहे डोरे

धवल कुलकर्णी

कहते हैं कि मुश्किल हालात से निबटने के लिए सख्त उपाय करने होते हैं. आगामी निकाय चुनावों के प्रतिष्ठा की लड़ाई बनने और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अंतिम लड़ाई होने के मद्देनजर शिवसेना के दो प्रतिद्वंद्वी गुट दलित समूहों को रिझाने के लिए एक-दूसरे से होड़ लगा रहे हैं. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) के प्रमुख और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर के साथ गठजोड़ की कोशिश कर रहा है. दूसरी ओर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बालासाहेबांची शिवसेना (बीएसएस) ने पूर्व लोकसभा सांसद जोगेंद्र कवाडे के नेतृत्व वाली पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी (पीआरपी) के साथ गठबंधन कर लिया है. बीएसएस की प्रमुख सहयोगी भाजपा ने रामदास अठावले से पहले ही गठजोड़ कर रखा है, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआइ) के अपने गुट के नेता और नरेंद्र मोदी सरकार में राज्यमंत्री हैं.

यह समझना मुश्किल नहीं है कि मुख्यधारा की सियासी पार्टियां आरपीआइ के गुटों को रिझाने के लिए क्यों लालायित हैं. इन गुटों में मुख्यतः नव बौद्ध दलित हैं. नव-बौद्ध (वे महार जिन्होंने 1956 में आंबेडकर के साथ धर्मांतरण कर लिया) राज्य की आबादी का 7-8 फीसद हैं और वे दलितों में सबसे बड़े समूह हैं. इसके अलावा, दलितों में सबसे ज्यादा जुझारू समझे जाने वाले नव-बौद्धों को किसी मुद्दे पर एकजुट करना आसान होता है. महाराष्ट्र में करीब 59 अनुसूचित जाति (एससी) समूह हैं. हालांकि कोई समुदाय एक साथ किसी को वोट नहीं करता लेकिन विभिन्न आरपीआइ गुटों को नव-बौद्ध दलितों के बीच समर्थन हासिल है.

उद्धव और प्रकाश 20 नवंबर को महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक 'प्रबोधनकार' केशव सीताराम ठाकरे को समर्पित एक पोर्टल के रिलॉन्च के अवसर पर एक मंच पर आए. प्रबोधनकार उद्धव के दादा थे और बहुजन समर्थक (गैर-ब्राह्मण) हिंदुत्व के पैरोकार थे. वे डॉ. आंबेडकर के भी सहयोगी थे. दो प्रमुख हस्तियों के पोतों की मुलाकात के बाद मुंबई, ठाणे, पुणे और नागपुर जैसे शहरों के निकाय चुनावों में गठबंधन की जमीन तैयार होने लगी. प्रकाश का यह प्रस्ताव स्वाभाविक है. आरपीआइ के दूसरे नेताओं के उलट उनका जनाधार हिंदू दलितों, अलुतेदारों (छोटे ओबीसी), मुसलमानों के साथ ही पढ़े-लिखे शहरी दलितों में भी है.

शिंदे और कावडे ने भी 4 जनवरी को अपनी पार्टियों के बीच गठजोड़ का ऐलान किया. कावडे ने 1984 में कथित तस्कर हाजी मस्तान मिर्जा के साथ मिलकर दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ का गठन किया था, जो महाराष्ट्र में दलित-मुस्लिम का पहला राजनैतिक गठजोड़ था. कावडे अतीत में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से भी गठजोड़ कर चुके हैं.

महाराष्ट्र की आबादी में नव-बौद्ध 7-8 फीसद हैं और वे सबसे बड़े दलित समूह हैं. वे जुझारू भी माने जाते हैं

उद्धव और शिंदे, दोनों के नेतृत्व वाले गुट खुद को 'असली' शिवसेना साबित करने में जुटे हैं. यह मुंबई में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा, जहां बीएसएस-भाजपा बृहन्नमुंबई नगर निगम पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही हैं. देश के सबसे अमीर शहरी निकाय पर फिलहाल उद्धव गुट का कब्जा है. दोनों के बीच संघर्ष तेज होने पर छोटी पार्टियां चुनाव के नतीजे बदल सकती हैं.

संयोगवश, शिवसेना और बौद्ध दलितों के बीच दुश्मनी का इतिहास रहा है. शिवसेना और दलित पैंथरों के बीच वर्ली में 1974 में संघर्ष हुआ था. पैंथरों को शिवसेना से भिड़ने वाला इकलौता सामाजिक समूह माना जाता था. शिवसेना ने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम आंबेडकर रखे जाने का विरोध किया था और इसी मुद्दे पर उसने मराठों, हिंदू दलितों और ओबीसी के बीच अपना आधार बढ़ाया था. अठावले और कावडे 'नामांतर' आंदोलन (1978-1994) की उपज हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग की गई थी.

मुंबई यूनिवर्सिटी में कला संकाय के पूर्व डीन पी.जी. जोगडंड का कहना है, "सियासी पार्टियां खुद को प्रगतिशील दिखाने के लिए आरपीआइ गुट से जुड़ना चाहती हैं... (लेकिन) अगर प्रकाश और शिवसेना हाथ मिला लें तो यह स्वागत योग्य होगा और एक नया सामाजिक इंजीनियरिंग का मॉडल बन सकता है." इससे किसी को फायदा हो न हो, आरपीआइ नेताओं को जरूर फायदा होगा. ■

निवेश को धरातल पर उतारने की चुनौती

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले योगी सरकार ने रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौते हासिल किए. लेकिन एमओयू को अमली जामा पहनाने में होगी सरकार की कठिन परीक्षा

आशीष मिश्र

मुंबई के कोलाबा में स्थित होटल ताज महल 5 जनवरी को दिग्गज उद्योगपतियों का मुख्य गंतव्य बन गया. वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए घरेलू निवेशकों को न्योता देने के लिए मौजूद थे. उन्होंने इस पहले घरेलू रोड शो की शुरुआत सुबह नौ बजे देश के प्रमुख बैंकर्स के साथ बैठक करके की. उन्होंने यूपी में अपनी सरकार के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हुए बदलावों और कानून व्यवस्था में सुधार की जानकारी दी. उन्होंने बैठक में बैंकर्स और वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों से यूपी के विकास में सहयोग की अपील की. उसके बाद योगी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी, आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला, हीरानंदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हीरानंदानी, कोटक महिंद्रा के सीईओ उदय कोटक समेत देश के कुल 22 प्रमुख उद्योगपतियों के साथ एक-एक करके मुलाकात की. सुबह नौ बजे से शुरू यह सिलसिला रात साढ़े आठ बजे फिल्म निर्माता एवं निदेशक सुभाष घई, बोनी कपूर, अभिनेता जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी समेत बॉलीवुड के अहम लोगों के साथ बैठक के बाद खत्म हुआ. फिर योगी पांच लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्ताव लेकर मुंबई एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो गए. उसके बाद योगी सरकार के प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों ने घरेलू निवेशकों को लुभाने के लिए 9-27 जनवरी के बीच देश के अहम शहरों में रोड शो की कमान संभाल ली है.

मार्च, 2022 में यूपी की सत्ता में दोबारा वापसी करने वाले योगी की सरकार 10 से 12 फरवरी के बीच प्रदेश में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने जा रही है. विदेशी निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए योगी ने सरकार के 12 मंत्रियों को 8 से 19 दिसंबर के बीच 17 देशों में रोड शो का जिम्मा सौंपा (देखें ग्राफिक्स). उन रोड शो को आठ रूट में बांटा गया. हर रूट की जिम्मेदारी उपमुख्यमंत्री या वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री को सौंपी गई. मैक्सिको और ब्राजील में रोड शो करने वाले उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बताते हैं, ''मुख्यमंत्री योगी की पहल पर रोड शो वाले हर देश में स्थित भारतीय दूतावास ने पहले से ही प्रमुख उद्योगपतियों को बैठक के लिए आमंत्रित कर रखा था. उन सभी देशों की स्थानीय भाषा में योगी सरकार की करीब 27 प्रमुख योजनाओं का अनुवाद भी कराया गया था. भाषा संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए

निवेश की कवायद

मुंबई में रोड शो के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांच लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हासिल किए

MAGAZINE KING

मंत्रियों के साथ अनुवादक की भी व्यवस्था थी. इनसे विदेशी निवेशकों के सामने यूपी की ब्रान्डिंग करने में सहजता हुई.''

विदेश गए मंत्रियों ने 22 दिसंबर को योगी को अपने दौरे की उपलब्धियों की रिपोर्ट सौंपी. मंत्रियों ने 17 देशों के निवेशकों के साथ 269 बैठकें की. इस दौरान 7.12 लाख करोड़ रुपए के 149 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए जिनसे सात लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना जताई गई.

मंत्रियों के विदेश दौरे से पहले योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कुल 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा था. पर विदेशों में हुए रोड शो और योगी के मुंबई में हुए घरेलू रोड शो के बाद सरकार ने कुल निवेश का लक्ष्य बढ़ाकर 17 लाख करोड़ रुपए कर दिया है. इसको पाने के लिए देश के प्रमुख शहरों के साथ यूपी के हर जिले में भी निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. 10 जनवरी को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में हुए जिला निवेशक सम्मेलन में 50 हजार करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्तक्षर किए गए. जिलों में निवेशक सम्मेलन के साथ 15 जनवरी से 2 फरवरी तक प्रयागराज, वाराणसी, आगरा समेत प्रदेश के 8 मंडल मुख्यालयों में भी रोड शो की योजना बनाई गई है. एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश लक्ष्य पाने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) इन रोड शो का आयोजन कर रहा है. लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर अरविंद मोहन बताते हैं, ''सुशासन के साथ सियासी स्थिरता भी औद्योगिक निवेश की जरूरी शर्त है जो 2018 की इन्वेस्टर्स समिट की तुलना में इस बार योगी सरकार के पक्ष में जाती है. प्रदेश में निवेश जुटाने के लिए पहली बार चरणबद्ध ढंग से प्रयास किए जा रहे हैं. सरकार निवेशकों का भरोसा जीतने में सफल हुई तो यूपी में औद्योगिक विकास का एक नया युग शुरू होगा. इससे यूपी की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी.''

''योगी सरकार में यूपी निवेश का ड्रीम डेस्टीनेशन बन चुका है. सुरक्षा, संभावना, सहयोग के कारण निवेशक यहां निवेश के लिए स्वयं आगे आ रहे हैं''

–नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी',
औद्योगिक विकास मंत्री, यूपी

अब तक का हिसाब-किताब

- यूपी इन्वेस्टर्स समिट (21-22 फरवरी 2018): 4.28 लाख करोड़ रुपये के 1,045 एमओयू मंजूर.
- पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (29 जुलाई, 2018): 61,792 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास.
- दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (28 जुलाई, 2019): 67,202 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास.
- तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (3 जून, 2022): 80,324 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं की शुरुआत.
- औद्योगिक विकास विभाग के अनुसार, वर्ष 2018 से अबतक तीन लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव जमीन पर उतरे. 65 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए. कोरोना काल में 66 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को अमली जामा पहनाया गया.

टीम योगी ने विदेश में जुटाया निवेश प्रस्ताव

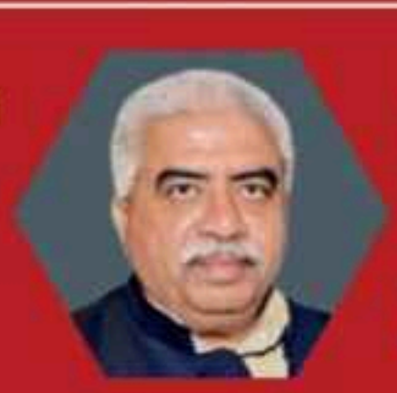

राकेश सचान
(कैबिनेट मंत्री लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग विभाग)

रोड शो: **यूएई (11 से 13 दिसंबर)**
प्रस्तावित निवेश: **18,590 करोड़ रु.**
प्रस्तावित रोजगार: **20,110**
इच्छुक मुख्य कंपनियां: **श्री सिद्धार्थ इन्फ्राटेक ऐंड सर्विसेज, आस्था ग्रीन एनर्जी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, लूलू ग्रुप**

जयवीर सिंह
(कैबिनेट मंत्री, पर्यटन विभाग)

आशीष पटेल
(कैबिनेट मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग)

रोड शो: **जापान, दक्षिण कोरिया (10 से 14 दिसंबर)**
प्रस्तावित निवेश: **18,350 करोड़ रु.**
प्रस्तावित रोजगार: **16,700**
इच्छुक मुख्य कंपनियां: **निसेकेन क्वालिटी इवेल्यूवेशन सेंटर टोक्यो, वन वर्ल्ड कॉरपोरेशन.**

धर्मपाल सिंह
(कैबिनेट मंत्री, पशुपालन विभाग)

सतीश महाना
(अध्यक्ष, यूपी विधानसभा)

रोड शो: **कनाडा, यूएसए (8 से 19 दिसंबर)**
प्रस्तावित निवेश: **19,265 करोड़ रु.**
प्रस्तावित रोजगार: **1,410**
इच्छुक मुख्य कंपनियां: **मोबेलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रुप, क्यूएसटीसी आइएनसी, माई हेल्थ सेंटर**

योगेंद्र उपाध्याय
(कैबिनेट मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आइटी विभाग)

केशव प्रसाद मौर्य
(उपमुख्यमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग)

रोड शो: नीदरलैंड, **फ्रांस (16 से 19 दिसंबर)**
प्रस्तावित निवेश: **9,664 करोड़ रु.**
प्रस्तावित रोजगार: **6,800**
इच्छुक मुख्य कंपनियां: **माहलर फंड्स, पारटेक्स एवी, इन्नोटेरा**

जितिन प्रसाद
(कैबिनेट मंत्री, लोक निर्माण विभाग)

नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' (कैबिनेट मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग)

रोड शो: **जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन (9 से 14 दिसंबर)**
प्रस्तावित निवेश: **17,000 करोड़ रु.**
प्रस्तावित रोजगार: **21,000**
इच्छुक मुख्य कंपनियां: **सैमसॉन, सरनेके इंटरनेशन ग्रुप एवी, बोसॉन एनर्जी एसए.**

संजय निषाद
(कैबिनेट मंत्री मत्स्य पालन विभाग)

ब्रजेश पाठक
(उपमुख्यमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग)

रोड शो: **मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना (9 से 14 दिसंबर)**
प्रस्तावित निवेश: **1,725 करोड़ रु.**
प्रस्तावित रोजगार: **4,200**
इच्छुक मुख्य कंपनियां: **द हॉसकिंसन ग्रुप, एम्बारेर**

स्वतंत्र देव सिंह (कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग)

रोड शो: **ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर (13 से 16 दिसंबर)**
प्रस्तावित निवेश: **24,560 करोड़ रु.**
प्रस्तावित रोजगार: **19,500**
इच्छुक मुख्य कंपनियां: **ग्लोबल स्टेट कैपिटल लिमिटेड, मार्बल रॉक्स वीसीसी, यूनिवर्सल सक्सेस लिमिटेड.**

सुरेश खन्ना
(कैबिनेट मंत्री, वित्त विभाग)

रोड शो: **यूके, यूएस (8 से 18 दिसंबर)**
प्रस्तावित निवेश: **11,720 करोड़ रु.**
प्रस्तावित रोजगार: **37,000**
इच्छुक मुख्य कंपनियां: **सिफी इंटरनेशनल, बेस्ट वे ट्रकिंग, इनफाइनाइट सॉल्युशंस**

(स्रोत: औद्योगिक विकास विभाग, यूपी)

MAGAZINE KING

निवेशकों के लिए बंजर बना बुंदेलखंड

योगी सरकार की कई कोशिशों के बावजूद बुंदेलखंड में उद्योग लगाने में रुचि नहीं दिखा रहे निवेशक. अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से बढ़ी उम्मीद

बांदा से चिल्ला रोड पर बंद पड़ी जिले की पहली सरकारी कताई मिल

उद्योगों का सूखा झेल रहे बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले के लिए वर्ष 2018 में यूपी सरकार का 'इन्वेस्टर्स समिट' एक सौगात लेकर आया था. इसमें इंग्लैंड की कंपनी एवी मौरी ने 400 करोड़ रुपए की लागत से खमीर प्लांट लगाने का एमओयू किया था. प्रदेश सरकार ने भी तेजी दिखाते हुए दो साल के भीतर चित्रकूट से मीरजापुर हाइवे पर मौजूद बरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में 68 एकड़ जमीन भी आवंटित कर दी थी. खमीर फैक्ट्री लगने से बुंदेलखंड के करीब 2,000 लोगों में नौकरी की आस भी जगी थी. चित्रकूट के राजकीय इंटर कॉलेज में प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद बरगढ़ गांव में रहने वाले सत्य प्रकाश विश्वकर्मा बताते हैं, ''दो साल से लोग बरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में खमीर की फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा.''

सत्य प्रकाश के जेहन में करीब 34 वर्ष पूर्व की यादें ताजा हो जाती हैं जब 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी कांटीनेंटल ग्लास फैक्ट्री का शिलान्यास किया था. सत्य प्रकाश बताते हैं, '' शिलान्यास के पहले साल तो बहुत तेजी से निर्माण कार्य हुआ. लेकिन 1989 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के सत्ता से हटने के बाद फैक्ट्री का निर्माण कार्य ठप हो गया. उसके बाद से किसी भी सरकार ने ग्लास फैक्ट्री की सुध नहीं ली.'' आज बरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में वीरानी छाई हुई है. बंद पड़े ग्लास फैक्ट्री के परिसर को बड़ी-बड़ी झाड़ियों ने ढक लिया है. चित्रकूट के जिला उद्योग अधिकारी संदीप केसरवानी बताते हैं, ''चित्रकूट में खमीर प्लांट लगाने वाली कंपनी एवी मौरी ने अधिक जमीन की मांग की थी इसलिए उसे पीलीभीत जिले में 100 एकड़ जमीन आवंटित की गई है. बरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में खमीर प्लांट के लिए आवंटित जमीन 'पेप्सिको' की सहायक कंपनी 'वरुण बेवरेज' को आवंटित की गई है. यह अगले कुछ महीनों में निर्माण कार्य शुरू कर देगी.'' धर्मनगरी चित्रकूट की तरह इसके बगल का जिला बांदा भी औद्योगिक निवेश की राह तक रहा है. जिले में चिल्ला रोड पर जिले की इकलौती औद्योगिक इकाई राजकीय कताई मिल दिसंबर, 1998 से बंद है. वर्ष 2018 के इन्वेस्टर्स समिट में बंद पड़ी कताई मिल की जगह पर दूसरा उद्योग लगने की संभावना बनी थी लेकिन किसी भी निवेशक ने इसमें रुचि नहीं दिखाई. बांदा से महोबा रोड पर 150 हेक्टेयर क्षेत्र में भूरागढ़ औद्योगिक क्षेत्र निवेशकों को लुभाने में पूरी तरह विफल साबित हुआ है. इस औद्योगिक क्षेत्र में ई-रिक्शा, लोहे के दरवाजे, प्लास्टिक सामग्री आदि से जुड़े 16 कारखाने संचालित हो रहे हैं लेकिन यहां कई जरूरी सुविधाओं का अभाव है. ई-रिक्शा कारखाना संचालक समीर गुप्ता बताते हैं, ''भूरागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, जलभराव और सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं हैं. प्रति वर्ष आठ हजार रुपए मेंटेनेंस चार्ज के रूप में लिए जाते हैं लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिलता. औद्योगिक क्षेत्रों की बदहाली भी निवेश में बड़ी बाधा है.'' वैसे, फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले बांदा में उद्योग विभाग को 24 उद्यमियों से 180 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं.

वर्ष 2017 में यूपी में सरकार बनाते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ाग्रस्त क्षेत्र बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास तेज करने के प्रयास शुरू कर दिए थे. यह योगी के प्रयासों का नतीजा ही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी, 2018 को लखनऊ में आयोजित यूपी इन्वेस्टर्स समिट में यूपी को रक्षा उत्पादों का केंद्र बनाने और बुंदेलखंड के विकास को गति देने के लिए 'डिफेंस कॉरिडोर' परियोजना की घोषणा की थी. परियोजना के छह नोड में से दो चित्रकूट और झांसी, बुंदेलखंड के ही जिले हैं. डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) को चित्रकूट में 101 हेक्टेयर जमीन आवंटित की जा चुकी है लेकिन इसपर उपक्रम लगाने के लिए किसी भी निवेशक ने रुचि नहीं दिखाई है. झांसी में आवंटित 195 हेक्टेयर जमीन में 183 हेक्टेयर केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन उपक्रम भारत डायनिमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) को पट्टे पर दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक इसपर निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ है. बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास के आंकड़ों का अध्ययन करने वाले कानपुर विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर राज बहादुर बताते हैं, ''एक्सप्रेसवे

धर्मनगरी चित्रकूट की तरह ही इसकी बगल का जिला बांदा भी औद्योगिक निवेश की बाट जोह रहा है. जिले की राजकीय कताई मिल वर्ष 1998 से बंद पड़ी है

और अन्य आधारभूत ढांचा अपेक्षाकृत मजबूत होने के बावजूद बुंदेलखंड नोएडा जैसे किसी विकसित शहर से दूर है. एक विकसित एयरपोर्ट की सुविधा न होने से भी बुंदेलखंड बड़े निवेशकों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है.'' योगी सरकार ने मार्च, 2017 में सत्ता संभालने के एक साल के भीतर फरवरी, 2018 में लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था. इसमें साढ़े चार लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे. औद्योगिक विकास विभाग के अनुसार, इनमें से तीन लाख करोड़ रुपये के एमओयू क्रियान्वित किए जा चुके हैं.

दूसरी बार प्रदेश की सत्ता संभालने के 100 दिन के भीतर ही मुख्यमंत्री योगी ने 3 जून, 2023 को तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया था. इस सेरेमनी में 80,224 करोड़ रुपए की निवेश वाली जिन 1,406 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ था उनमें बुंदेलखंड में स्थापित होने वाली परियोजनाओं की संख्या महज 34 है. अभी भी नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी के पश्चिमी जिले निवेशकों की पहली पसंद बने हुए हैं. औद्योगिक विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' बुंदेलखंड में निवेश बढ़ने को लेकर बेहद आशान्वित हैं. गुप्ता कहते हैं, ''बुंदेलखंड और पूर्वांचल में होने वाले निवेश को राज्य की नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के अंतर्गत 15 से 30 प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. इससे पिछड़े क्षेत्रों में निवेश का माहौल बना है.''

क्षेत्रवार निवेश परियोजनाएं

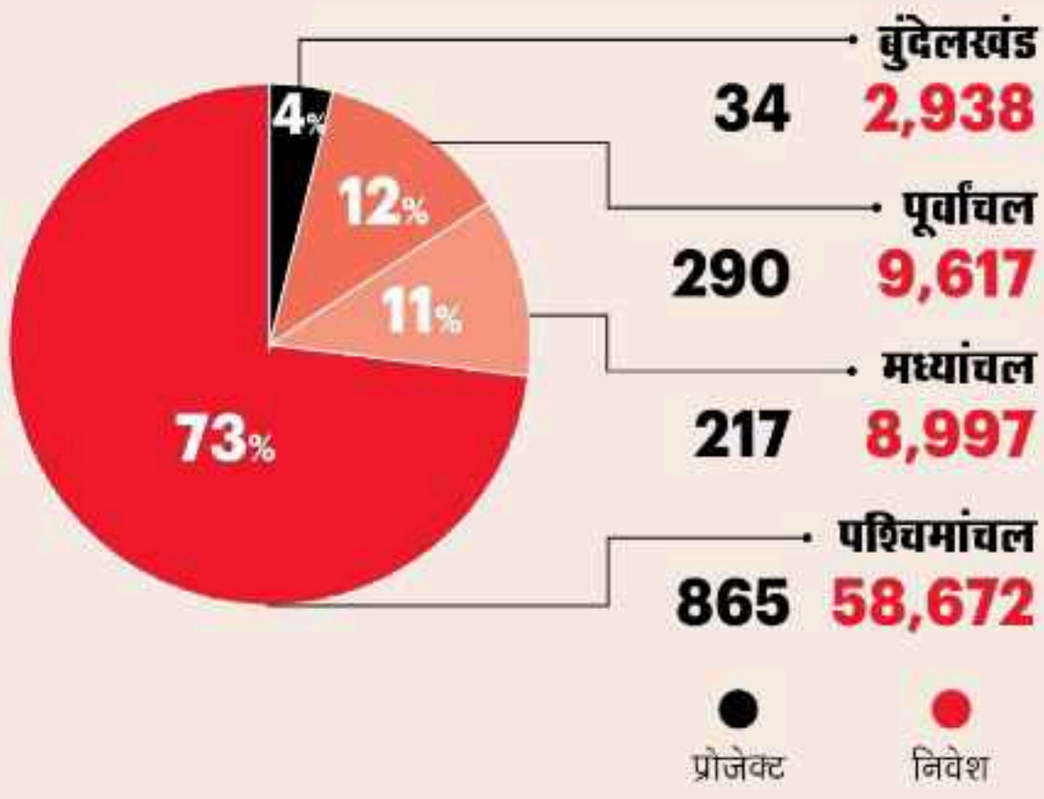

नोटः ब्योरा जून, 2022 में आयोजित 80 हजार करोड़ रुपए के निवेश वाली तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का है. निवेश के आंकड़े करोड़ रुपये में हैं. स्रोतः औद्योगिक विकास विभाग, यूपी

वैसे, इन एमओयू पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं. समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट एवं प्रवासी भारतीय विभाग के दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री रहे मधुकर जेटली कहते हैं, ''एमओयू की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है. यह उद्योगपतियों की ओर से सरकार को दिया जाने वाला एक 'ऑफर' है. इसे उपलब्धि के तौर पर प्रचारित करना जनता को बेवकूफ बनाना है. इन निवेश प्रस्तावों को हकीकत में उतारना योगी सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा.'' 2018 के इन्वेस्टर्स समिट में कई निवेश प्रस्ताव अभी तक हकीकत में नहीं उतर पाए हैं. बरेली में फर्नीचर निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से फर्नीचर पार्क, पीलीभीत में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जैसे प्रोजेक्ट जमीन न मिलने से शुरू नहीं हो पाए हैं. वैसे, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में होने वाले निवेश समझौतों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने खास इंतजाम किए हैं. यूपीसीडा ने नए उद्योगों के लिए 12 हजार एकड़ से अधिक का लैंड-बैंक तैयार किया है. औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' बताते हैं, ''राजस्व संहिता के प्रावधानों में संशोधन करके उद्योगों के लिए भूमि उपयोग प्रबंधन को सरल बनाया गया है. कृषि योग्य भूमि को गैर-कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन, भूउपयोग परिवर्तन, अनुसूचित जाति और जनजाति की भूमि की बिक्री से जुड़े प्रावधान आसान किए गए हैं.''

दोबारा सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने बदलाव के साथ औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नीति, टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पॉलिसी समेत कुल 30 जरूरी नीतियों को लागू किया है. करीब 17 लाख करोड़ रुपए के निवेश को जमीन पर उतारने के लिए योगी की सीधी निगरानी में एक टीम काम कर रही है. मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में निवेश से जुड़ी पूरी प्रक्रिया पहली बार ऑनलाइन कर दी गई. निवेश के लिए बनी संस्था 'इन्वेस्ट यूपी' के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रथमेश कुमार बताते हैं, ''ऑनलाइन पोर्टल 'निवेश मित्र' और 'निवेश सारथी' के जरिए निवेशकों को सुगम व्यापार का मौका मुहैया कराया जा रहा है. अब निवेशकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है.'' वहीं, 'निवेश मित्र' पोर्टल के तहत 'ऑनलाइन इन्सेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम' की शुरुआत की गई है. इस केंद्रीकृत व्यवस्था के जरिए निवेशकों को विभिन्न नीतियों के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन को आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है.

यूपी के पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले भारी-भरकम एमओयू करके योगी सरकार ने अपनी चुनौती बढ़ा ली है. अगर इन एमओयू को अमली जामा पहनाने में वह सफल हुई तो यूपी में औद्योगिक विकास के एक नए दौर की शुरुआत होगी अन्यथा इन्वेस्टर्स समिट महज एक आयोजन बनकर ही रह जाएगा. ■

''एमओयू निवेशकों की ओर से सरकार को दिया जाने वाला एक 'ऑफर' भर है. इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है. योगी सरकार को अभी तक जमीन पर उतरे कुल निवेश पर श्वेत पत्र लाना चाहिए''

–मधुकर जेटली, पूर्व दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री, एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट एवं एनआरआइ विभाग

ध्यान से सुनें
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा पटना में पार्टी विस्तारकों को संबोधित करते हुए

MAGAZINE KING

सज गई बिसात मिशन 350 की

भाजपा ने लोकसभा चुनावों से डेढ़ साल पहले ही अपने लिए मुश्किल 160 सीटों की पहचान की. 350 से ज्यादा के लक्ष्य के तहत 160 में से हर सीट जीतने की रणनीति तैयार

हिमांशु शेखर

''हम सब एक ऐसी यात्रा पर निकल चुके हैं, जिसका लक्ष्य भारत को परम वैभव दिलाना है. इस यात्रा में कोई आपकी पीठ थपथपाए, कोई शाबाशी दे या कोई उपेक्षा करे, आपको प्रसन्न होने या विचलित होने की जरूरत नहीं. आज आप विस्तारक हैं, कल आप प्रदेश के अध्यक्ष भी हो सकते हैं. यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है.'' हौसले और आत्मविश्वास को भीतर से मजबूत करने वाला यह भाषण भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा अभी पिछले ही महीने पटना में पार्टी की भविष्य की रणनीति के लिहाज से एक बड़े अहम मौके पर दे रहे थे. 21-22 दिसंबर को हुए इस प्रशिक्षण शिविर में वे 100 विस्तारक शामिल थे जो चुनावों के लिहाज से पार्टी के लिए 19 राज्यों की मुश्किल सीटों पर काम करने जा रहे थे.

यह शिविर दरअसल ऐसे दो प्रशिक्षण शिविरों की कड़ी में पहला था. 28-29 दिसंबर को हैदराबाद में हुए दूसरे शिविर में 60 विस्तारकों का प्रशिक्षण हुआ. ये विस्तारक 12 राज्यों की मुश्किल सीटों पर काम करेंगे. इन शिविरों की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दोनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के अलावा पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, महासचिव सुनील बंसल और एक अन्य महासचिव तथा बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद थे. जिन राज्यों में शिविर हो रहे थे, वहां के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक और पार्टी के दूसरे पदाधिकारी तो थे ही. अपनी पेप टॉक में नड्डा ने इन विस्तारकों को पीएम नरेंद्र मोदी के जनकल्याणकारी योजनाओं को जन—जन तक पहुंचाने की भी हिदायत दी.

इससे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी पार्टी की चुपचाप जमीनी स्तर पर चल रही तैयारियों का सिर्फ अंदाज लगाया जा सकता है. ये तैयारियां नितांत जमीनी यथार्थ पर खड़े रहकर की जा रही हैं. यही वजह है कि गुजरात विधानसभा चुनावों में पिछले महीने पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत (182 में से 156 सीटें) के बावजूद उसने 2024 के 'मुश्किल सीटों' की संख्या 144 से बढ़ाकर 160 कर दी. उसने अतिउत्साह में आने से पूरी तरह परहेज किया. पार्टी ने कुछ उसी तर्ज पर अगले लोकसभा चुनावों में 350 से ज्यादा सीटें हासिल करने का लक्ष्य तय किया है जिस तरह से उसने 2022 के गुजरात विधानसभा चुनावों में 150 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था. इसे नाम दिया गया है 'मिशन 350'. 160 मुश्किल सीटों की पहचान करके उन पर अभी से सुनियोजित काम करना पार्टी के इसी मिशन का हिस्सा है. जरूरत पड़ने पर मुश्किल सीटों की संख्या 160 से भी आगे बढ़ाई जा सकती है.

मुश्किल सीटें कहां-कितनी

दरअसल, पार्टी ने पहले चरण में देश भर में 144 मुश्किल सीटों की पहचान की थी. लेकिन दो वजहों से इन सीटों की संख्या 160 की गई. पहला, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड का भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से किनारा करना. नीतीश के विपक्षी खेमे में जाने की वजह से ही भाजपा को बिहार में मुश्किल सीटों की संख्या चार से बढ़ाकर दस करनी पड़ी. और ये दस सीटें हैं: नवादा, वैशाली, वाल्मीकि नगर, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मुंगेर, झंझारपुर, गया और पूर्णिया.

इसी तरह से महाराष्ट्र में पार्टी का समीकरण थोड़ा गड़बड़ाया. भाजपा को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र प्रदेश की सत्ता से बेदखल होने के बाद वहां सत्तारूढ़ महा विकास अघाड़ी में फूट पड़ेगी उद्धव ठाकरे, कांग्रेस तथा शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ जाएगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. तीनों की एकता बनी हुई है. अघाड़ी की उसी एकता को देखते हुए भाजपा ने महाराष्ट्र की 10 नई सीटों को अपनी मुश्किल सीटों की सूची में शामिल किया है. राज्य की बारामती, चंद्रपुर, रायगढ़, शिरूर और सतारा जैसी सीटों को पार्टी अपने लिए मुश्किल मानकर चल रही है.

भाजपा ने इन 160 सीटों की सिर्फ पहचान ही नहीं की है. इनके लिए अलग रणनीति बनाकर अभी से ही उन पर सघन काम शुरू हो गया है. क्या करना है, उस पूरे काम के समन्वय के लिए छह नेताओं की एक संयोजन समिति बनाई गई है. राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े उसके संयोजक हैं. उनके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, जी किशन रेड्डी, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा समिति के सदस्य हैं. और इन सभी 160 मुश्किल सीटों में से एक-एक की जिम्मेदारी गहन प्रशिक्षण की खुराक प्राप्त एक-एक विस्तारक को दी गई है.

इतनी बारीकी से काम! टीम, समिति, विस्तारक! भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरुप्रकाश पासवान सवाल का आशय समझते हुए जवाब देते हैं, ''यह भाजपा की कार्यपद्धति का सहज-स्वाभाविक हिस्सा है. चुनाव की दृष्टि से पार्टी के ध्यान में वे सीटें भी होती हैं, जहां हम मजबूत हैं और उन सीटों पर भी ध्यान दिया जाता है, जहां हमें अपेक्षाकृत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है. इन सीटों पर मोदी सरकार की योजनाओं का ठीक से प्रचार-प्रसार हो और लोगों को यह बताया जाए कि उनकी बेहतरी के लिए केंद्र सरकार किस तत्परता से काम कर रही है, इसी नजरिए से पार्टी ने अपनी एक व्यवस्था बनाई है. हमें यकीन है कि इन मुश्किल सीटों पर

फतह का फॉर्मूला

160 मुश्किल सीटों पर भाजपा ऐसा क्या करने जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में वह इन्हें जीत सके और पार्टी 'मिशन 350' का लक्ष्य हासिल कर सके?

1. 160 सीटों के लिए बनाए गए हैं 160 विस्तारक. ये सभी विस्तारक अभी से लोकसभा चुनाव तक अपनी-अपनी सीट पर रहकर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे.
2. मुश्किल सीटों को चार श्रेणियों में बांटा गया है: सर्वोत्तम, अच्छी, सुधार योग्य और अत्यंत खराब. वर्गीकरण के हिसाब से पार्टी की रणनीति.
3. मुश्किल सीटों के जातिगत और सामाजिक समीकरणों को देखते हुए इन पर सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति अपनाई जाएगी.
4. इन चुनाव क्षेत्रों के रसूखदार लोगों का समूह बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी ऑनलाइन या ऑफलाइन संवाद कराने की योजना है.
5. इन सीटों के रसूखदार लोगों को पार्टी पोस्टर-बैनर में भी जगह देगी.
6. इनमें से कम से कम 40 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली कराने की योजना है. बाकी पर शाह या नड्डा की रैली होगी.
7. हर सीट पर पार्टी की गतिविधियां सघन तौर पर चल सकें, इसके लिए इन सीटों में से जहां पार्टी कार्यालय का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, उसे जल्द से जल्द पूरा करने की रणनीति बनाई गई है.
8. केंद्रीय मंत्रियों के रात्रि प्रवास कार्यक्रम की भी योजना है. इस काम में 40 केंद्रीय मंत्री लगेंगे. हर मंत्री को 3-4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी मिलेगी. इन्हें 'क्लस्टर प्रभारी' बनाया जा रहा है.
9. प्रमुख योजनाओं का फायदा पाने वालों के साथ केंद्रीय मंत्रियों का सीधा संवाद कराया जाएगा.
10. मंत्रियों को योजनाओं के लाभार्थियों से जो फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर संबंधित राज्य के राज्यसभा सांसदों और स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर लोकसभा सीटों के भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और जातिगत समीकरण पर एक रिपोर्ट तैयार करके पार्टी को दी जाएगी.

भी 2024 में जीत हासिल होगी.''

लेकिन विस्तारकों वाला पहलू थोड़ा हटकर है. उसके सामने दिए गए नड्डा के भाषण से साफ हो जाता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उनसे क्या अपेक्षाएं हैं. पहली बात तो यह कि स्थानीय स्तर के नेताओं से अपेक्षित सहयोग और सम्मान मिले चाहे न मिले लेकिन उन्हें अपना काम करते रहना है. उन्हें किसी तरह के शिकवे-शिकायत की झंझट में नहीं फंसना है. दूसरी बात जो उभरकर आती है वह यह कि विस्तारकों को जमीनी स्तर पर केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना है. यहीं एक और पहलू जुड़ता है काशी थीम का. इन विस्तारकों को मुश्किल सीटों पर काशी थीम के आधार पर काम करने को कहा गया है. इसके तहत कश्मीर, अयोध्या, सरकार की योजनाएं, ऑनर यानी गौरव और ईमानदारी को आधार बनाकर भाजपा के लिए मजबूत जमीन तैयार करने की योजना बनी है.

मुश्किल सीटों के लिए बनाई गई रणनीति और उसके क्रियान्वयन में शामिल पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव अपना नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं, ''इन मुश्किल सीटों को चार श्रेणियों में बांटा गया है. ये श्रेणियां हैं: सर्वोत्तम, अच्छी, सुधार योग्य और बेहद खराब. सर्वोत्तम के तहत वे सीटें हैं, जहां हमने पिछले चुनाव में जीत भले न हासिल की हो लेकिन पार्टी अगर थोड़ा परिश्रम करे तो जीतने की स्थिति में आ सकती है. अत्यंत खराब श्रेणी में वे सीटें हैं, जहां पार्टी या तो कभी नहीं जीती या फिर बहुत लंबे समय से इन सीटों पर जीत नहीं हासिल कर पाई है. मुश्किल सीटों के जातिगत और सामाजिक समीकरणों को देखते हुए इन पर सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति अपनाई जाएगी. साथ ही इन चुनाव क्षेत्रों के असरदार लोगों का समूह बनाकर उनका ऑनलाइन या ऑफलाइन संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कराने की योजना बनाई गई है. इनमें से कम से कम 40 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली आयोजित कराने की भी योजना है. बाकी सीटों पर या तो शाह की रैली होगी या नड्डा की.''

इन मुश्किल सीटों के चयन के बारे में सीएसडीएस के प्रोफेसर और लोकनीति के सह-निदेशक संजय कुमार कहते हैं, ''भाजपा के लिए चुनौती वाली इन सीटों की सूची में सोनिया गांधी की रायबरेली, कमलनाथ के प्रभुत्व वाली छिंदवाड़ा और शरद पवार के असर वाली बारामती जैसी 20—25 सीटें शामिल हैं. 2019 में भाजपा ने राहुल गांधी की सीट अमेठी से जीत हासिल की थी. ये सिर्फ एक सीट नहीं होती बल्कि इनके जीतने से यह संदेश जाता है कि विपक्षी दलों का एक मजबूत किला ढहा दिया.''

हर सीट पर पार्टी की गतिविधियां सघन तौर पर चल सकें, इसके लिए इन सीटों में से जहां पार्टी कार्यालय का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, उसे जल्द से जल्द पूरा करने की रणनीति बनाई गई है. उल्लेखनीय है कि देश के हर जिले में भाजपा कार्यालय बनाने का काम अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते ही शुरू हुआ था और उसके लिए बाकायदा आठ सदस्यों की एक समिति बनाई थी. पार्टी को उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह काम पूरा कर लिया जाएगा.

पार्टी की व्यापक रणनीति के तहत ही मुश्किल सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों के रात्रि प्रवास कार्यक्रम की योजना भी बनाई है. इस काम में 40 केंद्रीय मंत्री लगाए जाएंगे. हर केंद्रीय मंत्री को 3-4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी जा रही है और उन्हें 'क्लस्टर प्रभारी' बनाया जा रहा है. कर्नाटक और ओडिशा की कुल चार लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी उठा रहे एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बताते हैं, ''पार्टी को लगता है कि अगर केंद्रीय मंत्री खुद आम लोगों के बीच जाकर मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे तो इससे लोगों का विश्वास बढ़ेगा और लोकसभा चुनावों में पार्टी को पहले के मुकाबले बेहतर जनसमर्थन मिल पाएगा.'' मंत्रियों को यह भी हिदायत दी गई है कि योजनाओं के लाभार्थियों से जो फीडबैक मिले उसके आधार पर संबंधित राज्यों के राज्यसभा सांसदों और स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर लोकसभा सीटों के भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक समीकरण पर एक रिपोर्ट तैयार करें. इससे पार्टी इन सीटों के लिए बेहतर रणनीति बना पाएगी.

भाजपा के 160 विस्तारकों की टुकड़ी अगर मकसद में कामयाब रही तो पार्टी की जमीन का विस्तार कर डेढ़ साल बाद अपने साथ कई नए सांसदों के दस्ते लेकर लौटेगी. सचमुच?■

जहांगीर अजीज
चीफ इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिस्ट, जे.पी. मॉर्गन

ऊंची वृद्धि दर हासिल करना आसान न होगा

वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वृद्धि धीमी रहेगी, जिसकी वजह से बार-बार इस ओर ध्यान जाएगा कि क्यों न राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों में ढील दी जाए. पर अच्छा वृहद प्रबंधन वही है जिसमें यह पता हो कि कहां रुक जाना है

भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आम धारणा तो यही है कि रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में रोजमर्रा की चीजों के दाम में उछाल, चीन में आ रही तेज सुस्ती और अमेरिकी फेडरल बैंक की तरफ से आक्रामक मौद्रिक सख्ती सरीखे झंझावातों के बावजूद यह मजबूती से उबर रही है. घरेलू महंगाई अभी भी ज्यादा होने के बावजूद उतार पर है. राजस्व में मजबूत बढ़ोतरी से उत्साहित राजकोषीय घाटा मजबूती की राह पर है और मौद्रिक नीति को ठीक ही कसा गया है. अकेली भौतिक परेशानी चालू खाते के घाटे (सीएडी) में तेज इजाफा है. इसकी वजह है तेल की ऊंची वैश्विक कीमतें और घरेलू मांग में बहाली के चलते गैर-तेल आयात में भारी बढ़ोतरी. रुपए में कमजोरी चालू खाते में भारी घाटे के लिए धन जुटाने की मुश्किल से उपजी है, खासकर जब वैश्विक ब्याज दरें एकदम बहुत बढ़ गई हैं और डॉलर दशकों के सबसे मजबूत स्तर पर है. रुपए में आ रहे तीव्र उतार-चढ़ाव में नरमी लाने की कोशिश में विदेशी मुद्रा भंडार को जमकर खर्च किया गया, बुरा वक्त पीछे छूट चुका है और विदेशी मुद्रा भंडार इतना है कि किसी भी उथल-पुथल से निबट ले.

यहां पेश है एक वैकल्पिक नैरेटिव. इकॉनमिक रिकवरी की रफ्तार तो अच्छी है, फिर भी वह उस 7 फीसद से नीचे बनी हुई है जिसकी ओर महामारी से पहले के वृद्धि के रुझान ने इशारा किया था. अपने आप में यह अपूर्ण है और महामारी से हुआ आर्थिक नुक्सान भारी और स्थायी हो सकता है. ज्यादा मार्के की बात यह है कि अगली दो तिमाहियों के दौरान वृद्धि की रफ्तार बहुत धीमी होनी तय है. सरकार और आरबीआइ इस साल औसतन 6.5-7 फीसद की वृद्धि देख रहे हैं. वित्त वर्ष की पहली दो तिमाहियों में रफ्तार अगर 13.5 फीसद और 6.3 फीसद रही है, तो साल की दूसरी छमाही में वृद्धि को 4-5 फीसद तक धीमा होना चाहिए, तभी 6.5-7 फीसद का औसत आ पाएगा. यह अर्थशास्त्र नहीं, गणित का सितम है!

लिहाजा अगर अगले वित्त वर्ष में वृद्धि 6 फीसद से ऊपर रहने की उम्मीद है, जैसा कि आम राय का सुझाव है, तो इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में इसे मौजूदा दर के मुकाबले 2 फीसद से ज्यादा बढ़ना होगा. वैश्विक वृद्धि इस साल 2.9-3 फीसद की तरफ बढ़ रही है. अगले साल इसके करीब आधा घटकर 1.7 फीसद पर आने के आसार हैं क्योंकि अमेरिका मंदी की तरफ बढ़ रहा है और चीन में बहाली दूसरी छमाही में शुरू होगी. जब वैश्विक अर्थव्यवस्था 1.2 फीसद अंक धीमी पड़ रही हो, ऐसे में भारत से 2 फीसद अंक ज्यादा वृद्धि की उम्मीद करना, बहुत लिहाज से कहें, तो भी चुनौतीपूर्ण होगा. निजी निवेश लगातार सुस्त बना हुआ है और बैंक कर्जों में हालिया बढ़ोतरी काफी हद तक ऊंची महंगाई के कारण है और इसलिए भी कि गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं पूंजी बाजार से धन उगाहने के बजाय बैंकों से उधार लेने की तरफ जा रही हैं. दरअसल कर्ज में बढ़ोतरी और डिजिटलीकरण के विस्तार और वित्तीय समावेशन बढ़ाने की कोशिशों के बाद भी जीडीपी के हिस्से के तौर पर कुल कर्ज (बैंकों और गैर-बैंक का मिलाकर) पिछले दशक के मुकाबले कम है.

मगर ज्यादा परेशान करने वाला अफसाना वह है जो सीएडी के बढ़ने को लेकर है. सीएडी को आयात और निर्यात के बजाय धन जुटाने के स्रोत के तौर पर देखिए. अर्थव्यवस्था के राजकोषीय घाटे की भरपाई या तो स्थानीय नागरिकों या विदेशियों से उधार लेकर की जानी चाहिए. निजी क्षेत्र की बचत का निवेश के मुकाबले ज्यादा होना (बचत-निवेश अंतर) राजकोषीय घाटे का हिस्सा है जिसकी भरपाई स्थानीय लोग करते हैं, और सीएडी वह हिस्सा है जिसकी भरपाई विदेशी करते हैं. इससे फर्क नहीं पड़ता कि सरकार सीधे गैर-बाशिंदों से उधार लेती है या नहीं. मसलन, भारत सरकार ज्यादातर जरूरतों के लिए देश से ही धन जुटाती है पर निजी क्षेत्र को विदेश से उधार लेने को मजबूर करती है. फर्क इससे पड़ता है कि प्रतिस्पर्धी मांगों के लिए धन कैसे जुटाया जाता है.

इस साल का धन जुटाने का गणित कुछ इस तरह है: गिरावट के बाद भी सार्वजनिक क्षेत्र (केंद्र, राज्य और पीएसयू मिलकर) को जीडीपी का 10-10.5 फीसद उधार लेने की जरूरत है, निजी क्षेत्र की अतिरिक्त

लेखकों के पोर्ट्रेटः राज वर्मा

इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

ऐसे समय में जब विश्व अर्थव्यवस्था सुस्त है और अमेरिका मंदी की ओर बढ़ रहा है, तब ग्लोबल मार्केट का रुझान अमूमन यही रहेगा कि वे ज्यादा जोखिम मोल लेने से बचेंगे

बचत (उसकी निवेश जरूरतों में धन लगाने के बाद) जीडीपी का 6.5-7 फीसद है, इतनी कि जीडीपी का 3-3.5 फीसद विदेशों से उधार लेने की जरूरत है, जिसका नतीजा सीएडी है. इसके मुकाबले, महामारी के साल 2020-21 में निजी क्षेत्र की अतिरिक्त बचत जीडीपी की 14-14.5 फीसदी जितनी ज्यादा थी, इतनी कि सार्वजनिक क्षेत्र का घाटा बहुत ज्यादा यानी जीडीपी का 13-13.5 फीसद होने के बावजूद भारत ने उधार लेने के बजाए जीडीपी का करीब 1 फीसद विदेश में निवेश किया, जिसका नतीजा उतनी ही मात्रा में चालू खाते के अधिशेष की शक्ल में सामने आया.

मसले को इस तरह देखने से आप बहसों की पेचीदा सुरंगों में जाने से बच जाते हैं कि निर्यात कम होती मांग के कारण गिरा या गैर-प्रतिस्पर्धी विनिमय दर के कारण; आयात जिंसों की ऊंची कीमतों के कारण बढ़ा या अमीर भारतीयों के विदेशी उपभोक्ता वस्तुओं पर पैसा उड़ाने के कारण; या क्या भारत के बुनियादी ढांचा निर्माण को अब पहले के मुकाबले ज्यादा विदेशी पूंजी साधन चाहिए. इसके बजाए यह समस्या को उसके मूल कारण—यानी भारत में निजी बचत में तीव्र गिरावट—पर केंद्रित करता है. रुपए का कमजोर होना विदेशी निवेशकों के यह कहने का तरीका भर है कि भारत में परिसंपत्तियों (शेयर और बॉन्ड दोनों) की कीमतें बहुत महंगी हैं, इसलिए ज्यादा सस्ती मुद्रा से इसकी भरपाई करने की जरूरत है. जब वैश्विक बाजार सीएडी की भरपाई के लिए पूरा धन नहीं दे रहे, आरबीआइ को देश की सार्वजनिक बचत यानी अपने विदेशी मुद्रा भंडार से निकालना होगा.

निजी बचत में गिरावट की क्या वजह है? अनेक वजहें हैं, पर घर-परिवारों और एसएमई की आमदनी में साफ कमी मुख्य कारण है. यह रुझान अगले साल भी उलटने के आसार नहीं हैं, इस हद तक कि सरकार को अगले साल के घाटे में अच्छी-खासी कमी लानी होगी. अगर वह ऐसा नहीं करती, तो सीएडी और भी बढ़ जाएगा. ऐसी दुनिया में जहां वैश्विक वित्तीय परिस्थितियां इतनी ही सख्त बनी रहेंगी या और ज्यादा सख्त होंगी (जो इस पर निर्भर करता है कि अमेरिका अपनी नीतिगत दरों को कहां ले जाता है), भारत के लिए अपनी विनिमय दर या शेयर तथा बॉन्ड के मूल्य निर्धारणों को काफी हद तक सस्ता किए बगैर ज्यादा बड़े सीएडी के खातिर धन जुटा पाना बहुत मुश्किल होगा (बॉन्ड के लिए इसका अर्थ बहुत ज्यादा प्रतिफल और नीतिगत दर होगा).

विदेशी उधारी (और महंगाई) को काबू में रखने और वित्तीय स्थिरता की हिफाजत के लिए सख्त बजट, ऊंची ब्याज दरों, कम निवेश और धीमी वृद्धि की जरूरत होगी. विश्व अर्थव्यवस्था के सुस्त पड़ने और अमेरिका के मंदी की तरफ बढ़ने के बीच वैश्विक बाजार ज्यादा से ज्यादा जोखिम से बचने का रुख करेंगे.

इन चुनौतियों से पार पाने का समझदार तरीका अपनी जमीन पर पैर टिकाए रखकर झंझावातों का सामना करना है. वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वृद्धि धीमी होगी और जवाब में राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों में ढील देने का प्रलोभन काफी ज्यादा होगा. मगर बच्चों की परवरिश की तरह अच्छे वृहद प्रबंधन का तकाजा यही है कि उसे पता हो कि कब नहीं कहना है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

संदीप वास्लेकर
प्रेसीडेंट, स्ट्रैटजिक फोरसाइट ग्रुप

क्या भारत विश्वगुरू बन सकता है?

युद्ध और शांति राजनैतिक विकल्पों से निकलते हैं. यूक्रेन की जंग आहिस्ता-आहिस्ता साल पूरा करने की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में पेश हैं इसकी भावी दिशा-दशा के तीन संभावित परिदृश्य

साल 2023 का एक अहम सवाल यह है कि **यूक्रेन** की जंग इस साल खत्म होगी या नहीं. इस जंग से बचा जा सकता था. जब 1994 से 2004 के दरमियान लिओनिड कुचमा यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, उन्होंने रूस और पश्चिम के साथ रिश्तों में संतुलन बनाकर रखा. उनके बाद 2005 से 2010 तक राष्ट्रपति रहे विक्टर यानुकोविच ने यूक्रेन को पश्चिमी खेमे में धकेल दिया. उनके उत्तराधिकारी विक्टर यानुकोविच ने तराजू का दूसरा पलड़ा चुना और भालू को गले लगाया. अगर यूक्रेन ने संवैधानिक तटस्थता का ऐलान किया होता, तो रूस 2014 में क्रीमिया को नहीं हड़पता और अगर यूक्रेन ने डोनबास पर मिंस्क-2 समझौते को लागू किया होता तो रूस 2022 में यूक्रेन पर हमला नहीं करता. तटस्थता को खारिज करने की यूक्रेन की राजनैतिक नासमझी रूस को अंतरराष्ट्रीय कानूनों और यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता की गारंटी देने वाले 1994 के समझौते का उल्लंघन करने के अपराध से बरी करने का बहाना नहीं है. यूक्रेन का युद्ध दिखाता है कि युद्ध विकल्प का मामला है. युद्ध महज भूगोल, अर्थव्यवस्था या नियति की वजह से नहीं होता. युद्ध नेताओं की तरफ से चुने गए विकल्पों की वजह से होता है.

अगर युद्ध विकल्प का मामला है, तो विकल्पों का मामला तो शांति भी हो सकती है. यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिली ने यूक्रेन को बातचीत से व्यावाहारिक समाधान निकालने की सलाह दी थी. यूक्रेन के नेताओं ने उन्माद भरे ढंग से जवाब दिया, ठीक उसी तरह जैसा उन्होंने तब किया था जब 2013 में हेनरी किसिंजर ने संवैधानिक तटस्थता की सिफारिश की थी. पेंटागन के शीर्ष आका की समझदारी भरी बात के बावजूद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूक्रेन को हथियार की आपूर्ति कर रहा है. इसके नतीजतन यूक्रेन में भविष्य के युद्ध के तीन संभावित परिदृश्य उभरते हैं.

परिदृश्य 1: युद्धविराम और शांति प्रक्रिया

अगर रूस और यूक्रेन परस्पर सुनिश्चित विनाश से बचना चाहते हैं, तो वे युद्धविराम और उसके बाद शांति प्रक्रिया की संभावनाएं टटोल सकते हैं. शांति प्रक्रिया के लिए अग्रमोर्चों से भारी हथियार वापस लेने होंगे, कैदियों की अदला-बदली करनी होगी, संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में विसैन्यीकृत क्षेत्र बनाना होगा, और यूक्रेन की तरफ से डोनबास की स्वायत्तता की खातिर मिंस्क-2 के प्रावधानों को लागू करने के बदले रूसी सेना की वापसी के लिए बातचीत शुरू करनी होगी.

सवाल यह है कि गतिरोध कौन तोड़ेगा. पी5 सदस्य देशों के बीच संवाद पूरी तरह टूट चुका है. पी5 के जेनेवा और न्यूयॉर्क स्थित राजदूतों के बीच अनौपचारिक बातचीत स्थगित है. अमेरिका-रूस के बीच सामरिक स्थिरता को लेकर चल रही बातचीत रोक दी गई है. जी20 की अध्यक्षता को नैतिक नेतृत्व के रूप में ग्रहण करते हुए भारत इस शून्य को भर सकता है. मॉस्को, वाशिंगटन डी.सी., पेरिस और बर्लिन में भारत के पास राजनैतिक साख है. भारत अकेले अपने दम पर काम करते हुए शायद पिछले दरवाजे से मध्यस्थता की आक्रामक पहल शुरू कर सकता है. विकल्प के तौर पर भारत मध्यस्थ देशों का एक नया और ऊर्जावान समूह बना सकता है और उसकी अगुआई कर सकता है. अगर भारत कामयाब होता है, तो वह अपनी 'विश्वगुरु' की हैसियत स्थापित करेगा और यूएनएससी के स्थायी सदस्यों में खुद को शामिल किए जाने का रास्ता आसान बनाएगा.

अगर सितंबर 2023 तक युद्धविराम नहीं होता, तो भारत को जी20 शिखर सम्मेलन में जबरदस्त कूटनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. राष्ट्रपति पुतिन शायद मौजूद न हों, वैसे ही जैसे नवंबर 2022 में पिछले शिखर सम्मेलन के लिए वे बाली में मौजूद नहीं थे. अगर वे शिखर सम्मेलन में शामिल होते हैं और पश्चिमी नेता भारतीय भूमि पर उन्हें अपमानित करते हैं, तो यह मेजबान देश के लिए बड़ी शर्मिंदगी का सबब होगा. भारत को मध्यस्थता के लिए सितंबर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है. जनवरी से मार्च तक सर्दियों के महीनों में युद्ध की रफ्तार ढीली पड़ जाएगी. कूटनीतिक पहल छेड़ने का वक्त अभी ही है.

परिदृश्य 2: लंबा खिंचता टकराव

अगर इस साल सितंबर तक युद्धविराम नहीं होता, तो पुतिन टकराव को जनवरी 2025 तक खींचना चाहेंगे, जब अमेरिका में नए

जी20 की अध्यक्षता करते हुए अगर भारत रूस और यूक्रेन के बीच **मध्यस्थता करते हुए युद्ध विराम करवाने में कामयाब हो जाता है तो वह विश्वगुरु की अपनी हैसियत स्थापित करेगा**

इलस्ट्रेशनः **नीलांजन दास**

राष्ट्रपति सत्तारूढ़ होंगे. इस बीच दुनिया खाद्य पदार्थों, उर्वरकों और ईंधन की कमी झेलेगी. श्रीलंका की घटनाएं, जहां खाद्य पदार्थों, उर्वरकों और ईंधन की अचानक कमी की वजह से गोटाबाया राजपक्षे की सरकार को उखाड़ फेंका गया, दुनिया के कुछ हिस्सों में फिर दोहराई जाएंगी.

अमेरिका का नया राष्ट्रपति अगर रूस के साथ समझौता करना चाहेगा, तो वह यूक्रेन को युद्धविराम और उसके बाद शांति प्रक्रिया मंजूर करने के लिए आसानी से मजबूर कर सकेगा. अगर 2025 का व्हाइट हाउस युद्ध के जारी रहने में अमेरिका के रणनीतिक, राजनैतिक और सैन्य हित देखेगा, तो युद्ध 2020 के दशक के अंतिम सालों के आगे भी खिंचेगा. वियतनाम का युद्ध करीब दो दशक चला था, जबकि इराक-ईरान युद्ध और अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण करीब एक दशक चला. यूक्रेन में 2020 के दशक से आगे भी लंबा युद्ध चलते देखना मुमकिन है, जब तक कि दोनों पक्षों के पास खोने को और ज्यादा न हो और दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाने वाले गतिरोध में उलझे हों. दूसरे देशों की तरह भारत भी आर्थिक नतीजों से बच नहीं पाएगा.

परिदृश्य 3: वैश्विक परमाणु युद्ध

लंबी खिंचती लड़ाई किसी ऐसी दुर्घटना या घटना को जन्म दे सकती है जो अनजाने या जानबूझकर परमाणु हमले और पलट हमले की तरफ ले जाए. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जनरल एंतोनियो गुटेरेस ने एकाधिक मौकों पर आगाह किया है कि मानवता परमाणु सर्वनाश से बस एक गलती भर दूर है.

यूएनएससी के पांच स्थायी सदस्यों ने जनवरी 2022 में परमाणु युद्ध से बचने के संयुक्त संकल्प का ऐलान किया था. हालांकि उनकी कथनी उनकी करनी से मेल नहीं खाती. अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस 'पहले इस्तेमाल नहीं' का सिद्धांत स्वीकार करने से इनकार करते हैं. रूस और अमेरिका ने 2,800 परमाणु वॉरहेड 'हेयर-ट्रिगर एलर्ट' पर रख रखे हैं, जो कार्यपालिका के फैसले के 10-15 मिनट के भीतर अपने निशानों पर हमला करने के लिए तैयार हैं. दोनों देश, और साथ में चीन भी, ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलों की दौड़ में शामिल हैं जो ध्वनि की रफ्तार से 27 गुना तेज चलती हैं, राडार से बच निकलती हैं और दो टन परमाणु विस्फोटक ले जा सकती हैं. इसकी दूरी के दायरे में अमेरिकी भूमि है; यूक्रेन नहीं. वैश्विक परमाण युद्ध, जो रूस और नाटो देशों की शिरकत से शुरू हो और फिर चीन और भारत को भी अपनी चपेट में ले ले, दुर्घटनावश, घटनावश या इरादतन मुमकिन है.

चूंकि भारत ऐसे युद्ध का अनिच्छुक शिकार होगा, इसलिए साउथ ब्लॉक के आला अफसरशाहों को परमाणु जोखिम कम करने और वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए कूटनीतिक पहल पर विचार करने की जरूरत है. ऐसी पहल बहुपक्षीय होनी चाहिए, चूंकि एकपक्षीय उदारता का कोई फायदा नहीं, जैसा कि यूक्रेन के उदाहरण से ही साबित हो चुका है. सबसे घातक हथियारों का परित्याग परमाणु हथियार संपन्न देशों के लिए खुशगवार विकल्प नहीं है. इसका विकल्प मानव सभ्यता का अंत है. ■

शिवशंकर मेनन
पूर्व विदेश सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

तीन चुनौतियां और अवसर एक

परिवर्तनकाल से गुजर रही दुनिया में, भारत के पास मौका है कि वह पिछले साल की तुलना में इस साल विश्व व्यवस्था को अपनी आकांक्षाओं के मुताबिक अधिक अनुकूल आकार दे

वर्ष 2022 हमें एक लड़खड़ाती हुई विश्व अर्थव्यवस्था, यूक्रेन में एक अंतहीन युद्ध, चीन में कोविड संक्रमणों की सूनामी, हर जगह बड़े पैमाने पर राष्ट्रवाद, अनेक स्थानों पर उभरते भू-राजनीतिक संकटों और दूसरी तरफ सकारात्मक परिवर्तन के गिने-चुने दृश्यों के साथ छोड़कर गया है. चीन-अमेरिका का सामरिक विवाद भी हमारे आसपास के क्षेत्र में बढ़ रहा है. इस स्थिति में भारत के सामने चुनौतियों का अंबार है. बड़ी शक्तियों की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के साये में जो वैश्विक वातावरण बना है आवश्यक रूप से भारत के कायापलट के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसमें बाहरी वचनबद्धताओं की आवश्यकता होगी. फिर भी महान शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता की इस दुनिया में भारत के लिए अवसर बन सकते हैं, यदि हम तीन मूलभूत चुनौतियों को सफलतापूर्वक संभाल सकें.

तीन चुनौतियां

बाहरी चुनौतियों में सबसे प्रमुख है चीन और वह भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है. वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर 2020 में हमने जो देखा, वह चीन द्वारा एलएसी का एक पूर्व-निर्धारित अतिक्रमण था और समझौतों और प्रचलित व्यवस्था के इस पूर्ण उल्लंघन ने यथास्थिति को बदल दिया. एलएसी अब गर्म है, और पूरे एलएसी पर तैनात दोनों पक्षों के 1,00,000 से अधिक सैनिक टकराव की स्थिति में हैं. आगे की घुसपैठ और अतिक्रमण को रोकने के लिए, पहला काम उपायों और कार्यों के संयोजन से एलएसी पर प्रभावी प्रतिरोध बनाना होगा. साथ ही, भारत और चीन आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं. सीमा पर तनातनी की घटनाओं के वर्ष में भी चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक

इलस्ट्रेशनः सिद्धांत जुमडे

भागीदार के रूप में उभर रहा है. चीन कई अन्य वजहों से भी भारत के लिए बहुत अहमियत रखता है. इसलिए रिश्तों को सुधारने के प्रयास गंभीरता से किए जाने चाहिए लेकिन यह एक ऐसा कार्य है जिसे दोनों पक्षों के बीच उच्च-स्तरीय राजनीतिक जुड़ाव के बिना नहीं किया जा सकता और तीन साल से अधिक समय से यह हुआ नहीं है.

दूसरी, एक नई एशियाई और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बनने की प्रक्रिया में है और कोविड महामारी तथा यूक्रेन में युद्ध ने इसे गति दी है. आसियान देशों के बीच की क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी या आरसीईपी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र बनाती है लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है. चीन अब अफगानिस्तान और भूटान को छोड़कर सभी एशियाई देशों का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई), एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) तथा अन्य पहलों द्वारा चीन-केंद्रित भौतिक, डिजिटल और वित्तीय संपर्क के नए अवसर बनाए जा रहे हैं. वैश्विक विनिर्माण मूल्य और आपूर्ति शृंखलाएं जिन्होंने वैश्वीकरण के दशकों के दौरान तेज विकास में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, लगभग पांच वर्षों से कम होती जा रही हैं. चीन और अमेरिका इसे सतह पर लेकर आ गए हैं, और जलवायु परिवर्तन तथा अन्य बहानों के नाम पर संरक्षणवाद को बढ़ावा मिल रहा है. यदि भारत को इस सदी के पहले दशक के उच्च विकास पथ पर वापस लौटना है, तो हमें आरसीईपी और भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचे (आईपीईएफ) के व्यापार चरण से दूर जाने के बजाय वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपना जुड़ाव बढ़ाने की आवश्यकता है.

तीसरी चुनौती अधिक कठिन अंतरराष्ट्रीय हालात से सफलतापूर्वक निपटने के लिए सुसंगतता और सामंजस्य बनाने की है जो आंशिक रूप से एक घरेलू चुनौती है. इतिहास की सभी सफल उदीयमान शक्तियों ने सही समय की प्रतीक्षा की है और तब तक मौजूदा व्यवस्था के साथ काम किया है. अपने उदय के लिए समर्थन हासिल करने और व्याख्या करने के लिए आंतरिक और बाहरी रूप से एक प्रेरक कथा का निर्माण किया है.

आज, हम कई खेमों में बंटी दुनिया में हैं, और भारत पूर्वी चीन सागर से ताइवान, दक्षिण चीन सागर से भारत-चीन सीमा, यमन और इसी तरह के एशिया में कई समुद्री भू-राजनीतिक तनाव क्षेत्रों से घिरा हुआ है. यह भारत की भू-राजनीतिक स्थिति और विकल्पों को कठिन बनाता है.

चार अवसर

इन सबके बावजूद परिवर्तन काल और संकट, अपने साथ अवसर भी लेकर आते हैं. फिलहाल उन कार्यों को पूरा करने का मौका है जिन्हें जरूरी माना जाता है लेकिन सामान्य समय के दौरान करना कठिन होता है, जैसा कि हमने 1991 में सुधारों के साथ देखा था.

विभिन्न व्यवस्थाओं में बंटी दुनिया ऐसी दुनिया है जहां अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के बीच से एक नई व्यवस्था बनेगी. यह भारत जैसे देशों के लिए एक ऐसी व्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करने का एक अवसर है जो हमारी आकांक्षाओं के लिए पिछली की तुलना में अधिक अनुकूल है, विशेष रूप से साइबर स्पेस जैसे नए डोमेन में.

तथ्य यह है कि चीन-अमेरिका प्रतिद्वंद्विता के लंबे समय तक कायम रहने की संभावना है और यहीं पर अन्य शक्तियों के सामने भू-राजनीतिक संतुलन के लिए अवसर बनता है. हमने देखा है कि कैसे बड़ी संख्या में देश यूक्रेन संकट पर दोनों में से किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने में झिझकते दिखे और एक तीसरा रास्ता तलाश रहे थे. हम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा के बीच एक सुरक्षित रास्ता तैयार करते भी देख रहे हैं, जिनमें से अधिकांश चीन से आर्थिक रूप से लाभान्वित हो रहे हैं लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर भरोसा करते हैं.

> चीन-अमेरिका प्रतिद्वंद्विता के लंबे समय तक कायम रहने की संभावना है और यहीं पर अन्य शक्तियों के सामने **भू-राजनीतिक संतुलन के लिए अवसर बनता है. ऐसे में भारत के साथ अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ बने रहेंगे**

महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता की दुनिया का एक लाभार्थी अमेरिका के साथ भारत का संबंध है. अमेरिका अब भारत को अलग तरह से देखता है. भारत के लिए, अमेरिका परिवर्तन का एक आवश्यक भागीदार है, न कि केवल एक ऐसी महाशक्ति जो चीन को लेकर हमारी कुछ चिंताओं को साझा करता है. दोनों देशों के बीच बढ़ता सामरिक सामंजस्य रक्षा और समुद्री सुरक्षा, राजनीति और क्वाड, आईपीईएफ (भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा) और अन्य नए गठनों में गहराते संबंधों में परिलक्षित होता है. बढ़ता सामंजस्य इशारा देता है कि यह साझेदारी 2023 में बढ़ेगी.

एक और अवसर तो उपमहाद्वीप में ही बन रहा है. भारत के पास भुगतान प्रणाली और कनेक्टिविटी जैसे आर्थिक साधनों को स्थापित करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ काम करने का अवसर है जो हमारे कुछ पड़ोसियों के आर्थिक और राजनीतिक संकट को दूर करने में मदद कर सकता है. वैसे संकट, जिससे फिलहाल उपमहाद्वीप के तीन देश जूझ रहे हैं और उनकी सरकारों ने आईएमएफ से मदद के लिए संपर्क किया है और पिछले डेढ़ साल में पांच सरकारें बदली हैं, के बीच हमारे लिए उन चीजों को करने का मौका बनता है जिसे हम सभी समझते हैं कि यह एक जरूरत है लेकिन घरेलू राजनीति सामान्य समय में इसकी अनुमति नहीं देती है.

दूसरा अवसर एक नया एशियाई राजनीतिक संतुलन बनाने के लिए काम करना है जो वैश्विक दक्षिण की चिंताओं के अधिक अनुकूल हो. हम पहले से ही एशिया के समुद्र में कई ऐसे तरीकों से सहयोग कर रहे हैं जो दो दशक पहले अकल्पनीय थे. हमें जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे देशों और हिंद-प्रशांत में अन्य देशों के साथ अपने काम का विस्तार करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एशिया खुला, बहुलतावादी और समावेशी बना रहे, जैसा कि वह अपने पूरे इतिहास में रहा है.

इस प्रकार, 2023 के लिए हमें कुछ भू-राजनीतिक पूर्वानुमान भले ही धूमिल नजर आ सकते हैं लेकिन भारत ने इससे पहले भी बदतर स्थिति का सामना किया है और संकट को अवसर में बदलकर रचनात्मक प्रतिक्रिया दी है. इसके लिए नई नीतियों और अलग नजरिए की जरूरत होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि भारत इसे फिर से कर सकता है. ■

जयदेव रानाडे
अध्यक्ष, सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस ऐंड स्टडीज

और मजबूत होगी दुश्मनी की चीनी दीवार

भारत को लगातार बढ़ती चीन की शत्रुता का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए. तथ्यों की मानें तो शी जिनपिंग का फैसला साफ है, वे भारत के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखने वाले हैं

शिक आर्थिक मंदी के बाद के दशक में विश्व व्यवस्था धीरे-धीरे बदलाव के दौर से गुजर रही है. भारत और जापान जैसी उभरती शक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र सहित दूसरे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अपना पूरा हिस्सा मांगना शुरू कर दिया है. हालांकि यह प्रक्रिया दो बड़े घटनाक्रमों से बुरी तरह से बाधित भी हुई—पहली कोविड महामारी और दूसरी फरवरी 2022 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पर आक्रमण कर एकतरफा रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को बदलने का प्रयास. 4 फरवरी को अपने सहयोगी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर सम्मेलन के बाद पुतिन का हौसला बढ़ा. चीन से मौन समर्थन का आश्वासन मिलने पर रूस ने अपनी सेना को चीन की सीमा से हटाकर यूक्रेनी मोर्चे पर तैनात कर दिया.

पुतिन और शी दोनों एक नई विश्व व्यवस्था के उदय को देखने के इच्छुक हैं. चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने शी जिनपिंग के हवाले से कहा कि ''चीन और रूस रणनीतिक सहयोग मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं.'' उन्होंने कहा कि यह ''एक रणनीतिक निर्णय है जिसके परिणाम चीन, रूस और दुनिया के लिए दूरगामी होंगे, और वे इस निर्णय से पीछे नहीं हटेंगे.''

यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध ने चीन के इरादों को और भी स्पष्ट कर दिया है. बीजिंग लंबे समय से अमेरिका के बराबर की शक्ति के रूप में पहचाने जाने की मांग कर रहा था. इसने दोनों शक्तियों के वैश्विक विवादों का साझा मध्यस्थ बनने के ''एक नए प्रकार के महान शक्ति संबंध'' का प्रस्ताव दिया था, हालांकि वह नाकाम रहा. शी के नेतृत्व में चीन ने अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाएं खुले तौर पर जाहिर कर दी हैं. शी ने चीन के सशस्त्र बलों का तेजी से आधुनिकीकरण किया और 2012 और 2017 में लगातार दो बार पार्टी कांग्रेस में चीन के दो प्रमुख लक्ष्यों को स्पष्ट किया—अमेरिका को पीछे छोड़ना और देश की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ यानी 2049 तक चीनी राष्ट्र का कायाकल्प. अपने दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चीन उन क्षेत्रों को फिर से अपने अधिकार में करेगा जिन्हें लेकर उसका दावा है कि चीन ने अपने ये क्षेत्र ''शत्रुतापूर्ण विदेशी शक्तियों द्वारा गैर-बराबरी वाली संधियों को लागू करने'' के कारण गंवाए हैं. 2013 में शी ने बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया. यह एक व्यापक भू-आर्थिक रणनीतिक पहल है जिसे चीन समुद्री और डिजिटल सिल्क रोड के माध्यम से बढ़ा रहा है. इसे चीन निर्मित संचार नेटवर्क के बहाने पूरी दुनिया में चीन की शक्ति के विस्तार के प्रयास के रूप में देखा गया. लेकिन महाशक्ति बनने से पहले चीन को हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर हावी होना होगा, जहां भारत सबसे बड़ी शक्ति है.

चीन के विस्तारवादी एजेंडे और आक्रामक विदेश नीति का सीधा असर भारत पर पड़ता है. संप्रभु भारत के लद्दाख, कश्मीर के कुछ हिस्से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बड़े हिस्से और लगभग पूरे अरुणाचल प्रदेश को चीन के आधिकारिक मानचित्र पर चीन के भूभाग के रूप में दर्शाया जाता है. चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग 90 प्रतिशत हिस्से पर भी दावा जताता है. उसने वियतनाम, जापान और फिलीपींस जैसे कई पड़ोसियों के क्षेत्रों का अतिक्रमण किया है और ताइवान को फिर से चीन के साथ

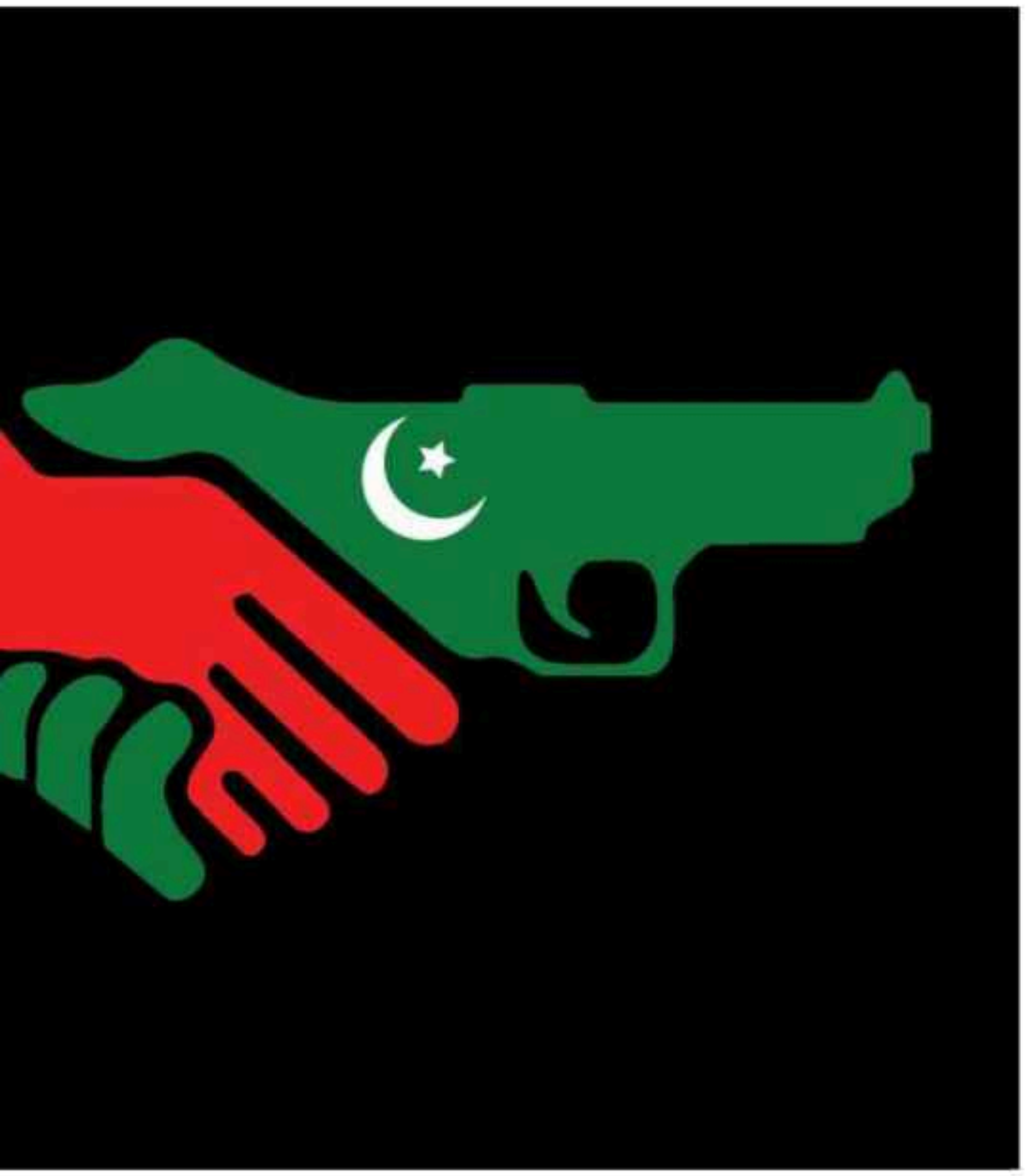

इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

2022 में 20वीं पार्टी कांग्रेस में जिनपिंग भारत की ऐसी नकारात्मक छवि पेश करने में कामयाब रहे जिसका असर लंबे समय तक रहने वाला है

शीघ्र मिलाने पर जोर दे रहा है.

अप्रैल 2015 में घोषित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी), कश्मीर, गिलगित और बल्तिस्तान पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे का समर्थन करता है. 2016 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की वेस्टर्न थिएटर कमान का निर्माण, जो चीन के पांच सैन्य थिएटर कमानों में से सबसे बड़ा है, संभावित रूप से चीन और पाकिस्तान की सैन्य ताकत को एकजुट करता है. पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) इसी कमान के अधिकारक्षेत्र में है और सीपीईसी में तैनात चीनी संपत्तियों और कर्मियों के लिए जिम्मेदार है. एक-दूसरे के सैन्य संचालन निदेशालयों में वरिष्ठ पाकिस्तानी और चीनी सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी से चीन-पाकिस्तान की मिलीभगत और स्पष्ट रूप से रेखांकित होती है. सीपीईसी के ऐलान के तुरंत बाद चीन ने अपनी रणनीतिक सोच में पाकिस्तान के महत्व का स्पष्ट संकेत दिया जब चीनी नेताओं ने भारतीय वार्ताकारों को बताया कि ''भारत को पाकिस्तान के साथ तनाव कम करना चाहिए और बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए, कश्मीर मुद्दे को हल करना चाहिए और उसके बाद चीन के साथ बेहतर संबंधों के लिए प्रयास करने चाहिए.''

अप्रैल 2020 से, जब चीन ने सभी समझौतों और संधियों का उल्लंघन करते हुए लद्दाख में घुसपैठ की, पूरी 4,057 किलोमीटर लंबी एलएसी सक्रिय हो गई है और कड़ाके की सर्दी में भी दोनों सेनाएं मुस्तैदी से तैनात हैं. पीएलए ने तिब्बत में अपने सैन्य और वायु सेना के अभ्यास को बढ़ाया है और हवाई अड्डों, रणनीतिक राजमार्गों और रेलवे सहित तिब्बत को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले बुनियादी ढांचे का तेजी से निर्माण किया है. शी ने कम से कम तीन मौकों पर वेस्टर्न थिएटर कमान का दौरा किया, जिसका संदेश साफ है. फिर भी न तो उन्होंने और न ही विदेश मंत्री वांग यी (जिन्हें अब केंद्रीय विदेश मामलों के आयोग का निदेशक नियुक्त किया गया है) के अलावा किसी अन्य वरिष्ठ नेता ने सीमा की स्थिति पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की. इससे साफ है कि संबंधों को सुधारने में उनकी कोई रुचि नहीं है. चीन भारत के साथ लंबे समय तक तनावपूर्ण संबंधों के लिए तैयार दिखाई देता है.

बीसवीं पार्टी कांग्रेस में पेश और अगले पांच वर्षों के लिए चीन की रणनीतिक दिशा तय करने वाली शी की कार्य रिपोर्ट से यह झलकता है कि भारत के प्रति चीन की सख्त मुद्रा में कोई बदलाव नहीं आने वाला. इसने उन रिपोर्टों की पुष्टि की कि चीन अपने परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि कर रहा है और पीएलए स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स और पीएलए रॉकेट फोर्स को बड़ा करने की योजना बना रहा है. सैन्य प्रशिक्षण और तैनाती पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, ''यह हमें सुरक्षा को लेकर अपने रुख को आकार देने, संकटों और संघर्षों को रोकने तथा मैनेज करने और स्थानीय युद्धों को जीतने में सक्षम बनाएगा.'' पिछली कार्य रिपोर्टों में 'स्थानीय युद्धों' का उल्लेख नहीं किया गया था. यह बदलाव मुख्य रूप से भारत के साथ संघर्षों को रेखांकित करता है. चीन पहले से ही भारत की सीमाओं पर सुरक्षा रुख को ''आकार देने'' का प्रयास कर रहा है. इसके अलावा, चीन के नए केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) के सात सदस्यों में से चार के पास वेस्टर्न थिएटर कमान का अनुभव है, जो चीन के लिए एलएसी के महत्व को दर्शाता है. भारत के लिए, इसका अर्थ है नए सिरे से सैन्य तैनाती और सीमाओं पर बढ़ते दबाव के अलावा आगे भी चीन के साथ झड़पों की अधिक संभावना. 9 दिसंबर को तवांग के पास यांग्त्से में 300 पीएलए सैनिकों का 17,500 फुट ऊंची रिज लाइन पर कब्जा करने का प्रयास इसकी मिसाल है.

पिछले अक्तूबर में बीजिंग की 20वीं पार्टी कांग्रेस में भारत को लेकर विशेष रूप से नकारात्मक चर्चा हुई जो बहुत असामान्य है और इसने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया. पार्टी कांग्रेस किसी देश का नाम लेने से बचती है, लेकिन इस बार शी ने भारत के लिए नकारात्मक रुख सुनिश्चित किया. जून 2020 में गलवान में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़पों की एक वीडियो क्लिप को बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल में इकट्ठे हुए लगभग 5,000 प्रतिनिधियों, विशेष आमंत्रितों और अधिकारियों को उद्घाटन वाले दिन दिखाया गया था.

बदलती विश्व व्यवस्था में बड़ी ताकतें किस पक्ष के साथ खड़ी होती हैं, यह भारत के लिए एक चुनौती होगी. चीन एक दीर्घकालिक समस्या बना रहेगा. नए सीएमसी की संरचना, गलवान झड़प का वीडियो दिखाया जाना, और तिब्बत में रक्षा बुनियादी ढांचे का तेजी से निर्माण, ये सारी बातें इशारा देती हैं कि शी जिनपिंग के दिमाग में कुछ तैयारियां चल रही हैं और वे संभवत: अगले एक या दो साल में भारत के खिलाफ सैन्य अभियानों की योजना बना रहे हैं. शी का रणनीतिक आकलन गलत है या सही, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है. ■

तीसरा ध्रुव बनने का इससे अच्छा मौका नहीं

किशोर महबूबानी
मानद फेलो, एशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर

एकध्रुवीय दुनिया के दिन लद गए, अब हम सही मायने में बहुध्रुवीय दुनिया की दहलीज पर खड़े हैं. ऐसे परिवेश में दुनिया की इकलौती स्वतंत्र ताकत के नाते भारत 'तीसरा ध्रुव' बनने की अनूठी स्थिति में

पहले साल पहले मिली आजादी के बाद भारत आज भू-राजनैतिक दृष्टि से अब तक की सबसे सुखद स्थिति में है. यह स्थिति है क्या? यह भारत के लिए खुद को दुनिया की इकलौती स्वतंत्र महाशक्ति के तौर पर पेश करने का मौका है.

यह स्थिति कैसे बनी है? इसका सरल जवाब यह है कि दुनिया आज मानव इतिहास के सबसे बड़े भू-राजनैतिक बदलाव के मुहाने पर है. हम एकध्रुवीय विश्व-व्यवस्था से एक बहुध्रुवीय, बहु-सभ्यता वाली व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं. भू-राजनैतिक बदलाव नए अवसर लाया है, लेकिन इसके अपने खतरे भी हैं.

बेशक, यह भारी व्यवस्थागत बदलाव चीन के दोबारा उभार की वजह से हुआ है. यह बदलाव काफी स्वाभाविक है. वर्ष 1 से लेकर 1820 तक चीन और भारत दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं रही हैं. अब आखिर पिछले 200 साल के पश्चिमी दबदबे के अपवाद का अंत हो रहा है. चीन, भारत और अधिकांश एशिया की इस परिदृश्य में वापसी पश्चिमी विचारों और पद्धतियों की वजह से हुई है, पश्चिम को इसका स्वागत करना चाहिए. हालांकि पश्चिम इसे सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है मगर व्यवहार में नहीं.

मानव इतिहास की दूसरी महाशक्तियों की तरह ही अमेरिका भी दुनिया में अपनी नंबर एक की हैसियत बरकरार रखने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहा है. अलबत्ता अमेरिका इनकार करता है कि उसने चीन के खिलाफ 'अंकुश लगाने' की नीति का दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन *फाइनेंशियल टाइम्स* के एडवर्ड लुके और यूरेशिया ग्रुप के इयान ब्रेमर जैसे अनुभवी और प्रतिष्ठित पश्चिमी जानकारों ने पुष्टि की है कि 'अंकुश लगाया जाना' शुरू हो चुका है. तत्कालीन सोवियत संघ (यूएसएसआर) के खिलाफ प्रथम शीत युद्ध में भारत ने खुद को 'गलत पक्ष' में पाया और उसकी कीमत चुकाई. आज कुछ भारतीय जानकारों का मानना है कि भारत अब 'सही पक्ष' के साथ है. इसलिए, रणनीतिक सोच-समझ वाली भारतीय बिरादरी में एक मजबूत और ताकतवर तबका तैयार हुआ है, जो यह तर्क दे रहा है कि भारत को अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए और ब्रिक्स के बजाय क्वाड को भारतीय विदेश नीति का मुख्य स्तंभ बनाना चाहिए.

चीन पर बनते अमेरिकी भू-राजनैतिक दबाव का फायदा उठाने का प्रलोभन समझ में आता है. यह आसान विकल्प मालूम होता है, जिसकी कोई खास कीमत नहीं चुकानी. हालांकि, अमेरिका का प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोगी बनने के नफे-नुक्सान का वस्तुपरक आकलन करें तो यह साफ दिखाई देगा कि ऐसा करके भारत वैश्विक व्यवस्था में एक स्वतंत्र तीसरा ध्रुव बनने का बड़ा भू-राजनैतिक अवसर खो देगा. और दुनिया को एक स्वतंत्र तीसरे ध्रुव की जरूरत है.

जरा अफ्रीका के 54 देशों की स्थिति पर गौर फरमाइए. 14 दिसंबर, 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ व्हाइट हाउस की बैठक में शामिल होने वाले अफ्रीकी नेताओं में से कई इस खुशामदी निमंत्रण से जरूर खुश हुए होंगे. लेकिन यह सोचना कि अब अमेरिका

अफ्रीका की आंतरिक समृद्धि और सुंदरता को पहचान रहा है, खुद को धोखा देने जैसा है. अफ्रीका के अधिकांश नेता इतने समझदार हैं कि वे समझते हैं कि व्हाइट हाउस का यह निमंत्रण इसलिए आया क्योंकि चीन बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआइ) के जरिए अफ्रीकी देशों में पैठ बढ़ा रहा है. अगर अमेरिका अपने व्यापार और प्रौद्योगिकी युद्ध के जरिए चीन की अफ्रीका में बढ़त रोकने में कामयाब हो जाता है तो अमेरिका अफ्रीका के साथ वही करेगा जो उसने प्रथम शीत युद्ध के बाद किया.

हां, भू-राजनीति निहायत निर्मम होती है. पिछले 2000 साल यही बताते हैं. दूसरे विकासशील देशों की तरह अफ्रीकी देश अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाले दशक में अमेरिका और चीन की भू-राजनैतिक होड़ तीखी होती जाएगी और उन्हें कठिन विकल्प चुनने होंगे. किसी एक पक्ष की ओर झुकने और कुछ विकल्पों को छोड़ने के लिए मजबूर होने से बेहतर वे तीसरे रास्ते के रूप में एक स्वतंत्र ध्रुव की ओर जाना चाहेंगे. अगर एक भरोसेमंद स्वतंत्र ध्रुव उनके लिए मिसाल बनता है तो उनके लिए अमेरिका और चीन के दबाव को अनदेखा करना और बीच का रास्ता अपनाना आसान हो जाएगा.

हाल का इतिहास बताता है कि दुनिया स्वतंत्र शक्तियों का सम्मान करती है. दिवंगत पियरे ट्रुडो के नेतृत्व में कनाडा अमेरिका का सहयोगी बना रहा, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसने वाशिंगटन को दो-टूक सलाह देने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई. उनके नेतृत्व में कनाडा कभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का चुनाव नहीं हारा. हालांकि, जब कनाडा ने स्टीफन हार्पर और जस्टिन ट्रुडो के नेतृत्व में अपनी स्वतंत्र लकीर छोड़ी तो वह यूएनएससी के चुनाव हारने लगा. यही कारण है कि जापान एक बार यूएनएससी के लिए बांग्लादेश से हार गया था. संयुक्त राष्ट्र में एक अफ्रीकी राजदूत ने बड़ी सहजता से मुझे बताया: यूएनएससी में अमेरिका को एक अतिरिक्त वोट क्यों दें?

यूएनएससी का अगला स्थायी सदस्य होने का भारत का दावा बिल्कुल जायज है. मैंने पहले भी कहा है कि उसे तत्काल और बिना शर्त स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए. यह दावा तब और मजबूत होगा, जब अधिक से अधिक देश यूएनएससी में भारत के तत्काल प्रवेश की मांग करें. यह तभी संभव होगा जब भारत साफ-साफ एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में सामने आए.

भारत अगर स्वतंत्र रुख अपनाता है तो वह अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय संघ जैसी सभी महाशक्तियों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है. उनके गैर-जिम्मेदार और अड़ियल रवैए पर वह उन्हें स्पष्ट सलाह दे सकता है. मसलन, वह अंतरराष्ट्रीय कानून के मामले में चीन को बता सकता है कि दक्षिण चीन सागर में उसके नौ-बिंदुवार सीमा रेखा के दावे समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएलओएस) के तहत बेबुनियाद हैं. वह अमेरिका और ब्रिटेन से विश्व अदालत के फैसले का सम्मान करने और डिएगो गार्सिया (चागोस द्वीपसमूह में एक प्रवालद्वीप) को मॉरिशस को सौंपने के लिए कह सकता है. एक प्रभावशाली तीसरे ध्रुव के ऐसे बयान इन मुद्दों के निस्तारण के लिए जरूरी दबाव बना सकते हैं.

इलस्ट्रेशनः सिद्धांत जुमडे

भारत का यूएनएससी की स्थाई सदस्यता पर दावा तब सही मायने में मजबूत होगा जब वह एक स्वतंत्र शक्ति के तौर पर सामने आए और अन्य देश उसे एक स्वतंत्र तीसरे ध्रुव की तरह देखते हुए उसके तत्काल प्रवेश की मांग करें

दुनिया में 2023 में सबसे बड़ा संकट यूक्रेन युद्ध है. सिर्फ एक देश ही रूस, यूरोपीय संघ, अमेरिका और यूक्रेन की गहरी संरचनात्मक चिंताओं के साथ रणनीतिक सहानुभूति दिखा सकता है और वह है भारत. भारत के पास 2023 में जी20 की अध्यक्षता एक अवसर है जिससे वह युद्धविराम कराने की कोशिश कर सकता है. इससे न केवल यूक्रेन के पीड़ित लोगों बल्कि दुनिया के गरीब लोगों की मदद होगी जो ऊर्जा की ऊंची कीमतों और अंतरराष्ट्रीय मुद्रास्फीति से त्रस्त हैं. अगर भारत इस कोशिश में नाकाम भी होता है तब भी उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ेगी क्योंकि दुनिया को यूक्रेन युद्ध में एक निष्पक्ष और संतुलित मध्यस्थ चाहिए.

कई लोग गलती से भारत के स्वतंत्र तीसरे ध्रुव के रूप में उभरने को पिछली 'गुट-निरपेक्ष' विदेश नीति की वापसी समझ लेते हैं. दरअसल, यह रुख भारत के पिछले गुटनिरपेक्ष रास्ते के ठीक उलट होगा. 1979 में क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की ओर से आयोजित हवाना गुटनिरपेक्ष शिखर बैठक में भाग लेते समय मैंने श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने को सही कहते सुना था कि दुनिया में केवल दो गुटनिरपेक्ष देश हैं: अमेरिका और सोवियत संघ. भारत समेत दुनिया का हर दूसरा देश किसी न किसी रूप में इन दोनों के साथ था.

आज के संदर्भ में कहें तो दुनिया में केवल दो वास्तविक गुट-निरपेक्ष देश हैं: एक तो अमेरिका और दूसरा चीन. यह साफ है कि अधिकांश देश इनमें से किसी एक के साथ जुड़ना नहीं चाहते (जैसा कि मैंने *हैज चाइना वन?* में लिखा है). इसके बजाए, दुनिया के अधिकांश देश तीसरा ध्रुव चाहते हैं. तीसरा ध्रुव बनने के लिए केवल एक ही देश सक्षम है, और वह है भारत. भू-राजनैतिक संदर्भ में कहें, तो यह भारत के लिए एक अद्भुत मौका है. उसे इसको बेकार नहीं जाने देना चाहिए. ■

उथल-पुथल के बावजूद मौके

एशले जे. टेलिस
सीनियर फेलो, कारनेगी एनडाउमेंट

चीन पर साझा हितों की वजह से अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध पर भारत की नीति का हालांकि पुरजोर विरोध नहीं किया, पर उसकी बेचैनी बहुत ही वास्तविक है

पहले के दो साल की तरह **2022 का वर्ष भी** तकलीफदेह और हताशाजनक साबित हुआ. टीके लगने में बढ़ोतरी और पिछले संक्रमणों से उत्पन्न और बढ़ती रोग प्रतिरोधक क्षमता की बदौलत कोविड से जुड़ी मौतों के स्तर में दुनिया भर में हालांकि गिरावट आई, पर दुनिया महामारी के जिद्दी शिकंजे में जकड़ी रही, जिसने अलग-अलग तीव्रता की आर्थिक उखाड़-पछाड़ को जन्म दिया. जवाब में ज्यादातर देश उदार राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां अपनाने को मजबूर हुए, जिनसे चीजें और पेचीदा हो गईं. नागरिकों को तीव्र आर्थिक तकलीफ से बचाना तो खैर जरूरी ही है, लेकिन उन्होंने बहुत कम वस्तुओं के पीछे भागते बहुत ज्यादा धन से उत्पन्न बेहताशा बढ़ती महंगाई की शक्ल में ऐसा झटका दिया जिसका अनुमान भले लगाया जा सकता हो पर अनिवार्य रूप से मुश्किल पैदा करने वाला था.

अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अभी इन मुसीबतों से जूझ ही रही थी कि बदकिस्मती से उस पर एक और जबरदस्त प्रहार हुआ और इस बार पूरी तरह निर्लज्ज राजनैतिक दुष्टता की वजह से व्लादिमीर पुतिन के रूस ने पड़ोसी यूक्रेन के खिलाफ पूर्वनियोजित सैन्य युद्ध छेड़ दिया. पुतिन ने जो चढ़ाई की, उसका मकसद यूक्रेन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्णायक ढंग से खत्म करके एक बार फिर नए सिरे से संयोजित रूसी साम्राज्य में मिलाना था.

इसमें तो कोई संदेह ही नहीं था कि यह युद्धपिपासु आक्रामकता संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्तब्धकारी उल्लंघन और हाल के सालों की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए भीषणतम खतरा थी. मगर इस गैरजरूरी जंग के नतीजे यूक्रेन और रूस के लिए पैदा दुश्वारियों से भी आगे जाते हैं: इसने पूरी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को चपेट में ले लिया और तेल-गैस की कीमतों में उछाल और खाद्य आपूर्तियों में व्यवधान पैदा कर दिया, जबकि कोविड संकट से उत्पन्न महंगाई की मुश्किलों को और बढ़ा दिया. इसे थामने की अनिवार्यता ने दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरों में तीव्र बढ़ोतरी के लिए उकसाया, जिसने कई देशों में मंदी नहीं भी तो जबरिया आर्थिक सुस्ती का खतरा पैदा कर दिया.

इस तरह 2023 का साल बेचैन कर देने वाले अपशगुनों और उथल-पुथल के जारी रहने के वादे के साथ शुरू हुआ.

सबसे पहले तो यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के खत्म होने के आसार दिखाई नहीं देते. मॉस्को को मिली अप्रत्याशित पराजयों के बावजूद पुतिन ने इस युद्ध को जारी रखने का ठान लिया लगता है, फिर चाहे रूसी लोगों को इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े या रूसी राज्य के लिए भविष्य में यह कितना भी अव्यवहार्य हो. भारत इस टकराव में पक्ष नहीं है—और उसने कम या ज्यादा बारीकियों के साथ इसकी भर्त्सना की है—फिर भी यह नई दिल्ली को प्रभावित करेगा, यहां तक कि नुक्सान भी पहुंचाएगा. सस्ते रूसी तेल के तत्काल फायदे की आड़ में क्षितिज पर मंडरा रही ज्यादा बड़ी मुश्किलें ओझल नहीं होनी चाहिए: मॉस्को के सैन्य-औद्योगिक कॉम्प्लेक्स पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से रूसी सैन्य कलपुर्जों की आपूर्ति में रुकावट; रणनीतिक भागीदार के रूप में चीन पर रूस की गहरी होती निर्भरता, वह भी तब जब चीन-भारत रिश्ते खुद खतरे में पड़े हैं; और महाशक्ति के रूप में रूस की लगातार जारी आंतरिक दुर्बलता, जो वैश्विक बहुध्रुवीयता की भारत की इच्छा के लिए नुक्सानदायक है. इतना ही नहीं, वैश्विक आर्थिक संकट का खतरा कायम है और भारत के लिए परेशान करने वाली प्रतिकूल हवाओं के झोंके पैदा कर सकता है, वह भी ऐसे समय जब महामारी के बाद उसकी बहाली अभी शुरू ही हुई है. दुनिया भर में महंगाई की मुश्किलें कुछ ज्यादा समय तक

> दुनियाभर की **महंगाई और वैश्विक आर्थिक मंदी** भारत के आयात के खर्च पर असर डालेगी और निर्यात बाधित करेगी जो **भारत की ग्रोथ का मुख्य कारक** है

बनी रहती दिखती हैं, जिसके भारत के आयात बिल के लिए नुक्सानदेह नतीजे होंगे. यूक्रेन की लड़ाई अगर अचानक जरा भी बढ़ती है, तो ऊर्जा की कीमतें फिर आसमान छूने लगेंगी और उर्वरकों की लागत भी बढ़ जाएगी. चीन का अपनी कोविड प्रबंधन रणनीति को उलटना भी घरेलू संक्रमण दरों में नाटकीय बढ़ोतरी की आशंका से भरपूर है, जो वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में और रुकावटें आने की गारंटी है. ये भारत को भी प्रभावित करेंगे, खासकर दवाइयों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार तक कई सारे उद्योगों के लिए चीनी आगतों पर उसकी अत्यधिक और बढ़ती निर्भरता को देखते हुए. वैश्विक मंदी, अगर वह आती है, या आर्थिक सुस्ती भी, जिसका आना अवश्यंभावी है, भारतीय निर्यातों को बाधित करेगी, जो भारत की आर्थिक वृद्धि के बेहद अहम चालक हैं.

अंत में, भारत में खतरों का आसन्न माहौल उतना ही अशांत और अस्थिर रहने की संभावना है जितना वह बीते साल के दौरान था. पाकिस्तान में स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और कोई राहत नजर नहीं आती. हालांकि इस्लामाबाद की मुश्किलें मोटे तौर पर अंदरूनी हैं, पर भारत तक उनके घातक फैलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. भारत के खिलाफ चीन-पाकिस्तान के रणनीतिक सहयोग का ज्यादा संकटपूर्ण तरीकों से तीव्र होना भी तय है. चीन पूर्वी लद्दाख में

इलस्ट्रेशन: सिद्धांत जुमडे

> अमेरिकी धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा लेना दोनों देशों के **रणनीतिक सहयोग को गहरा करने का अच्छा तरीका नहीं है**

आखिरी दो विवादित जगहों से सेनाओं को पीछे हटा भी लेता है, तब भी इसकी संभावना नहीं कि वह सरहदों पर फिलहाल तैनात काफी ज्यादा लड़ाकू बलों को उनकी शांतिकालीन जगहों तक वापस ले जाएगा. चीन की बदली हुई सैन्य मुद्रा के कारण भारत पर वित्तीय और संचालगत दोनों मामलों में जो बोझ आ पड़ा है, वह अनंतकाल तक बना रहेगा.

इस तरह नई दिल्ली के लिए 2023 का साल निराशाजनक तरीके से शुरू हुआ. भारतीय अर्थव्यवस्था अन्यथा उदास और सुनसान भूदृश्य पर उजला बिंदु बनी हुई है; भारत की घरेलू राजनीति उल्लेखनीय ढंग से लगातार स्थिर है. अमेरिका और भारत के रणनीतिक रिश्तों में लगातार स्थिर गति से सुधार आ रहा है. जो बाइडन के प्रशासन ने भारत के प्रति प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ किया है. भारत की जी20 की अध्यक्षता के दौरान अमेरिका, नई दिल्ली के प्रति समर्थन को अनगिनत तरीकों से पेश करेगा, जिनमें इस साल जी20 शिखर सम्मेलन में बाइडन का मौजूद रहना भी शामिल है.

मगर इस मामले में फिलहाल ज्यादा बड़ा खतरा रूस और यूक्रेन पर उसके हमले के बारे में भारत की नीति है. दो नावों पर एक साथ सवारी का भारत का रवैया—नजाकत के साथ रूस के हमले की भर्त्सना करना और साथ ही उसके नतीजों से फायदा उठाना—अभी तक इसलिए कारगर रहा है क्योंकि बाइडन प्रशासन ने चीन पर हितों के मेल की वजह से इसका पुरजोर विरोध नहीं किया. तिस पर भी भारत की नीति के प्रति अमेरिका की असहजता वास्तविक है और प्रतिकूल असर डाल रही है. बड़े अधिकारियों ने नई दिल्ली के साथ उपयोगी रिश्तों को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन अमेरिकी सरकार के दूसरे हिस्सों में—जहां सहयोग से जुड़े अहम विकल्पों का आकलन और जांच-पड़ताल की जाती है—भारत के प्रति सहानुभूति लगातार बढ़ते दबाव में है और खतरे में पड़ सकती है. इसलिए अमेरिकी धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा लेना अमेरिका-भारत रणनीतिक सहयोग को गहरा करने का अच्छा तरीका नहीं है. ऐसे समय जब दोनों देशों को बहुतेरे संकटों से निपटना है, फलदायी ''विचारों के आदान-प्रदान'' के जरिए ज्यादा मजबूत आपसी सहयोग के मौकों को सावधानी से विकसित करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है. ■

मोदी की चुनावी राह के बड़े रोड़े

नौ राज्यों के चुनाव प्रधानमंत्री और भाजपा के लिए 2024 के आम चुनाव का सेमीफाइनल होंगे; दूसरी ओर कांग्रेस के लिए खुद को पुनर्जीवित करने का यह आखिरी मौका है

राज चेंगप्पा

इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में **भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019** के आम चुनावों में लगातार जीत हासिल करके एक इतिहास रचा, जो 50 साल से अधिक पहले 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा हासिल की गई उपलब्धि के समान था. हालांकि, जब विधानसभा चुनाव की बात आई तो राज्यों में भाजपा को सत्तारूढ़ कराने की प्रधानमंत्री की क्षमता पर संदेह जताया जाने लगा. 2018 और 2021 के बीच हुए 23 राज्यों के चुनावों में, भाजपा ने एकमात्र सीधी जीत अपेक्षाकृत छोटे पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में ही हासिल की. उसे बाकी जीत, चाहे वह महाराष्ट्र, बिहार, तीन पूर्वोत्तर राज्यों या पुदुच्चेरी में हों, अन्य दलों के साथ गठबंधन में मिलीं. 2022 में, जब भाजपा ने उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में तीन अच्छी जीत दर्ज की, तब मोदी का जादू पूरे रंग में नजर आया. यह भाजपा के लिए अच्छी खबर है लेकिन हिमाचल प्रदेश में आंतरिक फूट के कारण मिली हार ने पार्टी को अंदरूनी गुटबाजी के खतरे की गंभीरता से आगाह कर दिया है.

2023 में नौ राज्यों में चुनाव होने हैं और इनमें न केवल भाजपा के लिए बल्कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के लिए भी बहुत कुछ दांव पर लगा है. इन राज्यों में बड़ी जीत मोदी और भाजपा के लिए 2024 के आम चुनाव की सबसे बड़ी दावेदार बना देगी. हालांकि मोदी की लोकप्रियता ऊंचाई पर बनी हुई है, लेकिन एक चरमराती अर्थव्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी जैसे प्रश्न भाजपा की चुनावी किस्मत पर ग्रहण लगा सकते हैं. मोदी के लिए फायदे की बात यह है कि चाहे वह अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो या कश्मीर में धारा 370 हटाना, हिंदुत्व के मोर्चे पर कामयाबी हासिल करने के बाद वे विकास के प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर पार्टी की पकड़ मजबूत करने में मददगार होंगे. इस साल जी-20 में भारत की अध्यक्षता उनके लिए एक अतिरिक्त उपलब्धि होगी. इस बीच, विपक्ष की स्थिति डांवाडोल है. हिमाचल में पार्टी की मनोबल बढ़ाने वाली जीत के बाद आगामी राज्य चुनाव राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए एक बड़े पुनरुद्धार का आखिरी बड़ा मौका हो सकता है. इनसे यह भी पता चल जाएगा कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का कोई राजनैतिक प्रभाव पड़ा है या नहीं. अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए, 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव मायने

हालांकि मोदी की लोकप्रियता ऊंचाई पर बनी हुई है, लेकिन **एक चरमराती अर्थव्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी भाजपा** की किस्मत पर ग्रहण लगा सकते हैं

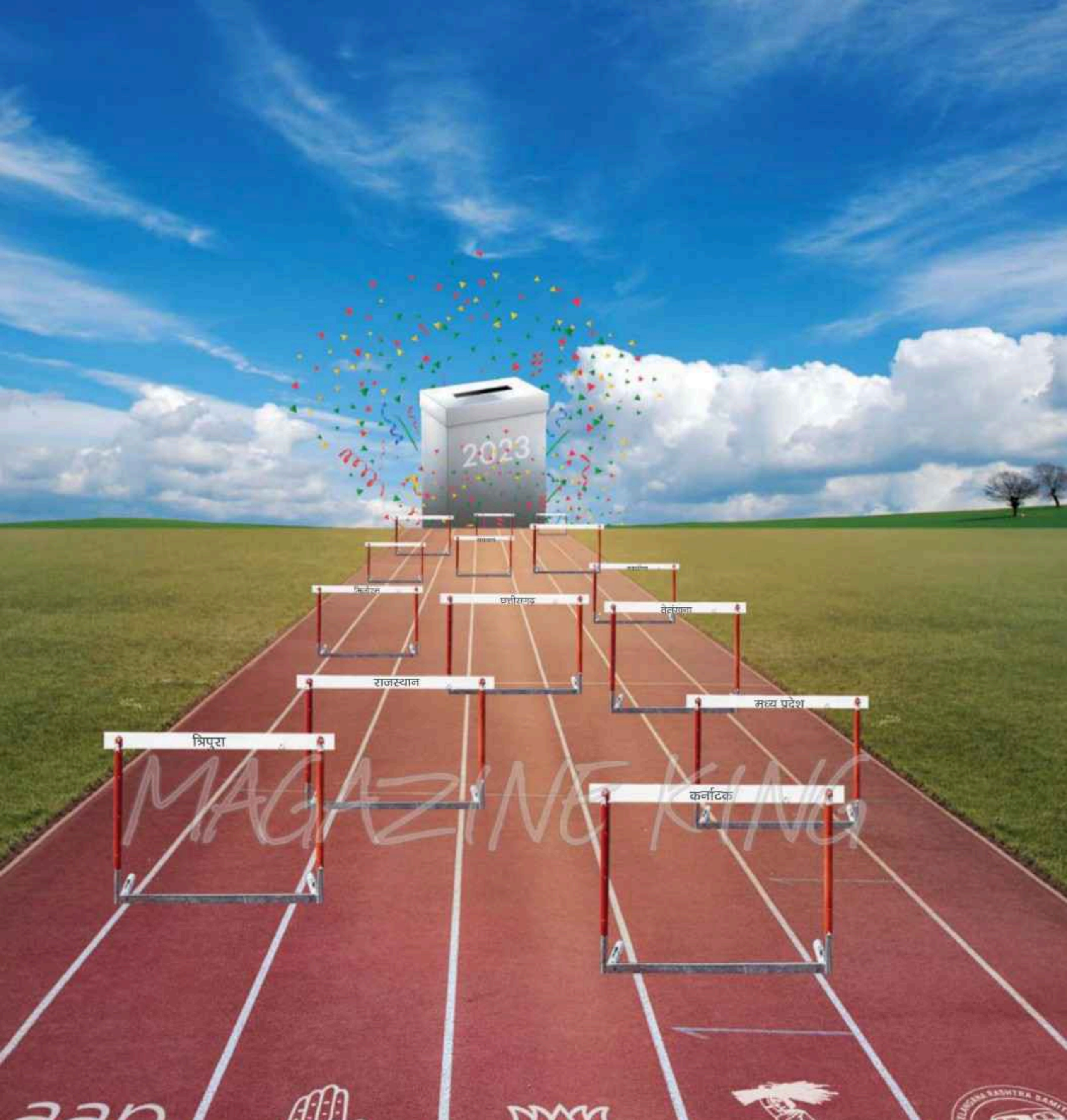
2023
छत्तीसगढ़
तेलंगाना
राजस्थान
मध्य प्रदेश
त्रिपुरा
कर्नाटक
MAGAZINE KING
aap
START

नहीं रखेंगे क्योंकि इनमें से अधिकांश राज्यों में उनकी उपस्थिति नगण्य है लेकिन वे पंजाब में जहां वे पिछले साल सत्ता में आए थे और अपने गढ़ दिल्ली में कितना अच्छा शासन दे पाते हैं, उससे उनकी क्षमता का आकलन होगा. दक्षिण में के. चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता वाली बड़ी क्षेत्रीय पार्टी, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को अपने और अपने नेता के अस्तित्व के लिए आगामी तेलंगाना चुनाव में जीत की आवश्यकता होगी.

दो हजार तेइस में होने वाले राज्य के चुनावों को चार प्रमुख लड़ाइयों में बांटा जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक का अलग-अलग प्रभाव होगा. पहला घमासान पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड में होगा जिसकी शुरुआत फरवरी में होगी. भाजपा और उसके सहयोगियों के लिए यहां कोई भी जीत प्रतीकात्मक होगी. सबसे ज्यादा नजर त्रिपुरा पर रहेगी जहां पार्टी के सामने सत्ता बरकरार रखने की चुनौती होगी. बढ़ती सत्ता-विरोधी लहर के कारण बिप्लब कुमार देब की जगह माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया था. अगर भाजपा इन तीनों चुनावों में जीत हासिल करती है, तो वह क्षेत्र में प्रभुत्व बनाए रखने में सफल होगी. यह उसके लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि मात्र छह साल पहले, वह कांग्रेस थी जो इस क्षेत्र की राजनीति की दिशा तय करती थी.

दूसरी लड़ाई अपेक्षाकृत बड़ी है, जो मई में कर्नाटक में होने वाली है. यह एकमात्र दक्षिणी राज्य है जहां अभी भाजपा का शासन है जबकि अन्य चार बड़े दक्षिणी राज्यों में इसकी उपस्थिति नगण्य है. हालांकि कर्नाटक में भी इसकी पकड़ कमजोर है. 2018 के चुनाव में, भाजपा 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी—224 के सदन में साधारण बहुमत से नौ कम—लेकिन 80 सीटों वाली कांग्रेस और 37 सीटें जीतने वाले जनता दल (सेक्युलर) ने गठबंधन करके सरकार बना ली. एक साल बाद, भाजपा ने कांग्रेस में दल-बदल कराकर अपनी सरकार बना ली और बी.एस. येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने.

दो साल बाद, जुलाई 2021 में, बढ़ते सत्ता विरोधी रुझान को टालने के लिए भाजपा ने येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया. बोम्मई के लिए अब भाजपा को जीत की ओर ले जाना बहुत मुश्किल कार्य लग रहा है क्योंकि राज्य में पार्टी के नेता उनके पीछे पूरे मन से खड़े नजर नहीं आते. कांग्रेस में भी उसके दो शीर्ष नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार के बीच अंदरूनी कलह चरम पर है. अगर दोनों एकजुट होकर चले तो कांग्रेस के पास जीतने का अच्छा मौका है. इससे पार्टी को इसके बाद होने वाले राज्य चुनावों में भाजपा से मुकाबला करने के लिए गति और धन दोनों मिल सकता है.

कर्नाटक चुनाव के नतीजे का 2023 के अंत में होने वाली तीसरी बड़ी लड़ाई पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होंगे. 2018 में, कांग्रेस ने तीनों राज्यों में जीत हासिल करके भाजपा को चौंका दिया, लेकिन वह उसका लाभ गंवा चुकी है. इसने मध्य प्रदेश को भाजपा के हाथों गंवा दिया जब इसके बहुत से नेताओं ने दलबदल करके कमलनाथ की सरकार गिरा दी. शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री के रूप में यह चौथा कार्यकाल है. सत्ता विरोधी लहर के साथ पार्टी में नेतृत्व की लड़ाई भी उतनी ही तेज चल रही है. हालांकि, संगठनात्मक रूप से भाजपा कांग्रेस के मुकाबले बहुत मजबूत बनी हुई है. राजस्थान में, कांग्रेस मुश्किल में है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सचिन पायलट अभी भी एक-दूसरे के साथ युद्ध की मुद्रा में ही हैं.

वैसे हालात भाजपा के भी कुछ अच्छे नहीं हैं. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान से पार्टी की एकजुटता पर असर पड़ रहा है. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए भाजपा अब तक एकजुट नहीं हो पाई है. ये तीन राज्य 2024 के आम चुनाव की दौड़ में महत्वपूर्ण हैं और जो पार्टी उन्हें जीतेगी हवा उसके पक्ष में बनेगी. भाजपा तर्क दे सकती है कि 2018 में इन तीन राज्यों को खोने के बावजूद, उसने 2019 के आम चुनाव में अपनी अधिकांश लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की. लेकिन यह आंशिक रूप से इसलिए भी था क्योंकि पुलवामा हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हावी हो गए थे और जो माहौल बना था उससे मतदाता मोदी के साथ खड़े हो गए. 2024 के लिए ऐसी कोई गारंटी नहीं है.

चौथी बड़ी लड़ाई तेलंगाना के लिए होगी, जहां भाजपा बड़ी बढ़त बनाने में कामयाब रही है, लेकिन वह तीसरे कार्यकाल के लिए मैदान में उतर रहे चालाक केसीआर और उनकी पार्टी, बीआरएस के प्रभुत्व को खत्म करने के लिए शायद पर्याप्त नहीं है. इससे बेफिक्र, भाजपा केसीआर को सत्ता से हटाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि यह राज्य उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनता जा रहा है. चाहे वह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस हो, ओडिशा में बीजू पटनायक की बीजू जनता दल हो, आंध्र प्रदेश में वाइ.एस. जगन मोहन रेड्डी की वाइएसआर कांग्रेस पार्टी हो या तेलंगाना में केसीआर की बीआरएस हो, इन सभी ने अपने-अपने राज्य में लाख कोशिशों के बावजूद एक बार भी भाजपा की दाल नहीं गलने दी है.

क्षेत्रीय दल पार्टी की दुखती रग बने हुए हैं. हालांकि इनमें से कुछ राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस को हटाकर भाजपा प्रमुख प्रतिद्वंद्वी दल बन गई है लेकिन क्षेत्रीय ताकतों को हराना सबसे बड़ी चुनौती है. बिहार में जद (यू) के नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर निकलकर राजद के तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला लिया है और वहां भाजपा के लिए राहें मुश्किल होंगी. महाराष्ट्र में, भाजपा ने भले ही शिवसेना को तोड़कर सत्ता में वापसी की हो, लेकिन वह अभी पूर्ण नियंत्रण से दूर है. शिवसेना से अलग हुए धड़े और भाजपा की मिलीजुली सरकार कितनी टिकाऊ होगी, यह इस साल मुंबई/ठाणे में होने वाले निकाय चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा, जो यह तय करेगा कि असली शिवसेना कौन है.

इसलिए, वर्ष 2023 कई मायनों में प्रमुख राजनैतिक दलों के लिए 2024 के आम चुनाव का सेमीफाइनल होगा. ■

> मोदी के लिए फायदे की बात यह है कि **उन्होंने हिंदुत्व के मोर्चे पर कामयाबी हासिल कर ली है,** वे विकास के प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर भाजपा की संभावनाएं बढ़ा सकते हैं

ब्लॉकचेन को नजरअंदाज न करें

रोहन मूर्ति
सीटीओ, संस्थापक
सोरोको

क्रिप्टोकरेंसियों की चमक 2022 में भले ही फीकी पड़ गई हो लेकिन उन्हें चलाने वाली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हमारे भविष्य के लिए अब भी बहुत दम है

बीते कुछ सालों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से चलने वाली क्रिप्टोकरेंसियों ने जबरदस्त उत्साह जगाया. निवेशक और कंपनियां ऐसे भविष्य का सपना देखने लगीं जिसमें ये डिजिटल मुद्राएं नई विकेंद्रीकृत और झट-पट लेनदेन के मामलों को बढ़ावा देंगी. फिर भी एक ओर जहां 2022 सभी परिसंपत्ति वर्ग या ऐसेट क्लास के लिए मुश्किल साल था, वहीं वह क्रिप्टो करेंसियों के लिए इससे भी ज्यादा बुरा साबित हुआ.

सभी क्रिप्टोकरेंसी का कुल मूल्य नवंबर 2021 में करीब 30 खरब डॉलर के शिखर से गिरकर आज 800 अरब डॉलर हो गया है, जिसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति को 20 खरब डॉलर से ज्यादा का नुक्सान हुआ है. ऐसा लगता है कि इसके पीछे दूसरी वजहों के अलावा धोखाधड़ी वाले व्यवहार—जो कुछ हद तक गवर्नेंस, निवेशकों की सूझबूझ, और इस क्षेत्र में नियमों की कमी वजह से—खुदरा और संस्थागत निवेशकों को समान रूप से चोट पहुंचाते हैं. क्रिप्टोकरेंसी के मामले में उल्लेखनीय घटनाओं में शामिल हैं:

- 8 अरब डॉलर का एफटीएक्स घोटाला, जो अमेरिकी फेडरल अभियोजकों के मुताबिक, कथित आपराधिक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का नतीजा था;
- टेरा का पतन, जो इस मुद्रा की एल्गोरिद्म प्रकृति के आसपास सार्वजनिक रूप से बताए गए जोखिमों की अनदेखी की वजह से हुआ. इससे लगभग 50 अरब डॉलर के बाजार मूल्यवाली क्रिप्टोकरेंसी का सफाया हो गया;
- क्रिप्टोकरेंसी के संस्थापकों और निवेशकों के बीच कथित सांठगांठ, जिसके चलते चुनिंदा कॉइन के मूल्य निर्धारण को कृत्रिम रूप से बनाए रखा गया.

लगभग सभी मामलों में आमतौर पर या तो किसी व्यक्ति का हित या लालच था जिसने पूरी व्यवस्था को खत्म कर दिया या नियंत्रण और संतुलन की पूरी कमी के साथ बेहद खराब गवर्नेंस था. क्रिप्टो को लगे इन प्रमुख झटकों के बावजूद, सच यह है कि इसमें अंतर्निहित तकनीक—ब्लॉकचेन—हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है. लोग अक्सर ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. पिछले कुछ सालों में ब्लॉकचेन को काफी प्रचारित किया गया और यह दुरुपयोग का भी शिकार हुआ है. इसने इसकी असली क्षमता और सीमाओं की पूरी समझ को बाधित कर दिया है.

ब्लॉकचेन तकनीक को कुछ सामान्य सवालों के जरिए समझते हैं:

- ब्लॉकचेन क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो यह एक बहीखाता है. हां, जिस तरह से हम 50 साल पहले हिसाब-किताब लिखते थे. सिर्फ एक फर्क है कि यह बही अपरिवर्तनीय है—यानी इसमें केवल लिखा जा सकता है, और आप इसे मिटा नहीं सकते और इसके साथ घालमेल नहीं कर सकते.
- यह खाता कहां रहता है? यह लेजर बांटा जाता है, यानी यह कई कंप्यूटरों में विभाजित है, जिसमें उस लेजर की कई प्रतियां इंटरनेट की बदौलत हरेक कंप्यूटर में मौजूद हैं. ये कंप्यूटर व्यक्तियों या संगठनों के हो सकते हैं, और ज्यादातर ब्लॉकचेन के नियमों के मुताबिक, इसके नेटवर्क में विषमता होनी चाहिए.
- इस बहीखाते को मेनटेन कैसे किया जाता है? एक प्रोटोकॉल, या एल्गोरिद्म से चलने वाले नियमों का एक सेट है, कि यह किस जानकारी को स्टोर कर सकता है, इसमें कौन लिख सकता है और इसे कैसे अपडेट किया जा सकता है. इन नियमों को ब्लॉकचेन के संस्थापक ही प्रोग्राम करते हैं, जिसमें कोड लोगों के लिए खुला होता है.
- आप बही खाते पर क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं? लगभग सब कुछ. वित्तीय लेन-देन, नौकरी का इतिहास, निजी सूचनाएं, वगैरह.
- जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल क्यों करें? क्योंकि ब्लॉकचेन लेजर प्रतियां अपरिवर्तनीय हैं और कंप्यूटरों में रखी जाती हैं, उन्हें अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद माना जाता है.

ब्लॉकचेन के बारे में इस बुनियादी जानकारी से पता चलता है कि दुनिया उसके बारे में क्यों उत्साहित है—वे किसी केंद्रीय समन्वय इकाई की जरूरत के बिना सूचना के प्रबंधन का विकेंद्रीकृत या बंटा हुआ तरीका प्रदान करते हैं. लेकिन कुछ भी बांटने का यह मोह क्यों

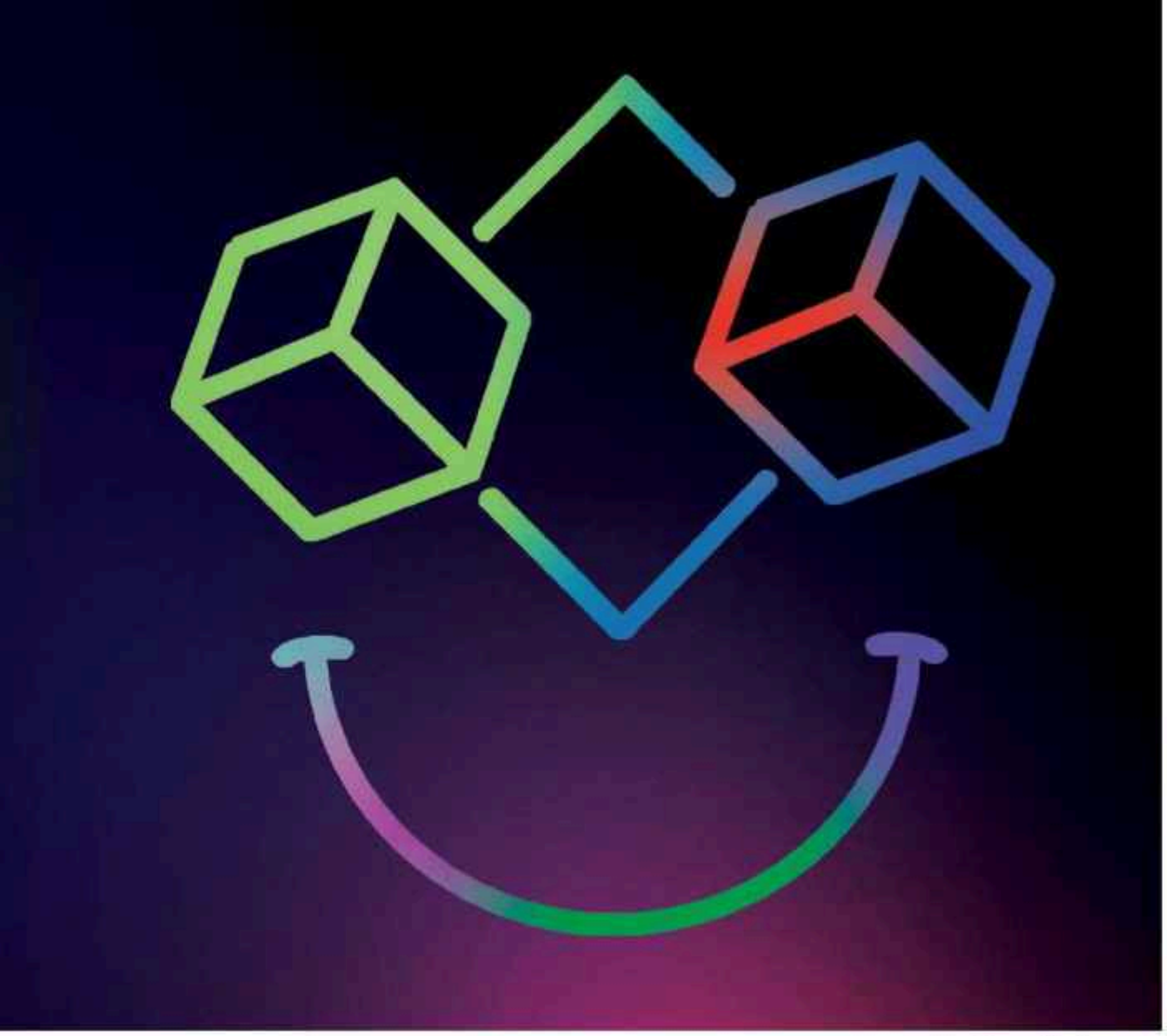

इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

है? दूसरे लोगों के साथ ही कंप्यूटर वैज्ञानिक लंबे समय से सबसे बड़ी और सबसे पुरानी वितरित प्रणाली—प्रकृति—से प्रेरित हैं. प्रकृति को नियंत्रित करने वाली कोई इकलौती केंद्रीय इकाई नहीं है फिर भी यह सबसे ज्यादा मापनीय और सुसंगत वितरित प्रणाली है, और यह नियमों और कानूनों के एक समूह से संचालित होती है. मिसाल के तौर पर कोई केंद्रीय इकाई किसी मधुमक्खी को किसी फूल, या किसी फूल को सूरज की रोशनी की ओर मुड़ने, किसी पौधे को फल पैदा करने के लिए, जानवरों को इन फलों को खाने के लिए निर्देश नहीं दे रही है. ये सभी संस्थाएं बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण के स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए नियमों के एक सेट का उपयोग करती हैं और एक नतीजा देती हैं जो सिस्टम के भीतर अच्छाई पैदा करता है. कोई सिस्टम अक्सर स्वाभाविक रूप से इसी तरह डिजाइन किया जाता है जो लाखों या अरबों प्रतिभागियों को माप सकता है. इसी तरह ब्लॉकचेन हमें अपनी मानव निर्मित दुनिया में कुछ, सभी नहीं, केंद्रीकृत संरचनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती है.

मजेदार बात यह है कि हम पहले से ही मानव निर्मित वितरित या बंटी हुई प्रणालियों के लाभार्थी हैं. मिसाल के तौर पर इंटरनेट मानव जाति की सबसे अच्छी तरह से निर्मित वितरित प्रणालियों में से एक है. आज यह जिस मुकाम पर है वह वितरित प्रणाली की ही बदौलत है: इंटरनेट कैसे फैलता है या आप इससे जुड़ने के लिए किन उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए कोई केंद्रीय नियामक नहीं है. इसी तरह, कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने 1960 के दशक के बाद से वितरित बहीखाता के लिए कई एल्गोरिद्म और सिस्टम विकसित किए हैं. उन्होंने स्टॉक ट्रेडिंग, हवाई यातायात नियंत्रण, या यहां तक कि फाइल शेयरिंग के लिए इस सिस्टम को उपयोगी पाया है. इसलिए कुछ अर्थों में ब्लॉकचेन पूरी तरह से नए नहीं हैं. वे स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम टेक्नोलॉजी की निरंतरता का हिस्सा हैं.

एक ओर जहां इंटरनेट भले ही वितरित प्रणाली हो लेकिन इसके ऊपर बने अधिकांश उपयोग के मामले—बैंकिंग, सोशल मीडिया, गेमिंग—वास्तव में, केंद्रीकृत हैं और इन्हें एचडीएफसी, मेटा और एपिक जैसी कंपनियां चला रही हैं. इन केंद्रीकृत उपयोग के मामलों, जिन्हें अक्सर वेब 2.0 कहा जाता है, की वजह से कुछ कंपनियों के हाथों में ज्यादा अधिकार होते हैं. यही वह जगह है जहां ब्लॉकचेन तकनीक ऐसे उपयोग के मामलों (या पूरी तरह से नए) के पुनर्निर्माण के अवसर देकर, जो विकेंद्रीकृत हैं, यथास्थिति में खलल डालती है. इसका मतलब यह है कि कोई केंद्रीय इकाई या मालिक नहीं है. ऐसे उपयोग मामलों (यूज केसेज) को वेब 3.0 कहा जाता है.

भले ही क्रिप्टो को 2022 में बड़ी असफलताओं का सामना करना पड़ा लेकिन ब्लॉकचेन के दूसरे ऐप्लिकेशंस को शिद्दत से खोजा जा रहा है जिनमें काफी संभावनाएं हैं

वेब 3.0 के उत्साही लोगों का मानना है कि विकेंद्रीकृत तरीके से एंड-यूजर ऐप्लिकेशन की कल्पना करने से कॉर्पोरेट बिचौलियों को कम कर या हटा दिया जाएगा जो वैसे भी लागत, सेंसरशिप और अस्पष्टता बढ़ाते हैं और कई तरह की बाधाएं खड़ी करते हैं. दरअसल, क्रिप्टो संस्थापकों और उपयोगकर्ताओं ने अक्सर इन्हीं तर्कों के आधार पर केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियों से अलग एक सार्वभौमिक वितरित, डिजिटल मुद्रा के विचार का समर्थन किया. एक ओर जहां क्रिप्टो को 2022 में बड़ी असफलताओं का सामना करना पड़ा है, वहीं ब्लॉकचेन के दूसरे ऐप्लिकेशंस को शिद्दत से खोजा जा रहा है जिनमें 2023 (और उसके बाद) में भारत और दुनिया के लिए बेहद संभावनाएं हैं. इनमें शामिल हैं:

- असली दुनिया की संपत्ति का टोकन, जैसे कि घर, ताकि मालिक अपनी संपत्ति को एक ब्लॉकचेन पर सूचीबद्ध कर सकें और उसमें इक्विटी बेच सकें, और इस तरह के लेन-देन का ब्योरा बहीखाता में दर्ज किया जाएगा;
- भारत में ट्रैक करने के लिए लीगेसी डिजिटल सिस्टम नहीं है, मिसाल के तौर पर, संपत्ति/भूमि रिकॉर्ड. यह इस तरह के स्वामित्व को ट्रैक करने, व्यक्तिगत क्रेडिट योग्यता को व्यवस्थित करने और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए आसान क्रेडिट प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए मूल्यवान है.
- बैंकिंग में धोखाधड़ी रोकने के लिए एकल बिंदु केवाइसी, डिस्ट्रिब्यूटेड वेरिफिकेशन और वैलिडेशन बनाकर;
- नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों के लिए पहचान प्रबंधन का बिल्कुल नया प्रतिमान. यह आज की पारंपरिक बैकग्राउंड जांच व्यवस्था की जगह लेगा. ब्लॉकचेन अंतिम उपयोगकर्ताओं को यह नियंत्रित करने में सक्षम बना सकते हैं कि वे अपनी जानकारी किसके सामने, कब और क्यों प्रकट करते हैं. कई दूसरे देशों की तरह भारत में स्वास्थ्य, संपत्ति और सार्वजनिक रिकॉर्ड के अन्य रूपों को ट्रैक करने के लिए लीगेसी डिजिटल सिस्टम की कमी है. लेकिन यह कमी ऐप्लिकेशंस के एक नए सेट के लिए एक अवसर है. ब्लॉकचेन का वर्तमान युग अपनी प्रारंभिक अवस्था में है लेकिन विकास निश्चित रूप से जारी है.

मैं टेक्नोलॉजी के बारे में हमेशा आशावादी हूं. हां, इस क्षेत्र में गवर्नेंस और नियमों में सुधार की जरूरत है. लेकिन उद्यमियों—विशेष रूप से यहां भारत में— को इस दौरान ब्लॉकचेन के हालात बदलने वाले उपयोग के मामलों की तलाश बंद नहीं करनी चाहिए. ■

प्रशांतो के. रॉय
पॉलिसी कंसल्टेंट और
टेक्नोलॉजी लेखक

डिजिटल रणभूमि के खतरे

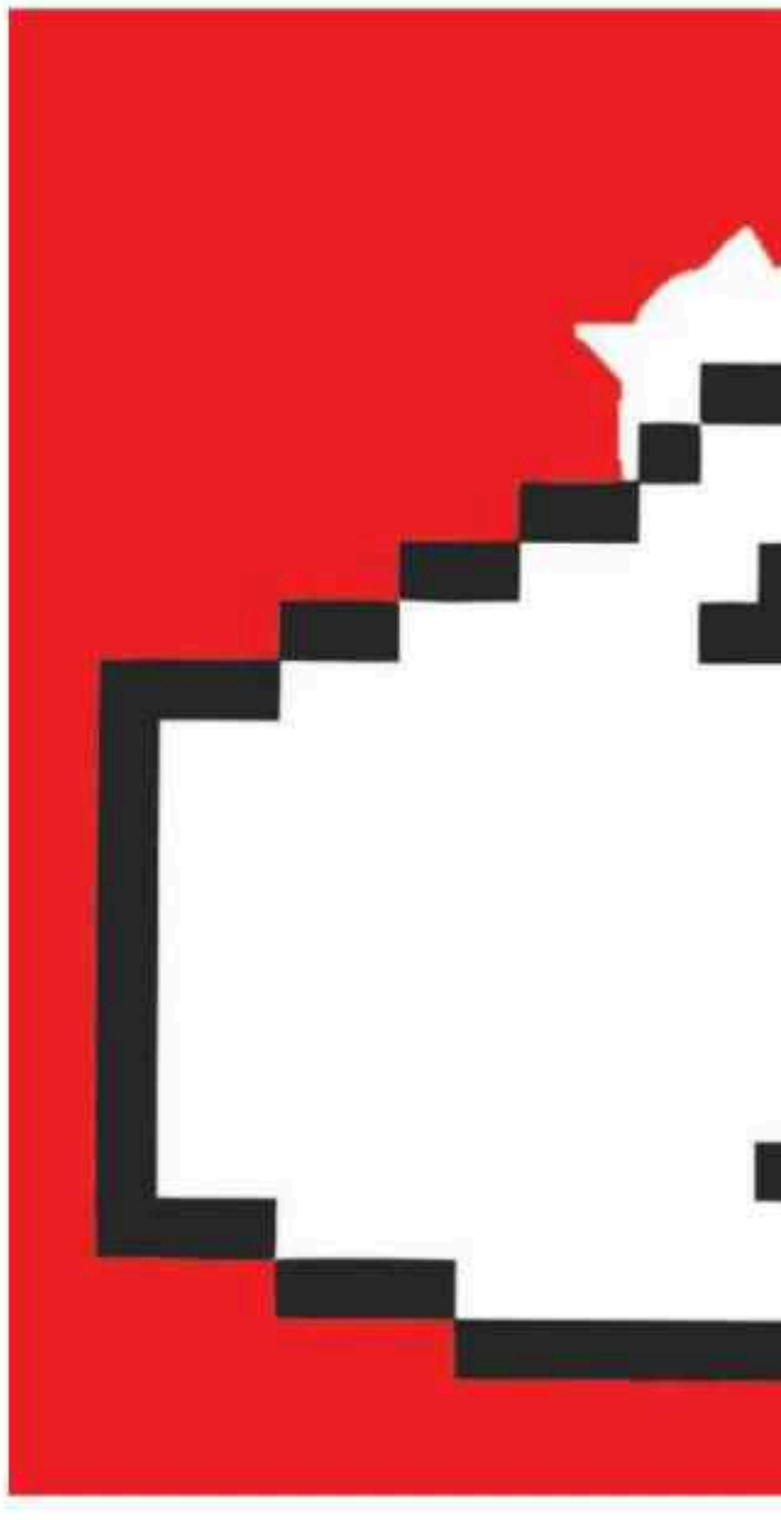

दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में ऑनलाइन सुविधाओं का जमकर इस्तेमाल होगा. एक अरब मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड और आधार कार्डों के साथ डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाएं सुलभ बना देगा लेकिन डेटा चोरी, ऑनलाइन अपराध और इंटरनेट बंद किए जाने से उनके खतरे बढ़ जाएंगे

पिछले साल के आखिर में भारत के प्रमुख सरकारी अस्पताल को पंगु कर देने वाले साइबर हमले ने हमें दिखा दिया कि 2023 में इस देश को किससे निबटना होगा: डिजिटल अपराध और युद्ध, दोनों रोजमर्रा की जिंदगी, महत्वपूर्ण सुविधाओं और बुनियादी ढांचों में दखल दे रहे हैं, और ये सीमा पर संघर्ष और घुसपैठ से ज्यादा नुक्सान पहुंचा रहे हैं.

एम्स दो हफ्ते से ज्यादा समय तक बाधित रहा, और मैनुअल सिस्टम में वापस आने के साथ ही धीरे-धीरे रेंगने लगा. हमलावरों ने न केवल प्रमुख सर्वरों को हैक कर सूचनाओं की चोरी की बल्कि बैकअप सहित कई टेराबाइट डेटा को भी खराब कर दिया. इसके बाद दूसरे अस्पतालों और हेल्थकेयर सिस्टम्स पर साइबर हमले हुए—सफदरजंग अस्पताल को कथित तौर पर एक दिन के लिए बंद कर दिया गया, और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सिस्टम में 24 घंटे के भीतर 'हांगकांग से' 6,000 से ज्यादा हैकिंग की कोशिश की गई.

इस तरह के हमले अक्सर 'रैनसमवेयर' होते हैं. इसमें बैकअप सहित डेटा में मैलवेयर डाल दिया जाता है और इसे ठीक करने के लिए फिरौती की मांग की जाती है. एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में 78 फीसद भारतीय संगठन मैलवेयर के हमलों के शिकार हुए, और उनमें से हर दसवें संगठन ने अपने डेटा और सिस्टम को फिर से उपयोग के लायक बनाने के लिए दस लाख डॉलर से ज्यादा की फिरौती दी.

एम्स के मामले में कथित तौर पर फिरौती का भुगतान नहीं किया गया लेकिन यह एक बड़ा सबक दे गया कि स्वास्थ्य सेवा के लिए साइबर सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है. यह साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सूचीबद्ध देश के छह 'महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर' में अभी तक शामिल नहीं है, भले ही इसकी सख्त जरूरत है. 2023 की फौरी जरूरतों में शामिल हैं: भारत के लिए बहुत विलंबित राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति, शीर्ष सार्वजनिक साइबर सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और कानून लागू करने के लिए गहन साइबर प्रशिक्षण.

इस बीच, पिछले तीन साल में 16 लाख साइबर अपराध की घटनाओं के साथ मामूली किस्म के साइबर अपराध में इजाफा जारी है. फिशिंग हमले, नकली ग्राहक सेवा संदेश, जब तक आप किसी लिंक पर क्लिक नहीं करते हैं, तब तक बैंक खातों को फ्रीज करने की चेतावनी. हालात सुधरने से पहले और खराब होंगे क्योंकि पहले के मुकाबले ज्यादा भारतीय ऑनलाइन होंगे.

डिजिटल इंडिया के मेगा प्लेटफॉर्म

हमारे यहां 1.15 अरब मोबाइल सब्सक्राइबर हैं, और 60 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन हैं, जो इस साल बढ़कर 70 करोड़ तक हो सकते हैं क्योंकि 2023 में 17.5 करोड़ नए स्मार्टफोन आने वाले हैं. मोबाइल डिजिटल इंडिया और तथाकथित जेएएम (जन धन, आधार, मोबाइल) ट्रिनिटी का केंद्र है. दुनिया के सबसे बड़े डेटाबेस आधार ने 1.3 अरब पहचान पत्र तैयार किए हैं. जन धन कार्यक्रम ने 47.7 करोड़ से ज्यादा लोगों को बुनियादी बैंक खातों के जरिए बैंक से जोड़ दिया है. इनकी वजह से 90 करोड़ से अधिक नागरिकों को 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण' मुमकिन हुआ है.

इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

भारतीय बड़ी संख्या में अपने **जीवन और काम के लिए इंटरनेट पर निर्भर** होते जा रहे हैं लेकिन इंटरनेट शटडाउन की घड़ी में **वे अचानक सारी सुविधाओं से वंचित** हो सकते हैं

इस डिजिटल पहचान पर निर्भरता का एक स्याह पहलू भी है: लाभ से वंचित करना. 2019 के चुनाव के बाद एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पाया गया कि आधार की समस्याओं के कारण 39 फीसद गरीब परिवारों को सब्सिडी वाले राशन से वंचित कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 में आधार कार्ड से जुड़ी याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया. इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि आधार से लिंक न होने की वजह से लगभग चार करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए गए, जिसके चलते भुखमरी से मौतें हुईं.

मोदी सरकार आधार, यूपीआइ और अन्य डिजिटल कार्यक्रमों की सफलता से प्रेरित होकर दूसरे मेगा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आगे बढ़ी है. जल्दी से कोविड वैक्सीन के लिए कोविन तैयार हो गया, जिसने दो अरब से ज्यादा शॉट्स देने में मदद की, और यह कोविड से परे एक टीकाकरण प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हो रहा है. इससे जुड़ा आरोग्य सेतु 'कोविड ऐप' एक हेल्थ ऐप बन जाएगा.

2023 में आने वाले मेगा प्लेटफॉर्मों में नया ओएनडीसी, या डिजिटल कॉमर्स के लिए एक नेटवर्क शामिल है, जिसका मकसद विदेशी स्वामित्व वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर निर्भरता को कम करना है. फिर नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर, या एनडीईएआर एजुकेशन, ऐसे क्षेत्र के लिए है. लेकिन 2023 में असली बड़ी पहल स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगी.

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के उद्देश्य वाला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 1.4 अरब भारतीयों के स्वास्थ्य डेटा को स्टोर करेगा. यह आधार से जुड़ा होगा. इसमें सभी ऐतिहासिक रिकॉर्ड, डॉक्टरों और चिकित्सा सेवा प्रदाताओं का एक नेटवर्क, दवाओं की एक लिंक्ड रजिस्ट्री, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और डॉक्टरों के बीच ''मरीजों की रजामंदी से'' डेटा साझा करने की इजाजत होगी.

इसके साथ डिजिटल इंडिया ऐक्ट भी तैयार किया जा रहा है, जो बुढ़ाते सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जगह लेगा. ये सभी नए कानून उस क्षेत्र को अधिक मजबूती से नियमित करेंगे जो दरअसल एक अरब भारतीयों को ऑनलाइन चला रहा है: सोशल मीडिया.

असामाजिक मीडिया

भारत में सोशल मीडिया संख्या और रफ्तार के मामले में हर साल तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा जब युद्ध का मैदान वास्तव में ऑनलाइन हो जाएगा: भारत के आम चुनाव से एक साल पहले. जी हां, वह साल है 2023.

अगला चुनाव बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर लड़ा जाएगा, और इस ध्रुवीकृत और विभाजित राष्ट्र में बहुत तेज आतिशबाजी होगी. भारत और भारतीयों के पास पतली ऑनलाइन चमड़ी है, जो मामूली उकसावे से आहत हो जाती है. लेकिन कानून लागू करने वाले सोशल मीडिया यूजर्स को गिरफ्तार करने के लिए तैयार बैठे हैं, खासकर परेशान करने वाले फैक्टचेकर्स को एक पुरानी हिंदी फिल्म के शॉट को पोस्ट करने जैसे जुर्म के लिए गिरफ्तार करने का इंतजार कर रहे हैं. फैक्ट चेक करने का काफी हद तक कृतघ्न काम खासकर दबाव में होगा क्योंकि गलत सूचनाओं की झड़ी लग जाएगी, और एक बार फिर ब्लॉक करने वाले ऑर्डर बढ़ जाएंगे.

स्याह पहलूः सब बंद

नागरिकों के लिए ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेवाओं पर निर्भर होने का क्या मतलब है, जिन्हें बंद किया जा सकता है—कभी-कभी बस इंटरनेट बंद करके? उनके लिए बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नामांकित होने का क्या मतलब है, कभी-कभी जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती या कोई विकल्प नहीं होता?

इन प्लेटफॉर्मों का साफ तौर पर मकसद है और उनके इरादे नेक हैं. कोविन ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम को सक्षम बनाया. यूपीआइ ने भारत में भुगतान को बदल दिया है. आयुष्मान भारत का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा को सस्ता और सुलभ बनाना और उपचार के लिए सेहद के रिकॉर्ड को बेहतर बनाना है.

आधार के जरिए इंटरलिंकिंग ही पहली कमजोर कड़ी है: हैकर हमला करके नागरिकों की थोक व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी तक पहुंच सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग हमले शुरू कर सकते हैं, डेटा का उपयोग बैंकिंग जैसी अन्य प्रणालियों में घुसपैठ करने के लिए कर सकते हैं, या सरकारी अधिकारियों या हाइ नेटवर्थ वाले व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए कर सकते हैं. हेल्थकेयर रिकॉर्ड हैकरों और ब्लैकमेलरों के लिए खास तौर पर बेशकीमती है, जैसा कि 2022 में एम्स से चुराया गया हो सकता है.

डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सभी प्रमुख सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बना देगा, लेकिन ऑनलाइन अपराध और सरकार की सनक के मामले में कमजोर होंगे. दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल प्रयोग डिजिटल इंडिया को 2023 में दुनिया बारीकी से देखेगी. ■

सिद्धार्थ रॉय कपूर
संस्थापक और एमडी
रॉय कपूर फिल्म्स

लाइट्स कैमरा, इंडिया

भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग में कई स्तरों पर बदलाव हो रहे हैं और एक साथ बहुत सी चीजें हो रही हैं. हमारी आबादी के फायदे इतने वृहद है कि हर प्लेटफॉर्म के लिए संभावनाएं हैं

मीडिया और मनोरंजन उद्योग के बारे में भविष्यवाणी करना आसान नहीं है, क्योंकि अपेक्षाकृत रूप से स्थिर समझे गए समय में भी आपकी बेहतर से बेहतर भविष्यवाणियां सिरे से गलत निकल सकती हैं. जनवरी 2023 में, जब मैं यह लेख लिख रहा हूं, ऐसी भविष्यवाणी और भी बेवकूफाना लगती है, खासकर इस बात को देखते हुए कि कोविड-19 की महामारी ने दुनिया भर के दर्शकों के व्यवहार को उलट-पलट दिया और ज्यादातर स्टूडियो, स्ट्रीमर, प्रदर्शकों, प्रसारकों और सर्जकों की रणनीतियों और व्यूह रचनाओं को 180 डिग्री का जबरदस्त झटका दिया. लेकिन अगर हम बाज दफे दिलेरी से बात कहने का जोखिम नहीं उठाते, तो शानदार उतार-चढ़ावों से भरे इस उद्योग में भला हैं ही क्यों? इसलिए मैं अपनी बात कहूंगा.

अब यह साफ है कि सिनेमाघरों में फिल्म देखने के ट्रेंड में आई हालिया गिरावट को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया है. 2022 में दुनिया भर में रिलीज *अवतार: द वे ऑफ वॉटर, टॉप गन: मावरिक* और *जुरासिक पार्क: डोमिनियन* सरीखी और हमारे देश में *के.जी.एफ: चैप्टर 2, आरआरआर* और *दृश्यम 2* के अलावा दूसरी फिल्में देखने के लिए दर्शकों के झुंड के झुंड निकलकर आए. साफ है कि हम अब भी अजनबियों की टोली के साथ अंधेरे सिनेमाघरों में जाने और खुद को बड़े परदे के जादू में खो देने के अनुभव पसंद करते हैं. इसी तरह, यह भी साफ होता जा रहा है कि सिनेमाघरों में देखने के लिए दर्शकों को जिस किस्म की फिल्में चाहिए, वे बहुत विशिष्ट शैलियों तक सीमित हो गई हैं. सुपरहीरो फिल्में, तमाशाई नजारे, खूब जोशो-खरोश और ताकत से भरी ऐक्शन फिल्में, जीव-जंतुओं पर बनी फिल्में और थ्रिलर यानी रोमांचक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही हैं. महामारी से पहले उन्होंने जितने दर्शकों को आकर्षित किया होता, उससे कहीं ज्यादा को रिझा रही हैं. दूसरी तरफ, ड्रामा, हल्की-फुल्की कॉमेडी, रोमांटिक-कॉमेडी और ज्यादा बारीकियों और परतों से भरपूर कहानियां अब पूरी तरह घर पर देखी जाने लगी हैं. यह बदलाव कोविड-19 के पहले से ही आ रहा था, पर कुछ खास जॉनर की फिल्मों का सिनेमाघरों में इतना जबरदस्त प्रदर्शन रहा है और कुछ का इतना खराब कि दोनों के बीच का अंतर बहुत साफ हो चला है. ऐसा नहीं है कि इस नियम के अपवाद नहीं होंगे. विलियम गोल्डमैन ने बहुत पहले कहा था, ''फिल्मों के कारोबार में कोई भी वाकई कुछ नहीं जानता.'' मगर बॉक्स ऑफिस पर अलग-अलग जॉनर की फिल्मों के अलग-अलग प्रदर्शन के हालिया ट्रेंड के चलते कम से कम आने वाले कुछ महीनों और सालों में स्टूडियो, स्ट्रीमर, निर्माता, निर्देशक और कलाकार इसी हिसाब से रचनात्मक फैसले लेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट को सिनेमाघरों के लिए और किसे गैर-सिनेमाघर प्लेटफॉर्मों के लिए हरी झंडी दिखाना बेहतर होगा.

गेमिंग कई सालों से एक बड़ा उद्योग रहा है (सिनेमा के कारोबार से कई गुना बड़ा). आने वाले सालों में मुझे पारंपरिक मनोरंजन उद्योग और गेमिंग उद्योग के बीच बड़ा संगम होता दिखाई देता है. युवा दर्शक अब नैरेटिव के अपने विकल्पों पर कहीं ज्यादा नियंत्रण रखने के अभ्यस्त हैं, चाहे वह सोशल मीडिया पर हो या गेमिंग में या नवोदित मेटावर्स में. यह तय ही समझा जाए कि इस पीढ़ी के दर्शक अब अपने मनोरंजन के नैरेटिव की कमान भी अपने हाथ में लेना चाहेंगे. कुछ सालों से इस दो तरह के विकल्पों पर आधारित नैरेटिव पर प्रयोग होते रहे हैं (मसलन, नेटफ्लिक्स पर 2018 का *ब्लैक मिरर: बैंडरस्नैच*), पर जो भविष्य मैं देख रहा हूं वहां दर्शक एआर/वीआर की सहायता से बने परतदार नैरिटिव को नियंत्रित करते हुए, बढ़-चढ़कर मुख्य पात्रों की भूमिका अख्तियार करेंगे और कथानक को आगे बढ़ाने वाले भावनात्मक विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे. इसमें भले अभी कुछ साल लग सकते हैं, पर यह अवश्यंभावी मालूम होता है कि जब टेक्नोलॉजी, अनुभव का ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण दर्शक के हाथ में सौंपने की दिशा में बढ़ रही है, वे अब अपने मनोरंजन के मूल अर्थ और सार पर अपना नियंत्रण और उसमें सक्रिय भागीदारी हासिल करना चाहेंगे. उच्च गुणवत्तापूर्ण, पहले से निर्मित ''कइयों के लिए एक'' मनोरंजन का युग अब इंटरेक्टिव (दर्शक को नैरेटिव चुनने का विकल्प देने वाला), इमर्सिव (3डी का एहसास देने वाला)

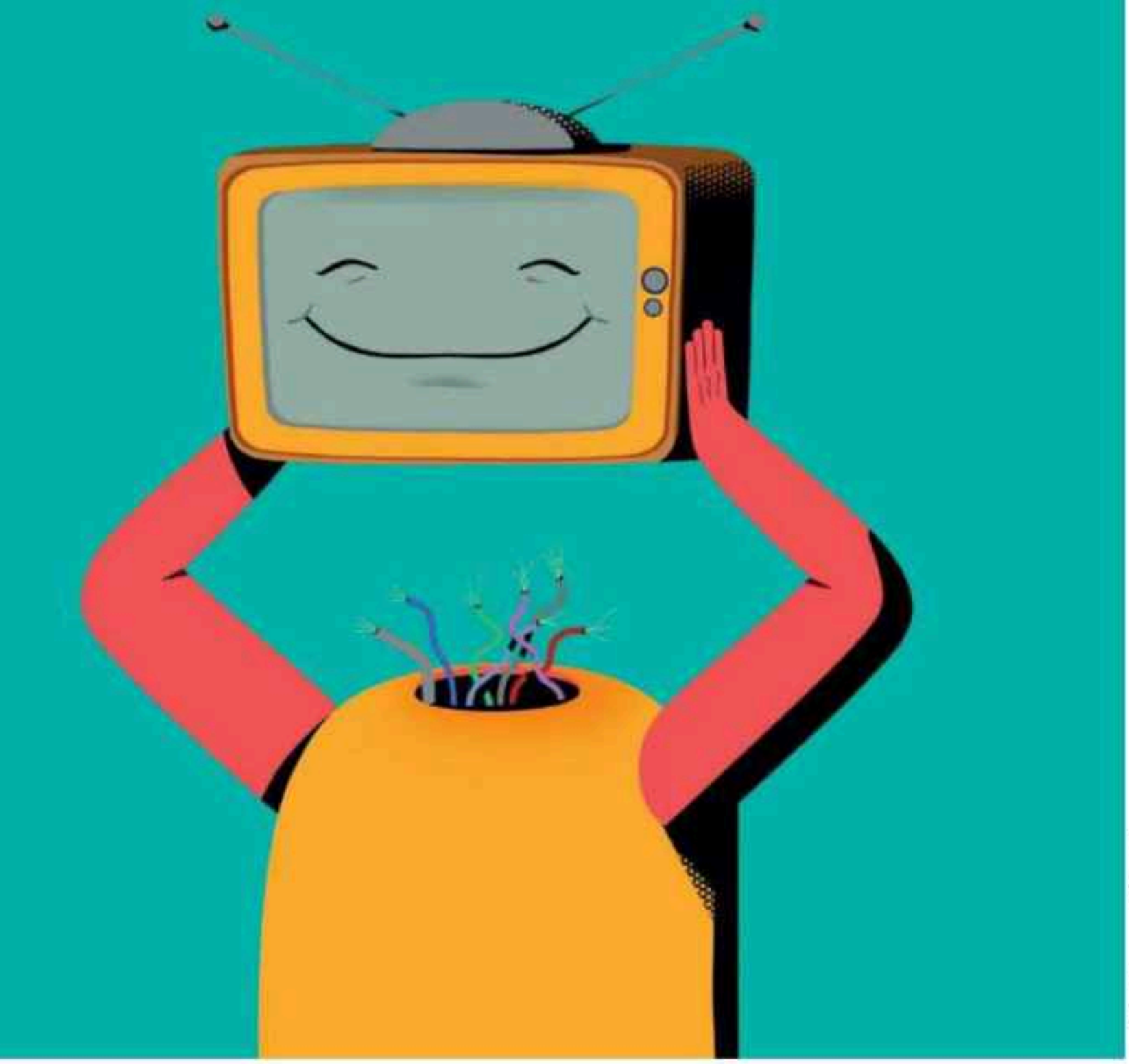

इलस्ट्रेशन: सिद्धांत जुम्डे

भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग अप्रत्याशित बढ़ोतरी के मुहाने पर खड़ा है. जिस तरह पिछला दशक विश्व में कोरिया की संस्कृति के विस्तार के नाम रहा, वैसे यह दशक भारत का है

और उनके हिसाब से ढले ''एक के लिए कई'' मनोरंजन के युग में बदल जाएगा.

नेटवर्क और के बल, दोनों ब्रॉडकास्ट टेलीविजन विकसित देशों के परिपक्व टीवी बाजारों में ''कॉर्ड-कटिंग'' के चलते गिरावट देख रहे हैं. भारत में अलबत्ता अच्छी-खासी आबादी वाले विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक जनसांख्यिकी समूहों में टेलीविजन और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म साथ-साथ बढ़ रहे हैं. आगे इसमें बदलाव होगा, पर अभी नहीं. यह हमें विरासत में मिली वृहद जनसांख्यिकी का अनूठा फायदा है. जब ढेरों लोग गरीबी से निम्न-आय से मध्यम-आय और उससे आगे की आर्थिक सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ रहे हैं, तमाम मीडिया प्लेटफॉर्मों पर एक साथ खपत बढ़ रही है. बाजार में मौजूद 30 से ज्यादा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बीच ''स्ट्रीमिंग वॉर'' जारी रहेगा. यह दर्शकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उन्हें अपना दिल बहलाने के लिए खूब विकल्प मिलते रहेंगे. सर्जकों, कलाकारों और ऑडियो-विजुअल उद्योग से जुड़े विभिन्न लोगों के लिए यह सुनहरा दौर है. भारत में डेटा दुनिया में सबसे सस्ता है, इसलिए वीडियो स्ट्रीम करने की कम कीमत दर्शकों की मनोरंजन की कभी तृप्त न होने वाली इच्छा को खूब पूरा करेगी. इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब वीडियो से लेकर जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (जीईसी) पर सोप ओपेरा और प्रीमियम क्वालिटी टीवी सीरीज और देश-दुनिया की विभिन्न भाषाओं से डब की गई और सबटाइटल वाली फिल्मों तक तमाम फॉर्मेट और अवधियों के कंटेंट की विविधता ने भारत को दुनिया में डेटा की सबसे ज्यादा खपत वाला देश बना दिया है.

स्टारडम की अवधारणा भी बदली है. टॉम क्रूज सरीखे वैश्विक फिल्म सितारों की जगह स्पाइडरमैन, आयरन मैन या डॉक्टर स्ट्रेंज सरीखे किरदार वैश्विक स्टारडम तक जा पहुंचे हैं. अब उन्हें परदे पर उतारने वाले अभिनेताओं के स्टारडम का समय नहीं रहा. इसी तरह भारत में *के.जी.एफ.* या *गोलमाल* सरीखी फ्रेंचाइज की अहमियत लगातार अर्थपूर्ण होती गई है. अब पहले की तरह अभिनेता के प्रति वैसे समर्पण का दौर नहीं रहा जो 1970 के दशक में अमिताभ बच्चन या 1990 के दशक में शाहरुख खान को हर फिल्म में हासिल था. हालांकि, अपवाद तो हमेशा होंगे ही. मगर यह जरूर मालूम होता है कि हर तरफ, हर एक पीढ़ी के भगवान बन जाने वाले सुपस्टार का जमाना लद गया है और उसकी जगह किरदारों और फ्रेंचाइज की कल्ट फैन फॉलोइंग का जमाना आ गया है.

लाइव एंटरटेनमेंट मीडिया और मनोरंजन कारोबार अभी एक बेहद उपेक्षित क्षेत्र है और अब तक यह कंटेंट केवल बड़े महानगरों के दर्शकों के उच्च सामाजिक-आर्थिक तबके तक सीमित है. इस क्षेत्र में धमाकेदार वृद्धि की अकूत संभावनाएं है, बशर्ते खास दर्शक वर्ग को लुभाने वाले कंटेंट के साथ-साथ अपेक्षाकृत छोटे शहरों में मौजूद मनोरंजन के नए अनुभवों की इच्छा को पूरा करके उनकी लगातार बढ़ती खरीद शक्ति का फायदा उठाते हुए कंटेंट बनाया जाए. आने वाले सालों में इस क्षेत्र पर नजर रखनी होगी.

कुल मिलाकर मैं मानता हूं कि हम भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग में अभूतपूर्व वृद्धि के दौर के मुहाने पर हैं. पिछले दशक में जिस तरह कोरिया को वैश्विक स्तर पर अपनी सांस्कृतिक पहचान के विस्तार का पल हासिल हुआ, बहुत कुछ उसी तरह अगला दशक भारत का होगा. इसके संकेत हमें कुछ समय पहले से ही दिखाई दे रहे हैं. हमारी कई फिल्में और सीरीज समुद्र पार करके वैश्विक मुख्यधारा के दर्शकों तक पहुंच रही हैं और ऑस्कर्स, गोल्डन ग्लोब्स और एमीज जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार और समारोहों में लोकप्रियता और स्वीकृति हासिल कर रही हैं. अभी तक यह छिटपुट रूप से ही होता रहा है, पर मैं एक बार फिर दिलेरी से कहने का जोखिम उठाकर कहूंगा कि 2030 तक भारत अपनी जानदार किस्सागोई और अनूठी आवाजों तथा विकल्पों के साथ लंबे समय तक दुनिया पर बने रहने वाला सांस्कृतिक असर पैदा करने वाली वैश्विक ताकत बन कर उभरेगा. मुझे लगता है 2023 वह साल है जब हम इस संभावना को हकीकत में बदलने के लिए कुछ बड़ी छलांगें लगा सकते हैं. ■

जनसांख्यिकीय लाभांश भुनाने का दौर

चिन्मय तुम्बे
एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, आइआइएम, अहमदाबाद

भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा. जनसंख्या के क्षितिज पर आने वाले ये बदलाव भारत की वैश्विक स्थिति को बदल सकते हैं और इसका भारत के भीतर क्षेत्रीय समीकरणों और आचार-व्यवहार पर असर पड़ेगा

इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

MAGAZINE KING

युक्त राष्ट्र के जनसांख्यिकीय अनुमान के मुताबिक, भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा. चीन ने एक अरब का मील का पत्थर 1980 के दशक की शुरुआत में पार किया, जब भारत की आबादी 80 करोड़ के आसपास थी. तभी से वन-चाइल्ड नीति और तेज आर्थिक वृद्धि ने चीन की जनसांख्यिकी राह को नाटकीय ढंग से बदल दिया, क्योंकि जन्म दर धड़धड़ाकर नीचे आ गई और आबादी 1.4 अरब के आसपास स्थिर होने लगी. भारत में परिवार नियोजन की नीति पर कमजोर अमल और चीन के मुकाबले धीमी आर्थिक वृद्धि के कारण ऊंची प्रजनन दरें कायम रहीं, जिससे आबादी का अंतर तेजी से मिटने लगा. कुछ अनुमानों के मुताबिक, चीन धमाकेदार जनसांख्यिकीय गिरावट के लिए तैयार है और तेजी से बढ़ता अफ्रीकी देश नाइजीरिया 21वीं सदी के आखिर तक दुनिया के दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के तौर पर चीन की जगह ले लेगा. भारत अलबत्ता सदी के लिए दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने को तैयार है. भारत इस मील के पत्थर तक कैसे पहुंचा, किस स्तर पर आबादी शिखर तक पहुंची और इसके क्या निहितार्थ हैं?

कुछ सैकड़ों लाख लोगों से एक अरब से ज्यादा लोगों तक भारत का जनसांख्यिकी विस्तार 1920 के दशक में शुरू हुआ. भारत की आबादी में 1921 से पहले के पांच दशकों में अकाल और महामारियों सरीखी बहुत ज्यादा मौतों वाली घटनाओं के कारण एक से दूसरी जनगणना के दौरान उतार-चढ़ाव आते रहे. उसके बाद हर दशक में भारत की आबादी बढ़ी. अकाल और बीमारियों की रोकथाम की बेहतर समझ और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की वजह से 20वीं सदी के दौरान मृत्यु दरों (खासकर शिशु और मातृ मृत्यु दर) में तेज गिरावट आई. जन्म दरें अलबत्ता 1960 के दशक में गिरना शुरू हुईं, कुछ तो शिशु मृत्यु दर में गिरावट आने के जवाब में और इसलिए भी कि गर्भ निरोधक तरीकों का इस्तेमाल बढ़ा. आबादी वृद्धि की तेज रफ्तार दरें 1950 के दशक से ही चिंता की बड़ी वजह रही थीं. इनके चलते 1976 में आपातकाल के दौरान अंतत: सामूहिक नसबंदी शिविर लगाए गए और परिवार नियोजन की जबरिया योजनाओं के खिलाफ जोरदार प्रतिक्रिया हुई.

> मौजूदा समय में हम जनसांख्यिकीय लाभांश लेने के चरण में हैं लेकिन भारत भी आखिर **तेजी से बूढ़ा तो होगा ही**

तब यह सोचा जाने लगा कि गिरती जन्म दरें बेहतर आर्थिक विकास की ओर ले जा सकती हैं, पर पिछले पांच दशक के वैश्विक अनुभव ने दिखाया कि दोनों के बीच रिश्ता बिल्कुल उलटा था, या जैसा कि कुछ लोगों ने कहा, ''विकास सबसे अच्छा गर्भनिरोधक है.'' सीधे-सादे शब्दों में कहें, तो ज्यादा संपन्न और बेहतर शिक्षित परिवारों ने कम बच्चों को जन्म देना चुना. देश में ही इसके सबसे अच्छे उदाहरण देखे गए, जहां दक्षिण भारत, उत्तर के अंत: प्रदेशों के मुकाबले ज्यादा तेजी से विकसित हुआ और साथ ही वहां प्रजनन में तेज गिरावट तथा आबादी की वृद्धि दर भी कम थी.

भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1980 के दशक के दौरान प्रति वर्ष 2 फीसद से कुछ ज्यादा के शिखर पर पहुंची और उसके बाद गिरने लगी. जनसंख्या वृद्धि दर गिरने के साथ एक नए राजनैतिक मुद्दे को अहमियत मिली. धार्मिक राष्ट्रवादियों ने कहा कि प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दरें गिर रही हैं, पर वे मुसलमानों के मुकाबले हिंदू आबादी में ज्यादा तेजी से गिर रही हैं. आगे यह भी कहा गया कि अगर इस पर लगाम नहीं कसी गई, तो मुसलमान भारत में अंतत: हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे. मुसलमानों में जन्म दर हिंदुओं से ज्यादा तो थी ही, पर इस अंतर को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया. भारत की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 1961 में कुछेक प्रतिशत अंकों से 2011 में करीब 14 फीसद तक मामूली बढ़ी. मगर वैश्विक आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी भी करीब 12 फीसद से बढ़कर 14 फीसद हो गई, क्योंकि समग्र जनसंख्या वृद्धि दरें दुनिया की दूसरी जगहों के मुकाबले भारत में इतनी ज्यादा थीं.

ज्यादा जन्म और मृत्यु दरों से कम जन्म और मृत्यु दरों के जनसांख्यिकी बदलावों की बदौलत आबादी में आयु समूहों के ढांचे बदल जाते हैं और जिसकी वजह से वह घटित होता है जिसे अर्थशास्त्री 'जनसांख्यिकी लाभांश' कहते हैं. यानी कुल आबादी में कामकाजी आयु समूह (15-65) की हिस्सेदारी पहले बढ़ती है और फिर वृद्ध आयु समूहों (65+) की हिस्सेदारी अच्छी-खासी बढ़ने पर कम होने लगती है. पहला दौर आबादी की ज्यादा उत्पादन क्षमता के लिहाज से लाभांश की ओर ले जाता है. भारत इसी दौर से गुजर रहा है, पर केरल और तमिलनाडु सरीखे कई राज्य दूसरे दौर में जा चुके हैं और तेजी से बूढ़े हो रहे हैं.

भारत में बीते दो दशकों में प्रजनन में गिरावट की गति तेज हुई. जनसांख्यिकीविद् एक आंकड़े की चर्चा करते हैं जिसे कुल प्रजनन दर कहा जाता है और प्रति महिला 2.1 बच्चों की राशि मोटे तौर पर स्थिर जनसंख्या दर्शाती है, यानी ऐसी आबादी जो हर पीढ़ी के साथ खुद को बदलती है. हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2.1 से कम है, जिसमें बिहार की 2.98 से सिक्किम की 1.1 तक काफी अंतर है. अब के बाद और धीमी जनसंख्या वृद्धि दरों का निहितार्थ यह है कि भारत की आबादी, जो फिलहाल 1.4 अरब है, 21वीं सदी में 2 अरब का आंकड़ा पार नहीं करेगी और अब से कुछ दशकों में करीब 1.7 अरब के शिखर पर पहुंच सकती है.

भारत की मौजूदा और पहले से देखी जा सकने वाली जनसांख्यिकीय यात्रा के कम से कम तीन स्पष्ट निहितार्थ हैं. पहला, आबादी के मामले में चीन पर भारत की बढ़त आने वाले दशकों में सैकड़ों लाख लोगों तक अच्छी-खासी बढ़ने जा रही है और यह उस दस्तावेजी बढ़त से काफी ज्यादा होगी जो चीन को भारत के ऊपर हासिल थी. अगर भारत की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है और चीन के बराबर आ जाती है और उससे आगे निकल जाती है, तो इसका मतलब होगा कि भारत 2050 तक समुचित रूप से चीन से ज्यादा बड़ा बाजार और अर्थव्यवस्था होगी. इससे भूराजनैतिक वजन हासिल होगा और दुनिया की महाशक्तियों के तौर पर भारत को अंतत: अमेरिका और चीन के साथ जोड़कर देखा जाने लगेगा.

दूसरे, भारत के भीतर, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सामने आ रहे जबरदस्त अंतरों का भारी दबाब संघीय प्रणाली पर पड़ेगा और खासकर लोकसभा में सीटों के आवंटन पर विचार करते समय पड़ेगा. परिसीमन की कवायदों से दक्षिण भारतीय राज्यों को नुक्सान होगा और दरअसल संसद में कम सीट हिस्सेदारी के जरिए उन्हें उत्तर के मुकाबले ज्यादा तेजी से विकसित होने की सजा मिलेगी. इसके अलावा उत्तर-दक्षिण के फर्क की वजह से लोग उत्तर से दक्षिण की ओर जा सकते हैं, उसी तरह जैसे पश्चिम के बुढ़ाते समाज अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देने के लिए ज्यादा प्रवासियों को जज्ब कर रहे हैं.

आखिर में, जापान और चीन के मुकाबले युवा देश होने की चर्चाओं के बीच भारत की कुल आबादी में बुजुर्ग आबादी की हिस्सेदारी अब के बाद तेजी से बढ़ने जा रही है. इस आबादी को सहारा देने के लिए बेहतर राजकोषीय प्रबंधन और 65 की उम्र के बाद भी काम करने को बढ़ावा देने की जरूरत का बढ़ना तय है. बुढ़ाते जापान में बुजर्गों के डाइपर की बिक्री ने बच्चों के डायपर की बिक्री को पीछे छोड़ दिया है. उस अवस्था में पहुंचने से पहले हमारे पास अभी कुछ दशक और हैं. ■

पृथ्वी को बचाने में क्या भूमिका निभा सकता है भारत

श्याम सरन
जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री के विशेष दूत (2007-2010)

भारत को सिर्फ जुबानी जमाखर्च के बजाए कुछ कर दिखाने का उदाहरण पेश कर नेतृत्व के लिए आगे आना चाहिए. यह पहल किसी अंतरराष्ट्रीय पारिस्थितिकी सम्मेलन के माध्यम से होना शायद ज्यादा बेहतर रहेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान 'लाइफ' के अक्षरों का विस्तार कर इसको मायने दिया—पर्यावरण के लिए जीवनशैली. यह एक अहम पहल की घोषणा की थी. यह हमारे ग्रह के पर्यावरण संतुलन को साधे रखने वाली जीवनशैली अपनाने के विश्वव्यापी अभियान को गति देने का एक प्रयास है. यह बताता है कि मौजूदा पारिस्थितिकी संकट हमारी जीवनशैली के मूल्यों में गिरावट का नतीजा है. और जब तक यह मूल्य प्रणाली नहीं सुधरती तब तक पारिस्थितिकी संकट दूर होने की कोई संभावना नहीं है. विश्वसनीयता हासिल करने और अन्य देशों के लिए एक उदाहरण बनने के लिए प्रधानमंत्री की यह पहल भारत की अपनी आर्थिक विकास रणनीति में शामिल होनी चाहिए.

भाजपा-नीत सरकार अक्सर भारत के गौरवशाली अतीत, प्राचीन सभ्यता और चिरस्थायी ज्ञान की याद दिलाती है. भारतीय संस्कृति में प्रकृति को विभिन्न रूपों में पूजा जाता है, वह एक मां है, पालनहार है और उसे सौंदर्य का प्रतीक भी माना जाता है. यह आधुनिक औद्योगिक सभ्यतावादी सोच के विपरीत है, जिसमें प्रकृति को एक ऐसी डार्क फोर्स माना जाता है जिसे नियंत्रित करके मानवता की सेवा के लिए

इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

इस्तेमाल किया जाना चाहिए. यही वह रवैया है जिसने हमारे ग्रह को तबाह कर रखा है. आज भारत भी इस दुष्चक्र में फंसा है. यह रातो-रात कोई बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन स्पष्ट तौर पर किसी मध्यवर्ती लक्ष्य के साथ एक दीर्घकालिक रणनीति तैयार करके अपने विकास को पारिस्थितिकी स्तर पर अधिक स्थिर रास्ते की ओर उन्मुख कर सकता है. भारत की तरफ से कॉप-27 में सामने रखी दीर्घकालिक रणनीति इस संबंध में निराश करने वाली है जिसके तहत 2070 तक कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो पर लाने का लक्ष्य रखा गया है.

लाइफ पर व्यावहारिक तौर पर अमल के लिए भारत क्या कर सकता है?

भारत जैसे लोकतंत्र में सभी नागरिक वाहन रखने के हकदार हैं. यह वाहन मालिक होने और उसे चलाने की पात्रता से अलग मामला है. इस समय भारत में वाहनों का घनत्व 32 प्रति हजार है, जबकि यूरोप में यह 800 प्रति हजार और अमेरिका में प्रति हजार व्यक्ति पर 900 वाहन है. अगर भारत इतने वाहन घनत्व का एक हिस्सा भी हासिल करना चाहे तो उन्हें चलाने के लिए दुनिया का सारा तेल पर्याप्त नहीं होगा. अगर ऐसा हो भी जाए तो भी न तो कारों को पार्क करने के लिए पर्याप्त जगह होगी और न ही उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त सड़कें और राजमार्ग. इसका थोड़ा टिकाऊ समाधान यह होगा कि भारी-भरकम टैक्स लगाकर निजी कारों को हतोत्साहित करने के साथ प्रभावी और किफायती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की कोशिश की जाए. भारी-भरकम राशि खर्च करके छह लेन के राजमार्गों और शहरी फ्लाइओवर्स के निर्माण की जगह प्रभावी रेल और नदी परिवहन के विकास पर ध्यान देना होगा.

> भारत में परिवहन की टिकाऊ व्यवस्था बनाने के लिए जरूरी होगा कि सस्ते और सक्षम **सार्वजनिक परिवहन तंत्र का विकास किया जाए**

भारत अभी भी मुख्यत: एक कृषि प्रधान देश है और इसकी 1.4 अरब आबादी के 58 फीसद हिस्से के लिए कृषि ही आजीविका का साधन है. देश अब भी गहन कृषि विकास कार्यक्रम (आइएडीपी) वाली रणनीति में सीमित है जो 1960 के दशक की हरित क्रांति की याद दिलाती है. उस समय तो यह बहुत सफल रही थी लेकिन पिछले कई दशकों से फायदे का सौदा साबित नहीं हो रही. हरित क्रांति के दौरान अच्छी पैदावार के लिए रासायनिक उर्वरकों और पानी के सघन इस्तेमाल के साथ-साथ संकर गेहूं और चावल के बीजों का उपयोग किया जाता था. फसल घनी होने के कारण यह कीट-पतंगों को आकृष्ट करती और इनसे निपटने के लिए कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल होता. समय के साथ-साथ मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता घटती चली गई, जिससे धीरे-धीरे उर्वरकों और पानी की जरूरत बढ़ती गई. अधिकांश क्षेत्रों में जल स्तर तेजी से गिरा है, जिससे गहन जल संकट उत्पन्न हो गया. रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल के कारण पानी के दूषित होने का मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. ऐसे घातक रसायन इस्तेमाल करने वाले किसान शायद ही कभी मुंह पर कपड़ा बांधने जैसे सुरक्षात्मक उपायों को अपनाते हैं और यही वजह है कि त्वचा, सांस संबंधी और आंखों की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं. कई प्रामाणिक और टिकाऊ विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद भारतीय कृषि उत्पादन उसी ढर्रे पर चल रहा है, जो काफी पहले अपनी उपयोगिता खो चुका है और हमारे जल स्रोतों को दूषित कर रहा है, हमारी मिट्टी को बंजर बना रहा है और हमारी ग्रामीण आबादी को बीमारी और मौत के कगार पर पहुंचा रहा है. ऐसे में केवल फसल की पैदावार पर ध्यान देने के बजाए किसानों को व्यावहारिक तौर पर आर्थिक एजेंट बनाने पर केंद्रित कृषि विकास की नई और टिकाऊ रणनीति की जरूरत है.

ग्लोबल मॉडल बनने की आकांक्षा रखने वाले भारत को भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु और पारिस्थितिकी के मोर्चे पर नेतृत्व के लिए आगे आना चाहिए. अपने क्षेत्र में सबसे बड़े, सबसे सक्षम देश के तौर पर भारत एक दक्षिण एशियाई जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना और पारिस्थितिकी पर समेकित योजना विकसित करने में मददगार हो सकता है. हिमालय में ग्लेशियरों का पिघलना लगातार तेजी से बढ़ रहा है और अगर इस पर काबू न पाया गया तो उपमहाद्वीप की बारहमासी नदियां बारिश के मौसम में बहने वाली धाराएं बनकर रह जाएंगी. ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जलस्तर में वृद्धि न केवल श्रीलंका और मालदीव जैसे द्वीपीय देशों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न करेगी, बल्कि बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में निचले डेल्टाई मैदानों के लिए भी संकट बढ़ सकता है. उपमहाद्वीप की नदियां जीवित प्रणालियां हैं और विभिन्न देशों के बीच उनके प्रवाह को खंडित करके निजी संपत्ति की तरह बांटा नहीं जा सकता. इसी तरह जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए क्रॉस बॉर्डर फॉरेस्ट कॉरिडोर हमारी जरूरत हैं. पूरे दक्षिण एशिया को सतत विकास का एक मॉडल बनाने के लिए भारत को अपने सभी दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ मिलकर काम करना होगा और यह वैश्विक मॉडल बनने की आकांक्षाओं के मद्देनजर भारत की साख को बढ़ाएगा. पारिस्थितिकी के लिहाज से एक अभिन्न क्षेत्र दक्षिण एशिया में अकेले राष्ट्रीय स्तर के समाधान कारगर नहीं होंगे. हमारी नदियां, हमारे पहाड़, हमारे जंगल और हमारे वन्य जीव, सभी हमारी साझी विरासत हैं और हमारी जगहों को साझा करते हैं. इन्हें केवल क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से ही स्थायी तौर पर संरक्षित किया जा सकता है. यह कहा जा सकता है कि लाइफ पहल को वैश्विक बनाने से पहले क्षेत्रीय बनने की जरूरत है.

भारत इस समय दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों के समूह जी-20 का अध्यक्ष है. भारत की अध्यक्षता में 2023 में होने वाला शिखर सम्मेलन हमारे ग्रह के अस्तित्व के लिए खतरा बने पारिस्थितिकी संकट को हल करने का एक मंच मुहैया करा सकता है. बीता वर्ष जलवायु परिवर्तन और संबंधित चुनौतियों से निपटने के वैश्विक सहयोगात्मक प्रयासों के दो अवसर गंवा देने के तौर पर याद किया जाएगा, लेकिन जैव-विविधता की क्षति एक ज्यादा बड़ी चुनौती है. नवंबर में मिस्र के शर्म अल-शेख में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (कॉप-27) और मॉन्ट्रियल में जैव-विविधता सम्मेलन (कॉप-15) के नतीजे जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की क्षति से जुड़े वैश्विक पारिस्थितिकी संकट को सुलझाने के लिए तत्काल कार्रवाई की अंतरराष्ट्रीय अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले नहीं रहे.

इसी आधार पर, संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया—समुद्र हमारी कुल जरूरत की 50 फीसद ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के पूरे उत्सर्जन का 25 फीसद हिस्सा अवशोषित करता है और उत्सर्जन की वजह से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त गर्मी का 90 फीसद हिस्सा सोख लेता है. यह न केवल इस ग्रह का फेफड़ा है बल्कि सबसे बड़ा कार्बन सिंक भी है—जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को घटाने वाला एक महत्वपूर्ण बफर है.

महासागरों में प्लास्टिक और खतरनाक कचरे की डंपिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अम्लीकरण और ऊष्मा का स्तर बढ़ने के साथ उनकी कार्बन सिंक करने की क्षमता घटती जा रही है. ऐसे ही कई अन्य फीडबैक लूप हैं जिन पर संभवत: एक अंतरराष्ट्रीय पारिस्थितिकी सम्मेलन के तहत पर्यावरणीय संकट को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है. जी-20 अध्यक्ष के तौर पर भारत इस तरह के दृष्टिकोण के साथ एक अगुआ की भूमिका निभा सकता है.

भारत को सिर्फ जुबानी जमाखर्च के बजाय कुछ कर दिखाने का उदाहरण पेश कर नेतृत्व के लिए आगे आना चाहिए. ■

बी.बी.आर. सुन्नू
[illegible]

यह साल बिजली वाहनों का होगा

बिजली वाहनों के क्षेत्र में उत्पति बेमिसाल, साथ बिक्रीदार्थ एक करोड़ सुपरिमित वाहनों तक सीमित

MAGAZINE KING

नी ति आयोग के 2016 में 2032 अनुमान में उच्च बिक्री वाला था कि इलेक्ट्रिक और ब्याज एक्सिडेंट का चीन में 2032 तक चालीस प्रतिशत में 1 मोबाइल की आधुनिक और दोपहर तक्का ट्रेक्टर के पहले में 50 लाख सर्विस तक नहीं चलना तो लगाते हैं. लेकिन उसमें अनुमान पास हुई. तब बिजली स्वास्थ्य परिवहन योगी विशेषज्ञ मंत्रालयों ने लोगन को कि 2032 तक चलना लगत और बिंदु को गोदि होने इलेक्ट्रिक्स लाखों का 120 मोबाइल इलेक्ट्रिकल. बिना पास था. आँटो उद्योग के नहीं लोगों के बेचने का बिक्री की लाखों तक आई. उसे पास लगत अन्तर्राष्ट्रीय लगत. ति आयोग के आँकड़ों से अनुमान नहीं था, लेकिन उसमें बिक्री से चलना था. कुल हमने बना बीते चलने चला चलने का लगत पुराना और इंजिन शक्ति दूत मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के उपलब्ध की बनना कि इलेक्ट्रिक रिक्शा (ई-रिक्शा), बिजली (ई-साइकिल) और छोटे चार पहिए व्यक्तिगत चलने के लक्ष्य में 2032 तक हमका हमेशा 120 परिवार करार रहता है. यही पिछे साल हमें भी कि उपलब्ध बिक्रीय दोपहर की अनुकूल व्यवस्था को और मुहावरा में ई-चालन को और बस करने लायें के लिए चलने का उसकी इकट्ठाकृत्रिम पास्तु. अर्थात् पिछले ई- चलती की कुल लगत मैंने भी अंतर्राष्ट्रीय दाम दूसरा (अवसर्ड) चली पेट्रोल-डीजल चालने का बाजार परिवार का हैं.

इस अवार रिपोर्ट 2022 के पीछे लगाया गये. कम अनुमानों से पता चला कि 2022 में भेज रिक्शा चली इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई-स्कूटर एवं ई-बाइक) की बिक्री 6,25,000 तक के आसपास है. जो 2021 में 15,723 से लगभग 150 फीसद ज्यादा है और इसमें सीएनजी/एलपीजी जैसे ईंधन वाले दोपहिया—स्कूटर और मोटरसाइकिल—वाले फीचर शामिल नहीं हैं. इसी तरह तिपहिया ऑटो रिक्शा (ई-रिक्शा) बिक्री का ई-रिक्शा (ई-रिक्शा) की बिक्री 2022 में 5 फीसद से है. लेकिन ऐसे अनुमान कि ऐसे लगत ई-रिक्शा की बिक्री की संख्या का 10 गुना तक हो गई है. यानी 2022 में ई-रिक्शा का 40 गुना का और सभी का आंकड़ा पूरी. और अनुमान दिखाते, 2022 तक कुल दोपहिया आधा से 50 फीसद बिक्रीदारी ई-रिक्शा की होंगे. तब तिपहिया रिक्शा बनाने में ई-रिक्शा के लिए बैटरी की लगत-आवश्यकता की पहली इकाई

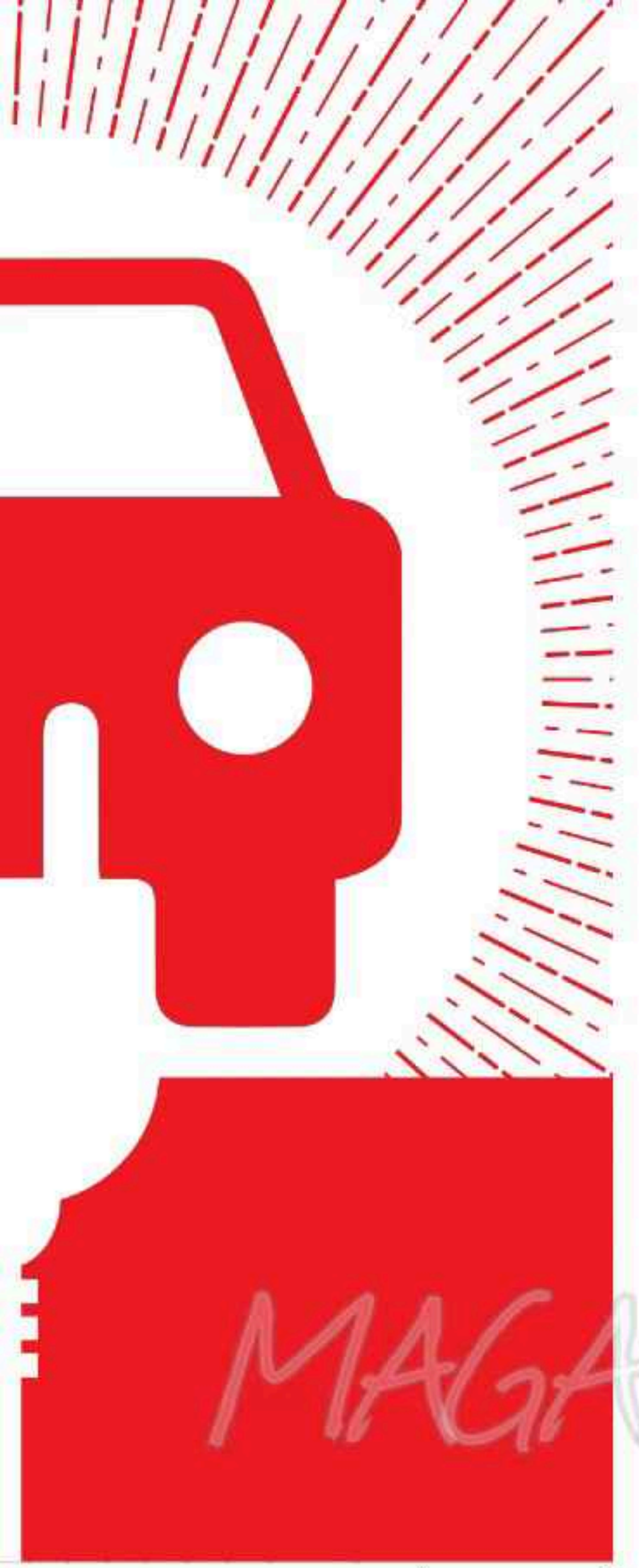

इलस्ट्रेशनः तन्मय चक्रवर्ती

स्थापित कर दी है. सरकार के मुताबिक, स्वैपिंग नियमों को जनवरी 2023 के अंत तक पक्का कर लिया जाएगा. संकेत कहते हैं कि उद्योग की दिशा बदलने जा रही है. 2024 की शुरुआत तक, हम बड़े पैमाने पर बैटरी-ऐज-अ-सर्विस (बीएएएस) को बुनियादी ढांचे के खड़ा होने की उम्मीद कर सकते हैं. मौजूदा वितरण नेटवर्क के लिहाज से शुरू में ये शीर्ष 10 शहरों में बनाए जा सकते हैं. मौजूदा कर संरचनाओं के साथ तेज रफ्तार ई-दोपहिया उपभोक्ताओं के तीन साल के लिए केवल 100 रुपए प्रति दिन पर उपलब्ध हो सकती है, और उसके साथ मासिक 'पैकेज्ड-एनर्जी' सेवा भी, जिसकी कीमत एक लीटर पेट्रोल से कुछ ही अधिक है. बेहतर प्रदर्शन, उपभोक्ता-मशीन का आधुनिक तालमेल, और लगभग शून्य रखरखाव खर्च के लाभों के साथ, ई-दोपहिया का अर्थशास्त्र इतना आकर्षक हो सकता है कि बाजार इस तरफ मुड़ सकता है.

पिछले कुछ वर्षों में उद्योग जगत का ध्यान मेटल संबंधी हुनर से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ा है, उत्पादन और वितरण के प्रतिमान बदले हैं. 2023 के अंत तक टेक्नोलॉजी-केंद्रित नए आगंतुक ई-दोपहिया के कुल बाजार में 40 फीसद से अधिक के हिस्सेदार हो सकते हैं. कल्पना कीजिए, कोई अगर मौजूदा दोपहिया इंजन को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या मजबूत हाइब्रिड में बदलने के लिए कोई रेट्रो-फिटमेंट किट बाजार में उतार दे. इस संभावित बाजार में 15 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हो सकते हैं. नतीजे अच्छे रहे तो असर इतना व्यापक होगा कि वाहन बाजार में 2030 से पहले ही ई-वाहनों की धूम मच सकती है. इसके लिए ब्रांड निर्माण का नजरिया चाहिए.

इस बीच, तिपहिया बाजार पूरी तरह इलेक्ट्रिक हो रहा है. 2022 में कुछ तिपहिया पंजीकरण में ई-तिपहिया और ई-रिक्शा संयुक्त हिस्सेदारी आधे से अधिक है. 2019 के बाद से आइसीई वैरिएंट की मात्रा में 50 फीसद गिरावट आई है, जबकि ई-वैरिएंट में 100 फीसद से ज्यादा वृद्धि हुई है. हालांकि कुल ई-वैरिएंट में ई-रिक्शा की हिस्सेदारी करीब 90 फीसद है. भले शुद्धतावादी बेढंगे कॉन्ट्रासेप्शन पर नाक-भौं सिकोड़ते हैं, लेकिन उनकी भी जरूरतें पूरी हो सकती हैं. उच्च हॉर्स पावर मोटर्स, ली-आयन बैटरी, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम और बेहतर बॉडी की उपभोक्ता अपेक्षाओं के साथ यह उम्मीद है कि 2030 से पहले 100 प्रतिशत ई-वाहन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

> बिजली से चलने वाले दोपहिया वाहनों का अर्थशास्त्र **बहुत बड़ी सख्या में लोगों को पारंपरिक इंजन** से नए वाहनों की तरफ ला सकता है

कार यानी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) क्षेत्र हमेशा पीछे चलता है. छोटे आधार के कारण इसमें बदलाव के आंकड़े पहली नजर में प्रभावशाली लगते हैं. 2022 में बेची गई 30,000 से अधिक इकाइयों में, बीईवी कारें पिछले साल देश में कुल कार पंजीकरण का लगभग 1 फीसद ही रही हैं. कीमत निर्धारण मामले के केंद्र में बैटरी है. भले ही हम कम क्षमता वाले पैकेज देखें, बैटरी पूरी तरह से सीमित वैश्विक आपूर्ति पर निर्भर रहेगी. मसलन, जिंबाब्वे ने असंसाधित लिथियम अयस्कों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर लिथियम खनन और अयस्क-लाभकरण का काम चीनी कंपनियों को सौंप दिया है. इस रुझान के तेज होने की ही उम्मीद है और इसमें कोबाल्ट भी जुड़ सकता है. क्या लिथियम निर्यातक देशों का संगठन (ओएलईसी) नई तकनीक वाला ओपेक बन जाएगा? अमीर देशों में ईवी परियोजनाओं के लिए कच्चे माल की बढ़ती मांग और लिथियम उत्पादकों का कार्टेलाइजेशन केवल कीमतों को बढ़ाने का काम कर सकता है. भारत जैसे देशों में बड़े पैमाने पर उपभोक्ता मांग केवल कीमत से तय हो सकती है. न ही कारों के लिए बैटरी बदलना कोई व्यावहारिक हल है. सॉलिड स्टेट और न्यू केमिस्ट्री जैसी टेक्नोलॉजी के विकास से बैटरी का आकार छोटा करने में मदद मिल सकती है, लेकिन 2026 से पहले इसकी कोई खास उम्मीद नहीं है. भारत में बीईवी कारें महंगी कारों तक ही सीमित रह सकती हैं. हाइड्रोजन फ्यूल सेल ईवीएस (एफसीईवी) और मजबूत हाइब्रिड इंजन ही भारतीय बाजार के लिए सबसे प्रभावी समाधान हैं.

जहां तक बसों की बात है, तो बीईवी बसों पर अंधाधुंध जोर से ज्यादा कोई गैर-मुनासिब सलाह नहीं हो, जो प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भरता पर जोर का मजाक बना रहा है, और यह हमारे शहरी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को ड्रैगन के पंजों में सौंप देगा! मौजूदा सिटी बस बेड़े को 'ट्रॉली बसों' में परिवर्तित करना और पूरी तरह से स्वदेशी शहरी पावर ग्रिड के जरिए चलाना एक सरल, अधिक बुद्धिमान और किफायती समाधान हो सकता है. इसलिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन पर सरकार की घोषणा कोई जल्दबाजी नहीं है. उम्मीद है, अनुसंधान खर्च का कुछ हिस्सा बायोमास से बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन विकसित करने पर खर्च होगा, जिससे कम लागत में हाइड्रोजन एफसीईवी बसों की जरूरत पूरी हो सकती है. अनुमान है कि सिर्फ 20 करोड़ टन कृषि अवशेषों से भारत सालाना 50 लाख टन तक 'हरित' हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है, जो कम से कम आधे इंटरसिटी बसों के बेड़े की जरूरतें पूरी कर सकता है. ■

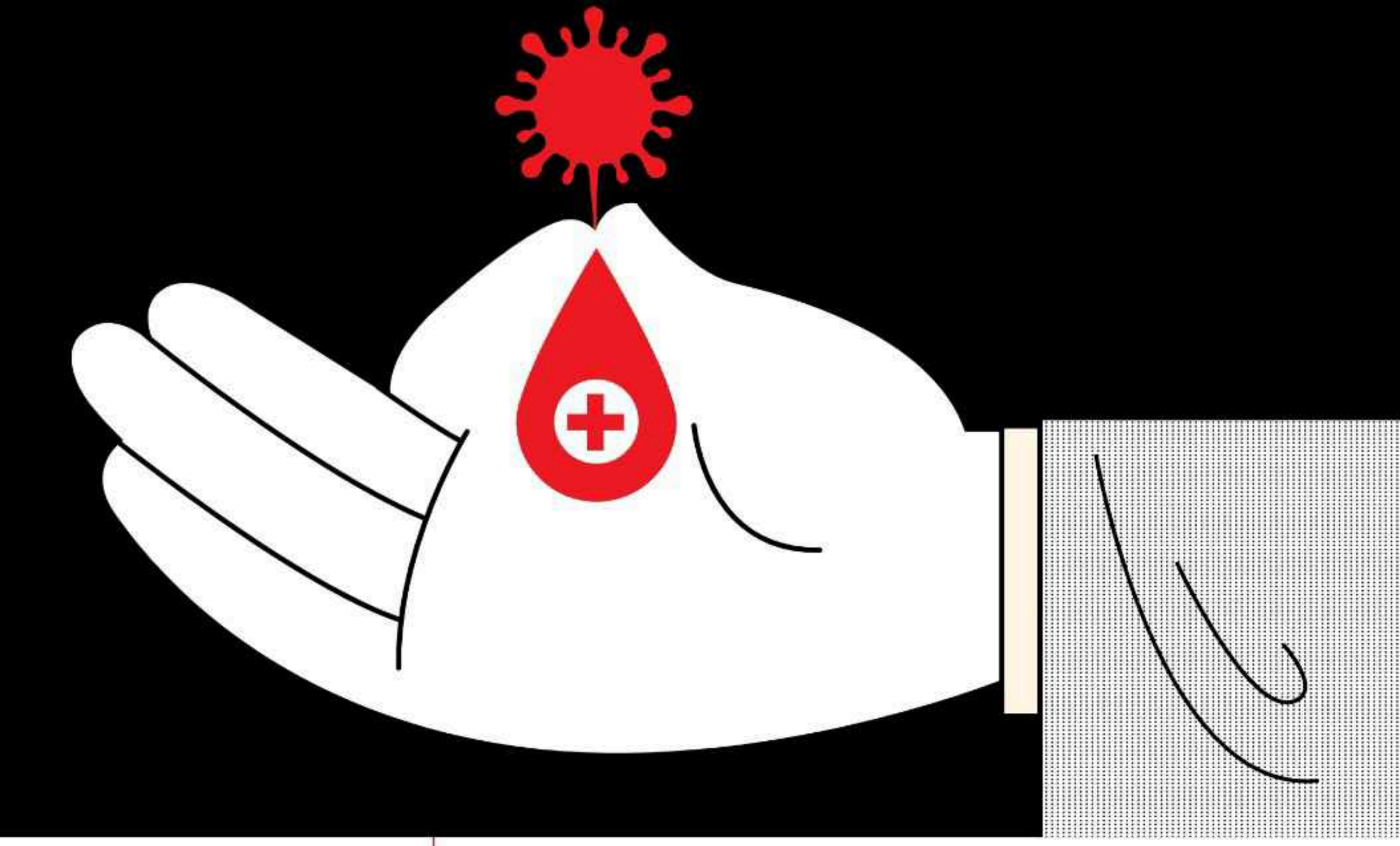

सौम्या स्वामीनाथन
पूर्व चीफ साइंटिस्ट
डब्ल्यूएचओ

तीन साल की महामारी ने पढ़ाया हमें जो पाठ

दुनिया भर की वैज्ञानिक और जनस्वास्थ्य सेवा से जुड़ी बिरादरी को सेहत का एक सर्वांगीण नजरिया अपनाते हुए मिलकर काम करना होगा. अब सवाल यह नहीं कि अगली महामारी आएगी या नहीं, बल्कि यह है कि कब आएगी

कोविड महामारी ने मानवता के सामने अप्रत्याशित चुनौती पेश की और यह बात अच्छी तरह समझा दी कि हमारी बेहतर माली हालत के लिए अच्छी सेहत बेहद जरूरी है—देशों ही क्यों, पूरी दुनिया के लिए. यह बीती दो सदियों का सबसे बड़ा आर्थिक झटका था, जिसमें वैश्विक अर्थव्यस्था ने 8 खरब डॉलर से ज्यादा गंवाए. इतना ही नहीं, इसका दंश गरीब देशों और लोगों ने झेला, जिससे दुनिया में गैरबराबरी और बढ़ गई. अंदेशा यह भी है कि बड़े पैमाने पर स्कूल बंद होने से प्रभावित छात्रों की मौजूदा पीढ़ी 17 खरब डॉलर के बराबर की जिंदगी भर की कमाई गंवा सकती है. कोविड ने यह भी दिखाया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किए गए निवेश से मिलने वाला फायदा बहुत ज्यादा हैं और वायरस के प्रभावों पर फतह पाने का ज्ञान और औजार विज्ञान से ही आते हैं. इसने देशों के लिए जनस्वास्थ्य और प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, खासकर इसे अंजाम देने वाले लोग और ऑक्सीजन सरीखी अनिवार्य वस्तुओं में निवेश की जरूरत पर बल दिया. बदकिस्मती से इसने विश्वव्यापी खतरे का जवाब देने के मामले में अंतरराष्ट्रीय एकजुटता की कमी और भूराजनीति की भूमिका को भी उघाड़कर रख दिया. राष्ट्रवाद और अदूरदर्शी नीतियों के चलते तमाम समुदायों को भारी असमानताएं

इलस्ट्रेशनः तन्मय चक्रवर्ती

झेलनी पड़ीं. सोशल मीडिया के जमाने की इस पहली महामारी का नतीजा 'इन्फोडेमिक' या सूचना-महामारी की शक्ल में सामने आया, जिसमें कई भ्रामक और गलत जानकारियां शामिल थीं, जिन्होंने लोगों को मास्क पहनने और टीके लगवाने सरीखे सुरक्षा के तमाम उपायों के बारे में गुमराह किया.

अब जब दुनिया महामारी के दौर से धीरे-धीरे उबर रही है, वायरस के विकास के बारे में अब भी कुछ अनिश्चितताएं हैं, पर अब हमारे पास वायरस से लड़ने के ढेरों औजार भी हैं, इसलिए हमें जनस्वास्थ्य की बड़ी चुनौतियों का मुकाबला करने की भावी योजना बनाकर सेहतमंद आबादी तैयार करनी चाहिए. आज भारत में अकाल मृत्यु (70 साल की उम्र से पहले मौत) का मुख्य कारण गैर-संक्रामक रोग या एनसीडी (दिल की बीमारी, डायबिटीज, लकवा, कैंसर, गंभीर सांस रोग) हैं. इसमें रोकथाम की अहम भूमिका है और इसका मतलब जोखिम के कारकों यानी खान-पान, शारीरिक हलचल, वायु प्रदूषण, तंबाकू, शराब आदि पर ध्यान देने के अलावा जांच के जरिए रोग का जल्द पता लगाने, बेहतर डायग्नोस्टिक और सस्ते इलाज पर ध्यान देना भी है. बीमारियों का असर कम करने के लिए सरकार को आगे बढ़कर जिम्मा संभालना होगा, जिसमें निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी की भूमिका भी अहम है. सेहत पर असर डालने वाली व्यावसायिक चीजों पर नीतिगत कार्रवाई की जरूरत बढ़ती जा रही है. इसमें खाने की चीजों में ट्रांस फैट पर पाबंदी, तंबाकू के सेवन पर नियम-कायदे और टैक्स लगाना, मोटे अनाजों को जन वितरण प्रणाली में शामिल करवाकर उनकी खपत को प्रोत्साहित करना और स्कूलों में अत्यधिक चर्बी, नमक और चीनी वाले खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री को नियम-कायदों के दायरे में लाना शामिल है.

प्रबुद्ध और स्वस्थ आबादी के निर्माण के लिए विज्ञान और स्वास्थ्य साक्षरता अहम पहलू होंगे. यह स्कूलों से शुरू होना चाहिए, पर सभी उम्र के लोगों को भी भरोसेमंद और बेहतर जानकारियां आसानी से समझ आने वाले तरीकों से देने की जरूरत है. अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए अक्सर व्यवहार में बदलाव, सामाजिक सहारे और प्रोत्साहन की जरूरत होती है. हमारे जनस्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में समाज विज्ञानी, व्यवहार अर्थशास्त्री और मानवविज्ञानी शामिल होने चाहिए. साथ ही, संचार रणनीतियों को सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के अनुरूप ढालने की जरूरत है. सोशल मीडिया की व्यापक पहुंच को देखते हुए सरकारी जनस्वास्थ्य महकमों को ऐसे समूह बनाने चाहिए जो 'इन्फोडेमिक्स' या सूचना की महामारी से निबटें और गलत जानकारी के प्रसार का पहले से अंदाज लगाने, निगरानी करने और जवाब देने के हुनर से लैस हों. हर राज्य और केंद्र में अलग जनस्वास्थ्य कैडर बनाना भी अहम है. बीमार लोगों का इलाज करने वाले क्लीनिशियन और रोगों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले जनस्वास्थ्य कैडर (डॉक्टर, महामारी विशेषज्ञ, नर्सें, पोषण विशेषज्ञ, सफाई निरीक्षक और प्रयोगशाला तकनीशियन सहित) के बीच फर्क पहचाना और सराहा जाना चाहिए.

कई देशों ने खासकर जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई चूक की थाह लेने के लिए महामारी को उठाए गए अपने कदमों की समीक्षा की. मकसद यह भी था कि ज्ञात और नए उभरते रोगाणुओं का जल्द पता लगाया जाए, डायग्नोसिस के लिए उम्दा प्रयोगशालाओं का बुनियादी ढांचा बने, प्रशिक्षित चिकित्सा-अर्धचिकित्सा बल हों, रियलटाइम डेटा संग्रह और विश्लेषण का इंतजाम हो, जोखिम संचार रणनीति और जरूरी कार्रवाई के बारे में प्रशासन को सलाह दे सकने वाले अधिकार-संपन्न स्थानीय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां हों. हमने एक विरोधीभास देखा: हाइ टेक्नोलॉजी पर कम और मौजूदा समुदाय आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य तरीकों पर ज्यादा निर्भर कुछ कम और मध्यम आय वाले देशों (जैसे रवांडा, सेनेगल, थाइलैंड और वियतनाम) ने बेहतर प्रदर्शन किया. कार्यबल के नियमित प्रशिक्षण और निगरानी और उनकी सहायता के लिए डिजिटल औजारों के इस्तेमाल सहित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में निवेश अहम होने जा रहा है. राजकाज और दूरदृष्टि को परिभाषित करने वाले राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट के साथ डिजिटल बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के कारण भारत बेहतर स्थिति में था क्योंकि वह कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, वैक्सिनेशन और टेलीमेडिसिन सेवाओं के लिए मोबाइल ऐप्लिकेशन तेजी से ला पाया. हमारे शहरों में शानदार विशेषज्ञों की मौजूदगी का फायदा उठाने के लिए इन डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार करना चाहिए, जिससे शहरों के ये विशेषज्ञ दूरदराज की ग्रामीण आबादियों की भी सेवा कर सकें.

अब हम सार्स-कोव-2 वायरस और उसके फैलने के बारे में कहीं ज्यादा जानते हैं, इसलिए हमारे आगे के कदम रणनीतिक होने चाहिए. यात्रा पर पाबंदियों (और लॉकडाउन) का बहुत कम असर होता है. इन्हें केवल अस्थायी उपाय के तौर पर ही लागू करना चाहिए. तमाम श्वसन रोगाणुओं के लिए हवा के आवागमन पर ध्यान जरूरी है. ऐसी तमाम जगहों पर जहां लोग बंद चारदीवारी में समय बिताते हैं, मसलन, शैक्षणिक संस्थाएं, कार्यस्थल, मॉल और रेस्तरां, या तो हवा की बेहतर प्राकृतिक आवाजाही हो या उन्नत एचवीएसी प्रणालियां लगाई जाएं. टेक्नोलॉजी के ज्यादा स्मार्ट इस्तेमाल की जरूरत है.

कई सुरक्षित और असरदार टीकों के विकास की बदौलत दुनिया महामारी के भयंकर दौर से निकल पाई. पहले यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि नए वायरस के उभरने के महज एक साल के भीतर टीके न केवल विकसित और इस्तेमाल किए जांएगे, बल्कि दो साल के भीतर दुनिया भर में 14 अरब खुराक लगा भी दी जाएंगी. आरऐंडडी और मैन्युफैक्चरिंग दोनों का पैमाना तमाम उम्मीदों से आगे निकल गया. सीईपीआइ, गावी और यूनिसेफ के साथ डब्ल्यूएचओ की तरफ से जारी कोवैक्स ने गैरबराबरी से निबटने में अहम भूमिका निभाई, जिसकी करीब 2 अरब खुराकें ज्यादातर निम्न, निम्नतर और मध्यम आय वाले देशों में 2022 के आखिर तक लगाई जा चुकी थीं. भारत के वैक्सीन उद्योग ने विशाल भारतीय आबादी को टीके देने के अलावा दुनिया के लिए मैन्युफैक्चर करने में प्रमुख भूमिका अदा की. भविष्य के लिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि वैश्विक आपातस्थिति के दौरान टीकों और दवाइयों सरीखे जीवनरक्षक उत्पादों की बौद्धिक संपदा की साज-संभाल कैसे की जाए. टेक्नोलॉजी का तेजी से ट्रांसफर और अलग-अलग जगहों पर (अफ्रीकी महाद्वीप के देशों सहित) मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं का अच्छी गुणवत्ता वाला नेटवर्क पूरी दुनिया की मांग तेजी से पूरी करने का एकमात्र तरीका है. टीके सबको समान रूप से सुलभ होते तो अनुमान है कि 2021 में दस लाख से ज्यादा जानें बचाई जा सकती थीं. डब्ल्यूएचओ के सदस्य देशों के बीच जिस महामारी समझौते पर वार्ता चल रही है, वह इस मुद्दे से निबटने का जीवनकाल में एक बार आने वाला मौका है, ताकि वही गलतियां दोहराई न जाएं. महामारी ने हमें कई सबक सिखाए और हमें चाहिए कि उन्हें सीखकर अगली बार के लिए बेहतर तैयार हों. एक और महामारी को लेकर सवाल यह नहीं कि वह आएगी या नहीं, बल्कि यह है कि कब आएगी. दुनिया कई चुनौतियों से घिरी है, जिनमें स्वास्थ्य, खाद्य प्रणालियों और जैवविविधता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, वायु प्रदूषण और जल संकट सरीखे उससे जुड़े पर्यावरण के जोखिम और साथ ही एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध का बढ़ता खतरा शामिल है. हमें स्वास्थ्य का समग्र नजरिया अपनाने की जरूरत है, जिसमें 'एक स्वास्थ्य' आयाम के साथ रोग की रोकथाम तथा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर ध्यान शामिल हो. अगर दुनिया का वैज्ञानिक और जनस्वास्थ्य समुदाय साथ मिलकर काम करे और ज्ञान, डेटा और समाधान साझा करने को राजी हो, तो इन चुनौतियों पर फतह हासिल की जा सकती है और हम सतत विकास लक्ष्य पूरे करने की राह पर लौट सकते हैं. एक ध्येय हमें भूलना नहीं चाहिए और वह है: किसी को पीछे मत छोड़ो. ■

> महामारी ने यह बताया कि **यात्राओं पर पाबंदी लगाने का खास लाभ नहीं है.** जमावड़े वाली जगहों पर हवा की आवाजाही का बेहतर इंतजाम बेहद अहम है

के. श्रीनाथ रेड्डी
पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआइ) में मानद प्रोफेसर

यह वक्त है एक कुशल स्वास्थ्य तंत्र बनाने का

सार्स-कोविड2 वायरस का खतरा हालांकि अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है लेकिन भारत की पूरी स्वास्थ्य प्रणाली को किसी एक बीमारी के लिए इतना ज्यादा समर्पित कर देना भी ठीक नहीं

MAGAZINE KING

चीन ने हाल ही में अपने यहां पाबंदियां हटाईं जिससे वहां बड़े पैमाने पर कोविड-19 का संक्रमण फैल गया. अमेरिका और कनाडा अब भी आस-पास ही मंडरा रहे कोविड, दोबारा आ धमके इन्फ्लुएंजा और जल्दी आ गए रेस्पिरेटरी सिनसिशियल वायरस (आरएसवी) की 'तिहरी महामारी' एक साथ झेल रहे हैं. भारत कुछ महीनों से चैन की सांस ले रहा है, जहां हाल के दिनों में नए मामलों और मौतों की संख्या जनवरी 2020 में वायरस के आगमन के बाद से सबसे कम दर्ज की गई. सार्स-कोव-2 अब कम खतरनाक है. भारत में वायरस की पिछली लहरों और बड़ी तादाद में टीके लगने से भी गंभीर बीमारी के खिलाफ अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता की रक्षात्मक परत बन गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आ रहे वायरस के नए रूपों के संभावित खतरे से सतर्क रहने की अपील की है, खासकर चीन का मौजूदा अनुभव खासी परेशानी पैदा कर रहा है.

हमें 2023 में जिन संक्रमणों से निबटना है, उनकी फेहरिस्त से कोविड-19 अभी निश्चित रूप से गया नहीं है. वायरस अब भी आसपास ही है, पर सब कुछ तहस-नहस करके विदा हो जाने वाले हमलावर की तरह नहीं, बल्कि ज्यादातर यहां रहने आए नए किरायेदार की तरह. ओमिक्रॉन के नए रूपों की वजह से समय-समय पर बढ़ते संक्रमणों के कुछ झोंके आएंगे, पर डेल्टा-सरीखे मौतों के आंकड़े नहीं होंगे, जब तक कि कोई बेहद प्रचंड और संक्रामक नया रूप अचानक न आ धमके. हमें अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चौकस रखना और वायरस के खतरनाक रूप से निबटने के लिए तैयार रहना चाहिए, पर उसे एक ही बीमारी के लिए बहुत ज्यादा समर्पित नहीं करना चाहिए. हमारा स्वास्थ्य का एजेंडा कोविड के अलावा भी कई मोर्चों पर ध्यान देने और असरदार कार्रवाई करने की मांग करता है.

इलस्ट्रेशनः तन्मय चक्रवर्ती

भारत में तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) का असर बहुत ज्यादा है, जहां दुनिया के एक-चौथाई मामले होते हैं. मल्टी-ड्रग-रेसिस्टेंट (एमडीआर) और एक्सट्रीमली ड्रग-रेसिस्टेंट (एक्सडीआर) के मामले गंभीर चुनौती पेश करते हैं. कोविड-19 के सालों के दौरान टीबी के मामलों की शिनाख्त पर असर पड़ा क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था सार्स-कोव-2 वायरस के संक्रमण को थामने, कोविड-19 के मामलों का पता लगाने के लिए गहन निगरानी, घर या अस्पताल में उनके इलाज और देश भर में टीके लगाने के कई चरणों में बहुत व्यस्त थी. इसका मतलब था कि टीबी से ग्रस्त लेकिन पहचाने नहीं गए लोग दूसरों को संक्रमित कर रहे थे. इलाज का सिलसिला भी टूटा क्योंकि मरीज स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच नहीं सके.

इस झटके से भारत के ऊपर बहुत दबाव आ गया, जिसने 2030 के वैश्विक लक्ष्य से पहले 2025 तक टीबी को खत्म करने के इरादे का ऐलान कर दिया था. अब हमें समुदायों को बड़े पैमाने पर जोड़कर और सार्वजनिक क्षेत्र की अगुआई में चल रहे राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए ऊर्जावान निजी क्षेत्र की मदद लेकर मामलों की शिनाख्त और इलाज के लिए कमर कसनी होगी. टीबी कार्यक्रम को एचआइवी-एड्स नियंत्रण के कामयाब कार्यक्रम से सबक सीखने होंगे और उसके साथ भागीदार बनना होगा क्योंकि टीबी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होने की वही साझा परेशानी है जो एड्स में होती है. इसी तरह टीबी नियंत्रण की कोशिशों को डायबिटीज और तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि यह उन्हीं लोगों को ज्यादा होती है जिन्हें डायबिटीज है या जो धूम्रपान करते हैं.

संक्रामक रोगों में हम मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया सरीखे वेक्टर-जनित रोगों का लगातार खतरा झेल रहे हैं. यह खतरा बढ़ेगा क्योंकि जलवायु परिवर्तन से देश गरम हो रहा है और मच्छर ज्यादा दूर तक और ज्यादा तेजी से फैल पा रहे हैं. कोविड-19 के अलावा नई जूनोटिक या पशुजन्य बीमारियां खतरा पैदा करेंगी क्योंकि पारिस्थितिकीय अवरोध टूटने से वायरस तमाम प्रजातियों में फैल पाएंगे. हमें समूचे वन्यजीवों, नियंत्रित वातावरण में पली-बढ़ी और मुक्त विचरण करती पशु आबादियों और मानव बस्तियों की 'एक स्वास्थ्य' निगरानी के लिए मजबूत ट्रैकिंग व्यवस्था बनाने की जरूरत है. साथ ही हमें संभावित महामारी में बदल सकने वाले किसी भी प्रकोप से तत्काल, असरदार और जोरदार तरीके से निबटने के लिए अपनी स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवस्था की तैयारी का स्तर बढ़ाना होगा.

जच्चा, बच्चा और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की राष्ट्रीय सकल मृत्यु दर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की तरफ से तय 2030 के लक्ष्य हासिल करने के रास्ते पर हैं, वहीं हमें अच्छा और खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों के बीच इन दरों में छह से सात गुना का फर्क पाटने का लक्ष्य बढ़-चढ़कर साधना चाहिए. हमें बाल पोषण में सुधार लाने और महिलाओं तथा बच्चों में एनीमिया का स्तर कम करने के लिए भी पुरजोर कोशिश करनी चाहिए. सीधे तौर पर ज्यादा वजन और मोटापे के अलावा मोटे दिखाई नहीं देने वाले लोगों में भी कम जाहिर 'शारीरिक मोटेपन' और 'आंत के मोटापे' की दरें बढ़ रही हैं. ये तमाम आयु समूह के लोगों में साफ दिखाई देती हैं और कार्डियो-मेटाबोलिक रोगों का खासा जोखिम पैदा करती हैं. ये व्यापक पोषण एजेंडे की मांग करती हैं जो हर प्रकार के कुपोषण से निबटे.

फिलहाल मौत की अव्वल वजह गैर-संक्रामक रोग (एनसीडी) हैं. इस झुंड में कार्डियोवस्कुलर और सेरिब्रोवैस्कुलर रोग (मुख्यत: दिल का दौरा और दिमागी लकवा), कैंसर, डायबिटीज, फेफड़े, लीवर और किडनी के गंभीर रोग और साथ ही आंख, कान, मुंह, हड्डियों और जोड़ों की बीमारियां शामिल हैं. इनमें से कई जीवन के बेहतरीन उम्र अवधि वाले मध्यकाल में मौत या विकलांगता का कारण बनती हैं. मानसिक स्वास्थ्य विकार इनसे प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के लिए तकलीफ का बड़ा कारण हैं. एनसीडी और मानसिक स्वास्थ्य की परेशानियां भारत में बढ़ रही हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था को उन्हें गंभीरता से लेना होगा. कोविड-19 के प्रकोप के दौरान भी इसके साथ मौजूद गैर-संक्रामक रोगों ने तीव्र संक्रमण, अस्पताल में भर्ती होने की नौबत और मौत का जोखिम साफ तौर पर बढ़ा दिया. एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देनी होगी ताकि जिंदगियों को महफूज रखने के अलावा गंभीर विकलांगता को रोकने के साथ उत्पादकता को बचाया जा सके.

> एनसीडी (गैर-संक्रामक रोगों) से बचाव और नियंत्रण के साथ हमें **मानसिक रोगों से सुरक्षा को अहम वरीयता देनी होगी.** जिंदगियां बचाने के अलावा लोगों को विकलांगता से सुरक्षित रखने के लिए यह सब बहुत जरूरी है

इस एजेंडे को तभी पूरा किया जा सकता है जब हम स्वास्थ्य व्यवस्था को देखभाल के हरेक स्तर पर मजबूत करने का बीड़ा उठाएं. इसके अच्छे प्रदर्शन के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सबसे अहम है. ग्रामीण और शहरी दोनों प्राथमिक देखभाल को मजबूत किए बिना हम संक्रामक रोगों पर दक्षता से काबू नहीं पा सकते या महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए ऊर्जावान प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते. न ही हम एनसीडी या मानसिक स्वास्थ्य विकारों की दक्षता से रोकथाम, पहचान और इलाज ही कर सकते हैं. जच्चा-बच्चा का स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्राथमिक देखभाल की सेवाओं पर निर्भर करता है.

प्राथमिक स्तर पर समग्र देखभाल को पक्की करते हुए इसे दो दिशाओं में द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से जोड़ना भी जरूरी है. आयुष्मान भारत कार्यक्रम कुशल स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करता है. इसके चार घटकों—व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन और डिजिटल हेल्थ मिशन—को आपस में जोड़ना चाहिए. मल्टीलेयर्ड, मल्टीस्किल्ड स्वास्थ्य कार्यबल और जनस्वास्थ्य विशेषज्ञता विकसित करने में निवेश हो. केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल भी सामंजस्यपूर्ण हो और यह भारत के लोगों को सभी आयामों में स्वास्थ्य मुहैया करने की साझा प्रतिबद्धता से प्रेरित होना चाहिए. यह संकल्प केंद्र और राज्य के बजटों में बढ़े हुए बजटीय आवंटन में झलकना चाहिए. क्या यह 2023 में शुरू हो सकता है? ■

खास रपट

कश्मीरी लड़कियां

कहां है हमारा रैनावारी

प्रदीपिका सारस्वत

हाल ही में दिल्ली के हैबिटाट सेंटर में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई. नाम था घर का पता. मधूलिका जलाली की यह फिल्म श्रीनगर के रैनावारी में अपने उस घर के खो जाने की घुटन से बाहर आने की कोशिश थी जिसे वे याद नहीं कर पा रही थीं. इसी तरह पिछले साल गुलमर्ग साहित्य महोत्सव में अनुष्का धर ने अपनी किताब टेक मी होम पर बात की. कश्मीर घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों का 1989 में शुरू हुआ भीषण पलायन आज भी जारी है. तब से अब तक की तमाम पीढ़ियां आज भी किसी तरह अपने उस घर से राब्ता बनाए रखने की जद्दोजहद में हैं जो शायद हमेशा के लिए उनसे छूट गया. इनमें अनुष्का और नियति की पीढ़ियां हैं जिन्होंने अपना घर कभी देखा ही नहीं. मधूलिका सरीखे लोग हैं जिनका जेहन घर छोड़ते वक्त इतना कच्चा था कि एक दर या दीवार तक न याद रख सका. और फिर हिना जैसे लोग हैं जिन्हें घाटी में बीते बचपन की याद आज भी इस तरह जकड़े हुए है कि किसी और ठिकाने को घर नहीं बनने देती.

मधूलिका जलाली (38 वर्ष)

फिल्मकार हैं, फिलहाल मुंबई में रहती हैं

कश्मीर का पता : रैनावारी, श्रीनगर

मैंने कश्मीर को घर की तरह नहीं देखा था, जब तक 2014 में पहली बार मैं हफ्ते भर के लिए परिवार के साथ वहां नहीं गई. वहां देखा कि सब वह भाषा बोल रहे थे जो मैंने सिर्फ घर में सुनी थी. अपने परिवार को ड्राइवर, सब्जी वाले या सड़क चलते आदमी से बेतकल्लुफी से कश्मीरी में बात करते देख मैं हैरान थी. मुझे लगा मैं यहां की हूं, मेरा बचपन यहीं बीतना था, न कि तमाम शहरों में बदले किराए के मकानों में.

मैंने पिता से कहा कि मुझे अपना वह घर देखना है जहां मैं पैदा हुई और छह साल गुजारे. उन्होंने साफ इनकार कर दिया. अपना घर देखने की मेरी बेचैनी और बढ़ गई. 2014 में जब मैं कश्मीर से लौटी तब जैसे लगा मेरे पांवों के नीचे से जमीन खींच ली गई थी. बस इतना पता था कि मुझे अपना घर, अपनी जड़ों को तलाशना था और कोई ऐसा शख्स मेरी मदद कर सकता था जिसने वह घर देखा हो. मैं बड़ी बहन के पास गई. जब वह कश्मीर में बीते बचपन की बात करती, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती. सब कुछ एक दम ताजा लगता, यहां तक कि उसका ट्रॉमा भी. लेकिन कश्मीर की मेरी यादें उधार की थीं. निर्वासन आपके साथ यही करता है. आपके पास अपना कुछ भी नहीं बचता. न यादें, न अपनी चीजें, आप बस दूसरों की आपबीती के दर्शक बनकर रह जाते हैं.

जब हम दिल्ली रहने आए तो मेरी मां को हिंदी बोलने में बड़ी तकलीफ हुई. वह सब्जी वालों, पड़ोसियों से बात करने में हिचकती. अब मैं समझ पाती हूं कि कितना अकेला महसूस किया होगा उसने. मुझे अपने ही परिजनों और रिश्तेदारों का भरोसा जीतने में बहुत वक्त लगा क्योंकि मैं उनकी दर्दनाक यादों की उन गलियों में जाने की कोशिश कर रही थी जो उन्होंने खुद अपने आप से छुपा रखी थीं. लगभग हर बार मुझसे कहा गया—क्या जानना चाहती हो? और अब क्यों? बहुत देर हो चुकी है. शुरुआत में मैं बस चचेरे भाई-बहनों, पारिवारिक मित्रों, रिश्तेदारों के इंटरव्यू कर रही थी. मैं उनसे पूछती कि रैनावारी के मेरे घर के बारे में उन्हें क्या याद है? कुछ दरवाजे और घर के ब्यौरे बताते. कुछ उस घर से जुड़ी यादें साझा करने लगते. फिर मैंने पुरानी तस्वीरें मांगनी शुरू कीं. तस्वीर तो एक भी ठीकठाक न मिली, पर इस प्रक्रिया में समझ आया कि औरतों मसलन मां, चाचियों, मामियों की और बातें सुननी चाहिए. मर्द ज्यादातर राजनीति पर, नौकरियों की बात करते लेकिन औरतों पर निर्वासन का असर बहुत गहरा था. मेरी मां अब तक उन बर्तनों की बात करती है जो रैनावारी के घर में छूट गए, वो कपड़े जो उसने निकलने से पहले सुखाए थे. इन छोटी-छोटी चीजों ने मेरा दिल तोड़ दिया. डॉक्यूमेंट्री में मैंने जान-बूझकर औरतों से ज्यादा बात की. फिल्म बनाने की यह यात्रा मुझे कहीं न कहीं मेरे घर के करीब भी लाई और घर को पाने की बेचैनी को भी और बढ़ाया. मुझे लगता है कि मेरी तलाश तो अब शुरू हुई है. ■

?

अनुष्का धर (19 वर्ष)

फिलहाल न्यू यॉर्क में पढ़ रही हैं
कश्मीर का पता : मलयार, श्रीनगर

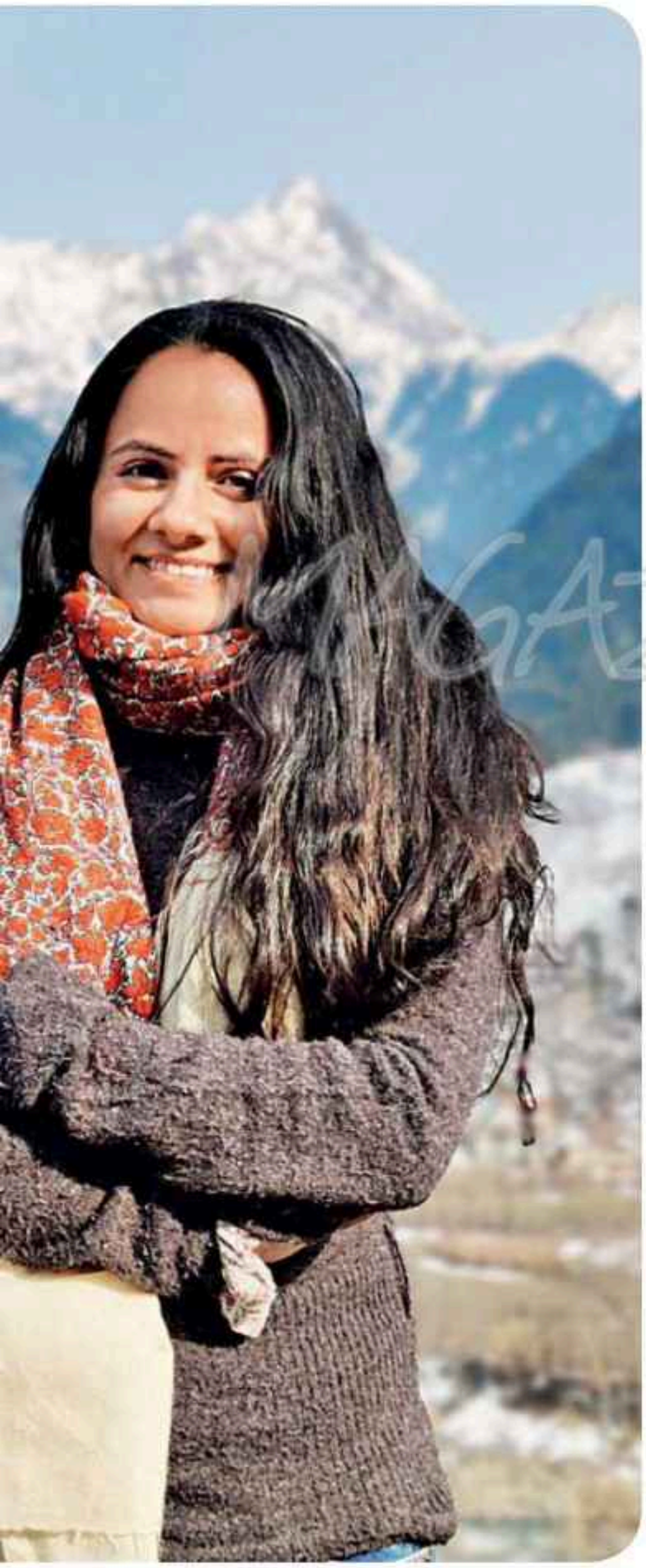

मैं कश्मीर से दूर बड़ी हुई. एक कश्मीरी परिवार में बड़े होते वक्त एक चीज बिल्कुल साफ थी कि हम कश्मीरी खाना खाते, त्योहार मनाते, कश्मीरी जुबान बोलते पर कश्मीर के बारे में बात नहीं करते. जब मैं और छोटी थी तो छुट्टियों के बाद मेरे दोस्त अपने अनुभव साझा करते कि वे गांव गए, खेत-खलिहान घूमे, वहां लोगों से मिले. मेरी बारी आती, तो मैं चुप. मेरे पास बताने को कुछ होता ही न था. थोड़ी बड़ी हुई तो चुप रहने की मजबूरी मुझे परेशान करने लगी. मुझे समझ आने लगा कि मेरा घर कहीं ऐसी जगह था जिसके बारे में मैं जानती ही नहीं.

मेरा परिवार इस बारे में बात नहीं करना चाहता था. मैं सवाल करती तो वे परेशान हो जाते. इस बारे में बात करना उनके लिए बहुत दुखद था. धीरे-धीरे मुझे घर के बारे में नई बातें पता चलने लगीं, मेरे दिल में परिवार के लिए प्यार और इज्जत और बढ़ गई. कितना कुछ खोने और सहने के बाद वे यहां थे.

अपने खोए घर को जानने की बेचैनी ने मुझे ऐसी चीजें करने पर मजबूर किया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी. यह बेचैनी न होती तो मैं महज 16 की उम्र में यह किताब न लिख पाती. मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी 14 साल की कच्ची उम्र में कश्मीर जैसे उदास करने वाले, जटिल विषय का सामना करना. ऐसी उम्र में आप ज्यादा कुछ जानते-समझते नहीं. घर की अनुपस्थिति से जुड़ी हरेक आपबीती जो मैंने सुनी, हर तस्वीर जो दिखाई गई उसने मुझे अंधेरे अतीत में ले जाकर छोड़ दिया. हरेक आवाज में कितना ट्रॉमा था, मुझे अंदाजा ही न था. शुरुआत में जब मैं सुनती कि मेरे परिवार पर यह सब बीता, तो मैं भावुक और बेचैन हो जाती. एक लेखक की अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मुझे उम्र से ज्यादा बड़ा होना पड़ा. इसलिए कितनी भी घुटन, दर्द या बेचैनी से मैं गुजरी, पर मैं सब कहानियां इकट्ठा करती गई.

इस किताब के पीछे की अनकही कहानी बेहद निजी है. यह उस राजनीति से कहीं दूर की बात है जो हम कश्मीर के मुद्दे के इर्द-गिर्द पाते हैं. यह एक किशोर लड़की की कहानी है जो जानना चाहती है कि वह कहां से आई है. इसमें एक मासूमियत है, एक मोहब्बत है, और यह किताब भरोसा देती है कि पलायन के 30 से ज्यादा साल बीत जाने पर भी कश्मीरी पंडितों की पीढ़ियां अपने घर को भूली नहीं हैं, वे इसे नए सिरे से खोज रही हैं.

बहुत-से लोग नहीं समझ पाते कि इस पलायन में कश्मीरी पंडितों ने सिर्फ घर नहीं खोया, जीने का अपना तरीका ही उनसे छूट गया. उन्हें सब कुछ शून्य से शुरू करना पड़ा. कुछ पंडित दुनिया भर में नाम और पैसा कमा रहे हैं, पर ऐसे कितने ही पंडित हैं जो इंटरनली माइग्रेटेड पर्संस कैंप या आइडीपी कैंप में रहे. कल जब मैं इस लायक होऊंगी तो किसी जरूरतमंद पंडित बच्चे की शिक्षा का खर्च जरूर उठाऊंगी. ■

हिना कौल (42 वर्ष)

फिलहाल फरीदाबाद और यूट्यूब पर कायनात में कश्मीर का पता : सफा कदल, श्रीनगर

राजवंत रावत

कश्मीर से निकलते वक्त मैं दस साल की थी. मुझे याद है, पुरखों के घर से निकलते वक्त किस नजर से मैंने उसे देखा था. मुझे पता न था कि अब मैं कहां जाऊंगी, भविष्य क्या होगा, पहचान क्या होगी. कश्मीर से निकलते वक्त मैं मां-बाप के साथ नहीं थी. पता भी न था कि दोबारा मां-बाप और दादी-दादा से कब मिल सकूंगी. मेरे सपने उसी घर में छूट गए.

घर की याद में मैंने कविताएं लिखनी शुरू कीं, खोए घर के बारे में कहानियां लिखीं. बाद में कायनात नाम से यूट्यूब चैनल बनाया. बचपन में मैं बंजारों की तरह एक जगह से दूसरी जगह भटकी. टेंट और कैंप में घर की एक सुरक्षा, एक अपनापन, एक जगह जो आपको चाहिए होती है, वह मुझसे छिन गई. जब मैं फिर परिवार के साथ रहने लगी तो दादा-दादी को कश्मीर के लिए तड़पते देखा. दादाजी ने याद्दाश्त खो दी. वे आखिरी सांसें कश्मीर में लेना चाहते थे, पर बदकिस्मती देखिए कि उन्हें परदेस में जलाया गया. एक किशोरी के लिए वह भावनात्मक ट्रॉमा झेलना आसान न था. कश्मीर से रातो-रात निकलना और नई जगहों पर फिर जीना सीखने की कोशिश. हम सब जैसे बिना जड़ों के लोगों की तरह जीते हैं. हमारा कोई स्थाई पता नहीं है. धीरे-धीरे हमारे रीति-रिवाज, हमारी संस्कृति भी खो रही है. बिना बर्फ के, बिना वितस्ता के ऐसे कितने रिवाज हैं जो पीछे छूट गए.

2018 में पति के साथ कश्मीर जाने पर हम पुरखों के घर भी गए, कुछ मंदिर भी देखे, जो बुरे हाल में थे. लेकिन साधु बरबर शाह के मंदिर और सफा कदल में घर के पास के राम मंदिर में जाना बेहद रोमांचकारी था. वहां की यादें मेरे जहन में वैसी की वैसी कैद थीं जैसे कल ही मैं वहां दादी के साथ गई थी.

कायनात का सफर शुरू करने से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती थी डर. फिर से कश्मीर और खासकर डाउनटाउन के खंडित होते मंदिरों में जाना. हमने खतरा उठाया. मुश्किल से मुश्किल हालत में भी कभी नहीं सोचा कि काश मैं पंडित न होती और मुझे इस त्रासदी से न गुजरना पड़ता. मैं आज अपने परिवार के साथ जहां हूं, खुश हूं, मेरे पास कोई कमी नहीं, पर मेरी आत्मा आज भी मेरे खोए हुए घर में बसती है. वह कमी पूरी ही नहीं होती.

मेरी कविताएं पंडितों के जला दिए गए, छीन लिए गए घरों और मंदिरों के बारे में हैं, हमारी खोई हुई पहचान के बारे में हैं. मेरी कविताएं यह बताने की कोशिश करती हैं कि हम किस तरह अपने अतीत और वर्तमान के बीच बंटे हुए जी रहे हैं, उन हालात की बात करती हैं जिनकी वजह से हमें अपना सब कुछ छोड़कर बंजारों की जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा. उन जगहों की कहानियां जो कभी जिंदगी से गुलजार थीं, आज उजाड़ और बंजर हैं.

मैं आशावादी हूं और भविष्य में कश्मीरी पंडित समुदाय को फिर कश्मीर में देखती हूं. मैं देखती हूं कि हमें न्याय मिलेगा. बचपन में हमने जो खोया है, हम पाएंगे, हमारा बचपन, हमारे मन की शांति, हमारी खुशी... ■

कश्मीरी लड़कियां

बचपन में बहुत जल्दी मुझे यह समझ आ गया कि हम जहां थे, जहां मैं पैदा हुई, जहां मैं बड़ी हो रही थी वो 'घर' नहीं था. पिछले कुछ समय में जब भी मैंने कश्मीरी पंडित दोस्तों से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो ज्यादातर ने मुझे बताया कि उनके परिवार ने कश्मीर छूटने की त्रासदी को उनसे दूर रखा पर मेरे घर में यह रोज की बातचीत में शामिल था. शायद इसलिए क्योंकि मैं जिस मुहल्ले में पली बढ़ी वहां कई निर्वासित पंडित परिवार रहते थे. लोगों के लिए माइग्रेशन यानी विस्थापन का अर्थ पंछियों के एक मौसम से दूसरे की तलाश में दूर देश जाने या गांव से शहर जाने तक सीमित था. पर हम कश्मीरी पंडितों के लिए यह शब्द हमारी पहचान से जुड़ गया. जब मुझे पहली बार यह समझ आया कि माइग्रेशन कश्मीरी का नहीं अंग्रेजी का शब्द था तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ. मेरे माता-पिता की शादी 1990 में घाटी छोड़ने के बाद हुई और मैं हिमाचल में पैदा हुई जहां मेरे पिता नौकरी करते थे. मैं दादी-दादा से निर्वासन की कहानियां सुनते हुए बड़ी हुई. परीकथाएं खत्म हो गईं तो उन्होंने मुझे कश्मीर में बीती अपनी जिंदगी की कहानियां सुनानी शुरू कीं.

मेरा पूरा अस्तित्व निर्वासन की त्रासदी में डूबा रहा है. पहले स्कूल और फिर कॉलेज में मैं हमेशा कश्मीर की ही बात करती थी, इस कदर कि मुझे टोक दिया जाता था कि कुछ और बात करो. मैंने निर्वासन का साहित्य पढ़ा. झुंपा लाहिरी का साहित्य, महमूद दरवेश की कविता, एडवर्ड सईद का निर्वासन पर काम. मैं कहां पैदा हुई, कहां स्कूल गई, कैसी शिक्षा मुझे मिली, यह सब निर्वासन ने तय किया, मेरा कवि, लेखक और अनुवादक होना भी. मैंने पत्रकारिता पढ़ी ताकि कश्मीरियों की कहानियां दुनिया तक पहुंचा सकूं. फिर मैं सिनेमा स्टडीज पढ़ने जेएनयू गई. यहां मेरी यात्रा तीन शब्दों के साथ शुरू हुई—ट्रॉमा, एग्जाइल (निर्वासन), सिनेमा. मेरी कश्मीरी पहचान और निर्वासन का अनुभव मेरे सारे रिश्तों पर असर डालता रहा. उनसे दोस्ती मुमकिन न हो सकी जो हमारे मुद्दों को नजरअंदाज करते या उन्हें गैर-जरूरी समझते. इस त्रासदी का सामना करने का मेरे पास एक ही तरीका था, इसे लिखना. मैं तस्वीरें, किस्से, गीत, बातचीत रिकॉर्ड करने लगी, अपने परिवार को अपने फोन कैमरा पर हर वक्त रिकॉर्ड करती रहती. लगता कि निर्वासन का ये डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है.

क्लासरूम में कश्मीर पर बात होते समय जब देखती कि पंडितों के निर्वासन पर बात करने की जरूरत ही नहीं समझी जाती, तो मैं अपना पक्ष जरूर रखती. लोग हमारे दर्द से इस कदर अनजान थे कि मुझे यह तक सुनने को मिला कि तुम वापस क्यों नहीं चली जातीं. उस नैरेटिव में मुझे यह समझ आया कि खुद को कश्मीरियों का दोस्त बताने वाले, सभी कश्मीरियों के दोस्त नहीं. अन्याय पर लोगों का गुस्सा और न्याय की अवधारणा एकतरफा थी. इसलिए मैंने कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों की आवाजों को समेटने वाले सिनेमा और संगीत पर काम शुरू किया. सबसे बड़ी चुनौती थी इस सवाल का जवाब: जब मैं अपने समुदाय के दर्द और ट्रॉमा से ही पूरी तरह उबर नहीं पाई हूं तो पूरे कश्मीर के दर्द को कैसे समझूं. मेरे लिए बड़ी बात थी जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने 2020 में कश्मीरी संगीतकारों पर मेरे रिसर्च पेपर को बेस्ट पेपर अवॉर्ड दिया. मेरे मां-बाप को मेरे काम पर भरोसा होने लगा, जिस तरह मैं उनके दर्द को जुबान दे पा रही थी, वे हैरान थे. कहते हैं न कि जो किताब आप पढ़ना चाहते हैं अगर वह लिखी नहीं गई है, तो आप उसे लिखें. अब तक कश्मीर से जुड़े मेरे अनुभव और व्यथा को कहने वाली किताब मुझे नहीं मिली है, तो मुझे अपनी कहानी खुद ही कहनी होगी. शुरू में मेरे भीतर कश्मीर को लेकर बहुत गुस्सा था लेकिन साहित्य और लेखन ने इन भावनाओं को समझने में बहुत मदद की. मैंने इस गुस्से को अपने काम के जरिए बाहर लाने की कोशिश की है. मैं अपने घर और अपनी जड़ों को खोना अब तक स्वीकार नहीं कर पाई हूं, आगे कर सकूंगी या नहीं, कह नहीं सकती. ■

राजवंत रावत

नियति भट्ट (29 वर्ष)

लेखक, अनुवादक, फिलहाल दिल्ली में
कश्मीर का पता : अशमुकाम, अनंतनाग

क्या दिन थे और क्या दिन आ गए!

गीतकार-शायर **जावेद अख्तर** अपने परिवार के लोगों और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में

● पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में

नेहरू जी के बगैर आप मॉडर्न इंडिया की कल्पना ही नहीं कर सकते. वे ओल्ड और मॉडर्न इंडिया के बीच का सेतु हैं. उन्होंने डेमोक्रेसी की जड़ें इस धरती में उतार दीं. उनका ऑटोग्राफ हासिल करने का एक किस्सा है. वे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की नींव रखने अलीगढ़ आए थे. मैं और मेरा दोस्त वहां एंथम गाने वाले थे. वे स्पीच देकर गाड़ी में बैठे. मेरी एक पड़ोसन ने एक कागज पर नेहरू की तस्वीर और तिरंगा बनाकर दिया था. भागते हुए उसे मैंने नेहरू जी को दिया. उन्होंने सोचा, मैंने बनाया होगा, तो पेन निकालकर सिग्नेचर कर दिए. सोचिए, क्या दिन थे और क्या दिन आ गए!

—सौरभ द्विवेदी

● पिता जांनिसार अख्तर के बारे में

मेरे पिता जांनिसार अख्तर ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि बेटा, मुश्किल जबान में लिखना बहुत आसान है पर आसान जबान में लिखना बहुत मुश्किल. आसान जबान में आप तभी लिख सकते हैं जब आपका ख्याल क्लियर हो.

● बेटी जोया अख्तर और बेटे फरहान अख्तर के बारे में

जोया ने अपनी फिल्म *दिल धड़कने दो* में सारे डायलॉग किसी और से लेकिन एक कुत्ते के डायलॉग मुझसे लिखवाए. उसे यह ख्याल क्यों आया होगा कि कुत्ते के डायलॉग मेरे बाप से बेहतर कोई नहीं लिख सकता? मैं इस डर से नहीं पूछता कि कहीं बता दे तो? ऐसे ही फरहान की फिल्म *रॉक ऑन* के लिए *मेरी लॉन्ड्री का इक बिल* जैसी वोकैबुलरी का गाना लिखा था. उस साल मुझे सारे अवार्ड *जोधा-अकबर* के लिए मिले. *रॉक ऑन* के लिए किसी ने नहीं दिया.

● बीवी शबाना आजमी और तलाकशुदा बीवी हनी ईरानी के बारे में

शबाना हर रोल में परफेक्शनिस्ट है. बेटी है तो ऐसी कि आपने देखी न होगी. दोस्त ऐसी कि उत्तरी ध्रुव पर भी हो तो दोस्तों को बर्थडे विश कर देगी. वो ऐसी दोस्त है जिस पर मैं डिपेंड कर सकता हूं. हनी और मैं बेहतरीन दोस्त हैं. उसने मेरी किताब में एक अच्छी बात कही है कि जो लोग अच्छे दोस्त होते हैं उन्हें कभी शादी नहीं करनी चाहिए.

● छोटे भाई सलमान अख्तर के बारे में

वो एक ब्रिलिएंट आदमी है. उसके कई शेर ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि काश! ये मैंने लिखा होता. जैसेः 'जो छुपाने की थी वो बात बता दी मुझको/ जिंदगी तूने बहुत सख्त सजा दी मुझको'. वो बोलता कितना अच्छा है. उसका मेजर स्ट्रक्चर उसके दिमाग में क्लियर होता है. सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है.